▪ वैशाख कृष्णा - 3 ▪ संवत 2082 ▪ वर्ष - 20 ▪ अंक - 257 ▪ पृष्ठ - 8 ▪ रु. 5/- बेंगलूरु » बुधवार » 16-04-2025 ▪ www.dakshinbharat.com ▪ Email : news@dakshinbharat.com

दक्षिण भारत राष्ट्रमत

ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತ ರಾಷ್ಟ್ರಮತ | ಹಿಂದಿ ದಿನ ಪತ್ರಿಕೆ | बेंगलूरु और चेन्नई से एक साथ प्रकाशित

4 ऊँटनी का दूध अमृत तुल्य, ऊँटपालकों को मिले इसका उचित मूल्य : बागड़े

6 अराजकता में डूबे बंगाल में नाउमीदी का अंधेरा

7 मुस्लिम तुष्टिकरण की राजनीति करते-करते कांग्रेस खुद पंचर हो गई : केशव

फर्स्ट टेक

हरियाणा भूमि सौदा मामले में ईडी ने रॉबर्ट वाड्रा के बयान दर्ज किए

नई दिल्ली/भाषा। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 2008 के हरियाणा भूमि सौदे से जुड़े धन शोधन मामले में मंगलवार को लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के बहनोई और कारोबारी रॉबर्ट वाड्रा के बयान दर्ज किए। आधिकारिक सूत्रों ने यह जानकारी दी। ईडी की पूछताछ को ''राजनीतिक प्रतिशोध की भावना से प्रेरित'' बताते हुए वाड्रा ने कहा कि पहले भी ईडी उनसे (धन शोधन के अन्य मामलों में) घंटों पूछताछ कर चुकी है, हजारों पन्ने साझा किए हैं, लेकिन फिर भी एजेंसी उनके खिलाफ मामले उठा रही है। मध्य दिल्ली के सुजान सिंह पार्क स्थित अपने आवास से वाड्रा (56) एपीजे अब्दुल कलाम रोड स्थित ईडी मुख्यालय तक करीब दो किलोमीटर पैदल चलकर पहुंचे। वह अपने वकील के साथ पूर्वाह्न 11 बजे ईडी कार्यालय में दाखिल हुए, जबकि उनकी सुरक्षा टीम बाहर ही रही।

यूक्रेन संकट के हल के लिए रूस, अमेरिका के बीच सहमति नहीं बनी

मॉस्को/भाषा। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कहा है कि अमेरिकी वार्ताकारों के साथ कई दौर की बातचीत के बाद भी दोनों पक्ष यूक्रेन संकट के समाधान के प्रमुख पहलुओं पर अब तक सहमति नहीं बना सके हैं। उनका यह बयान यूक्रेन में रूस के रॉकेट एवं ड्रोन हमले बढ़ने के बीच आया है। मंगलवार को कोमर्सेंट समाचार पत्र द्वारा प्रकाशित एक साक्षात्कार में, लावरोव ने कहा कि रूस, अमेरिका के साथ बातचीत जारी रखने के लिए तैयार है, क्योंकि वह अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनके पूर्ववर्ती जो बाइडन के रुख के बीच स्पष्ट अंतर देखता है। पिछले शुक्रवार को ट्रंप के करीबी सहयोगी स्टीव विटकॉफ रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ एक बैठक के लिए सेंट पीटर्सबर्ग गए थे।

ट्रंपने हार्वर्ड विश्वविद्यालय को दिए जाने वाले अनुदान पर रोक लगाई

बोस्टन/एपी। अमेरिका सरकार ने कहा है कि वह हार्वर्ड विश्वविद्यालय को दिए जाने वाले 2.2 अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक के अनुदान और अनुबंधों पर रोक लगा रही है। यह घटनाक्रम ऐसे समय हुआ जब विश्वविद्यालय ने सोमवार को कहा था कि वह परिसर में आंदोलन संबंधी सक्रियता को सीमित करने की ट्रंप प्रशासन की मांगों का अनुपालन नहीं करेगा। प्रशासन ने शुक्रवार को हार्वर्ड को लिखे पत्र में व्यापक सरकारी और नेतृत्व सुधारों का आह्वान किया, जिसके तहत हार्वर्ड को ''योग्यता-आधारित'' प्रवेश और नियुक्ति नीतियां स्थापित करनी होंगी, साथ ही विविधता संबंधी विचारों पर अध्ययन निकाय, संकाय और नेतृत्व का लेखा-जोखा भी रखना होगा।

16-04-2025 सूर्यास्त 6:32 बजे | सूर्योदय 17-04-2025 6:06 बजे

BSE	NSE
76,734.89	23,328.55
(+1,577.63)	(+500.00)

सोना	चांदी
9,312 रु.	93,401 रु.
(24 कैरेट) प्रति ग्राम	प्रति किलो

मिशन मंडेला

दक्षिण भारत राष्ट्रमत

दक्षिण भारत का लोकप्रिय हिन्दी दैनिक

epaper.dakshinbharat.com

कैलाश मण्डेला, मो. 9828233434

कोर्ट बनाम जनमत

हर विवाद का कोर्ट हल करे,
हो संभव बस यही सदा।
कुछ तथ्य सबूत गवाहों से,
यह परंपराएं रही सदा।
किंवदन्ती जनश्रुति के दम पर,
हमने कुछ बातें कही सदा।
जन्मे थे राम कहां पर कब,
जनमत का मत ही सही सदा।।

नेशनल हेराल्ड मामला:

सोनिया, राहुल गांधी के खिलाफ ईडी ने आरोप-पत्र दाखिल किया

■ **सोनिया, राहुल को एजेएल-वाईआई की 5,000 करोड़ रुपए की संपत्ति का मालिक पाया गया**

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

नई दिल्ली/भाषा। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 'नेशनल हेराल्ड' मामले में अपने आरोपपत्र में कहा है कि कांग्रेस नेताओं ने इसकी मूल कंपनी एजेएल की 2,000 करोड़ रुपये की संपत्ति 'हड़पने' के लिए 'आपराधिक साजिश' रची थी। जांच एजेंसी ने दावा किया कि इसके लिए उन्होंने 99 प्रतिशत शेयर महज 50 लाख रुपये में अपनी निजी कंपनी 'यंग इंडियन' को हस्तांतरित कर दिए, जिसमें सोनिया गांधी और राहुल गांधी बहुलांश शेयरधारक हैं।

विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने की अदालत के समक्ष धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की विभिन्न धाराओं के तहत दायर अभियोजन शिकायत में संघीय जांच एजेंसी ने कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी को आरोपी नंबर एक और उनके बेटे तथा लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को आरोपी नंबर दो बनाया है।

नौ अप्रैल को दाखिल ईडी के आरोपपत्र में अन्य आरोपियों में कांग्रेस नेता सुमन दुबे और सैम पित्रोदा, दो कंपनियां यंग इंडियन (वाई आई) और डोटेक्स मर्चेंडाइज प्राइवेट लिमिटेड और सुनील भंडारी (डोटेक्स मर्चेंडाइज के) शामिल हैं।

ईडी ने पीएमएलए की धारा 44 और 45 के तहत ''धनशोधन के अपराध को अंजाम देने'' के साथ ही धारा 70 (कंपनियों द्वारा अपराध) के तहत आरोपपत्र दाखिल किया है। ईडी ने पीएमएलए की धारा चार के तहत आरोपियों के लिए सजा की मांग की है। इस धारा के तहत सात साल तक जेल हो सकती है।

अदालत ने मामले की सुनवाई 25 अप्रैल को तय की है।

सूत्रों ने 'पीटीआई' को बताया कि ईडी ने इस मामले में ''अपराध से अर्जित आय'' की पहचान 988 करोड़ रुपये और संबद्ध संपत्तियों का मौजूदा बाजार मूल्य 5,000 करोड़ रुपये बताया है।

ईडी ने शनिवार को कहा था कि उसने 661 करोड़ रुपये की अचल संपत्तियों को कब्जे में लेने के लिए नोटिस जारी किया है, जिन्हें उसने इस जांच के तहत कुर्क किया है।

आरोपपत्र प्रतिशोध की राजनीति : सिब्बल

नई दिल्ली/भाषा। राज्यसभा सदस्य कपिल सिब्बल ने 'नेशनल हेराल्ड' मामले में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा कांग्रेस के शीर्ष नेताओं सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किए जाने को लेकर मंगलवार को कहा कि यह प्रतिशोध की राजनीति और सत्ता का दुरुपयोग है। वरिष्ठ अधिवक्ता ने यह भी कहा कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की कार्रवाई राजनीति में एक और गिरावट है तथा इस तरह की कार्रवाई बदले की भावना से हो रही है। उन्होंने संवाददाताओं से कहा, इस देश में राजनीति प्रतिशोध की राजनीति, सत्ता के प्रचार की राजनीति, सभी विपक्षी नेताओं पर भ्रष्ट होने का आरोप लगाने की राजनीति, सभी विपक्षी नेताओं को गिरफ्तार करने की कोशिश करने की राजनीतिबन गई है।

मुर्शिदाबाद हिंसा पर खुफिया रिपोर्ट

बांग्लादेशी कट्टरपंथी 'स्थानीय नेताओं की मदद से' हिंसा में शामिल

■ **बांग्लादेश स्थित दो कट्टरपंथी संगठन- जमात-उल मुजाहिदीन बांग्लादेश (जेएमबी) और अंसारुल्लाह बांग्ला टीम (एबीटी) के सदस्य कथित तौर पर मुर्शिदाबाद हिंसा में शामिल थे।**

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

नई दिल्ली/भाषा। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में वक्फ संशोधन कानून के विरुद्ध आंदोलन के कारण हाल ही में उत्पन्न हिंसा में बांग्लादेशी कट्टरपंथी 'शामिल' थे, जिन्हें कथित तौर पर एक राजनीतिक दल के स्थानीय नेताओं की मदद मिली थी। सूत्रों ने यह दावा किया है।

सूत्रों ने एक खुफिया रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि बांग्लादेश स्थित दो कट्टरपंथी संगठनों- जमात-उल मुजाहिदीन बांग्लादेश (जेएमबी) और अंसारुल्लाह बांग्ला टीम (एबीटी) के सदस्य कथित तौर पर मुर्शिदाबाद हिंसा में शामिल थे। इस हिंसा में तीन लोग मारे गए थे।

सूत्रों ने रिपोर्ट का हवाला देते हुए दावा किया कि हिंसा बांग्लादेशी बदमाशों द्वारा की गई थी, जिन्हें कथित तौर पर एक राजनीतिक दल के स्थानीय नेताओं की मदद मिली थी।

सूत्रों ने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्रालय मुर्शिदाबाद की स्थिति पर बारीकी से नजर रख रहा है, जहां शांति बहाल करने और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए राज्य पुलिस के साथ केंद्रीय बलों को तैनात किया गया है।

सूत्रों ने बताया कि भारत-बांग्लादेश सीमा पर तैनात सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) को भी कड़ी निगरानी रखने का निर्देश दिया गया है, ताकि पश्चिम बंगाल में अवैध घुसपैठ न हो सके।

केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन ने मुर्शिदाबाद जिले में बड़े पैमाने पर हुई हिंसा के बाद 12 अप्रैल को पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) के साथ डिजिटल तौर पर बैठक की थी।

केंद्र ने अपनी बातचीत के दौरान राज्य सरकार से अन्य संवेदनशील जिलों पर कड़ी नजर रखने और जल्द से जल्द सामान्य स्थिति सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त कदम उठाने को कहा।

लोगों के जीवन में परिवर्तनकारी बदलाव लाने के लिए काम करें लोक सेवक : मुर्मु

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

नई दिल्ली/एजेन्सी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने लोक सेवकों से ईमानदारी और संवेदनशीलता के साथ काम करने की अपील करते हुए कहा है कि स्थानीय और राज्य स्तर पर उनके द्वारा किए गए विकास एवं जन कल्याण कार्य राष्ट्रीय लक्ष्यों को हासिल करने में सहायक होंगे।

श्रीमती मुर्मु ने मंगलवार को यहां विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों में सहायक सचिव के रूप में कार्यरत 2023 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के एक समूह से राष्ट्रपति भवन सांस्कृतिक केंद्र में मुलाकात की।

राष्ट्रपति ने अधिकारियों को

संबोधित करते हुए कहा , वे असाधारण दृढ़ संकल्प और कड़ी मेहनत से आईएएस अधिकारी बने हैं। इससे उनके व्यक्तिगत जीवन में एक परिवर्तनकारी बदलाव आया है। अब और भी अधिक दृढ़ संकल्प और समर्पण के साथ, उनके पास अनगिनत लोगों के जीवन में परिवर्तनकारी बदलाव लाने का अवसर है। उनकी सेवा और अधिकार का क्षेत्र इतना व्यापक है कि वे अपनी पहली पोस्टिंग में ही कई साथी नागरिकों के जीवन को बेहतर बना सकते हैं।

श्रीमती मुर्मु ने अधिकारियों को वंचित वर्ग के लोगों के उत्थान के लिए विशेष प्रयास करने की सलाह दी। उन्होंने यह भी सलाह दी कि वे अपने करियर की यात्रा के दौरान कुछ समय बाद पोस्टिंग के स्थानों का दौरा करें और अपने काम के दूरगामी परिणाम देखें।

राष्ट्रपति ने कहा कि अधिकारियों को सिविल सेवकों के अधिकारों और कर्तव्यों को ध्यान में रखना चाहिए। लोक सेवक के कर्तव्य ही उसकी जिम्मेदारियां हैं और उसके अधिकार ही उन कर्तव्यों को पूरा करने का साधन हैं। राष्ट्रपति ने अधिकारियों से कहा , उनके असली करियर की कहानी उनके काम से बनेगी,सोशल मीडिया पर फॉलोअर्स की संख्या बढ़ाने से नहीं। उनकी असली सामाजिक संपत्ति उनके अच्छे काम से तय होगी। उन्होंने कहा कि हर लोक सेवक को ईमानदारी और उद्देश्य के साथ काम करना चाहिए। पर्यावरण प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों का सभी सामना कर रहे हैं। अनैतिकता का प्रदूषण और मूल्यों का क्षरण भी बहुत गंभीर चुनौतियां हैं।

वक्फ कानून पर पाकिस्तान की टिप्पणी को खारिज किया भारत ने

नई दिल्ली/एजेन्सी। भारत ने नये वक्फ कानून को लेकर पाकिस्तान की टिप्पणियों को मंगलवार को दृढ़ता से खारिज कर दिया और उसे नसीहत दी कि वह अल्पसंख्यकों के अधिकारों को लेकर स्वयं के रिकॉर्ड को देखे। वक्फ कानून पर पाकिस्तान की टिप्पणियों के बारे में मीडिया के सवालों के जवाब में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा, हम भारत की संसद द्वारा अधिनियमित वक्फ संशोधन अधिनियम पर पाकिस्तान द्वारा की गई प्रेरित और आधारहीन टिप्पणियों को दृढ़ता से खारिज करते हैं। जायसवाल ने कहा,पाकिस्तान के पास भारत के आंतरिक मामले पर टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं है। पाकिस्तान के लिए बेहतर होगा कि जब अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा करने की बात आती है तो वह दूसरों को प्रचार करने के बजाय अपने स्वयं के रिकॉर्ड को देखे।

वक्फ कानून के खिलाफ

दायर याचिकाओं पर आज उच्चतम न्यायालय में सुनवाई

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

नई दिल्ली/एजेन्सी। वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 के खिलाफ उच्चतम न्यायालय में दायर विभिन्न याचिकाओं पर बुधवार को सुनवाई होगी। राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र के लोगों तथा राजनीतिक दलों द्वारा इस अधिनियम के विरुद्ध न्यायालय में 12 से अधिक याचिकाएं दायर की गई हैं जिनमें इस अधिनियम को संविधान के विरुद्ध और एक खास संप्रदाय के प्रति भेदभावपूर्ण बताते हुए इसे निरस्त किए जाने का अनुरोध किया गया है।

न्यायालय ने इन याचिकाओं पर 16 अप्रैल को सुनवाई करने का निश्चय किया।

वक्फ संशोधन अधिनियम को संसद के बजट सत्र में मैराथन चर्चाओं के बाद पारित किया गया। राष्ट्रपति ने इस विधेयक पर मुहर लगा दी जिसके बाद ही यह देश का कानून बन गया है।

भाजपा शासित छह राज्यों ने नये वक्फ कानून के समर्थन में उच्चतम न्यायालय का रुख किया

नई दिल्ली/भाषा। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) शासित मध्यप्रदेश और असम सहित छह राज्यों ने वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 की संवैधानिक वैधता का समर्थन करते हुए उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है। भाजपा शासित छह राज्यों - हरियाणा, महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और असम - ने अलग-अलग याचिकाएं दायर की हैं जिनमें वक्फ (संशोधन) अधिनियम को रद्द किए जाने या इसमें परिवर्तन किए जाने की स्थिति में संभावित प्रशासनिक और कानूनी परिणामों को रेखांकित किया गया है। उत्तराखंड वक्फ बोर्ड, वक्फ (संशोधन) अधिनियम का समर्थन कर रहा है। उसने भी उच्चतम न्यायालय में एक अर्जी दायर की है।

मुंबई आतंकी हमला भारत-पाक संबंधों में महत्वपूर्ण मोड़,

पाकिस्तान गलत हरकतों में संलिप्त : जयशंकर

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

आणंद (गुजरात)/भाषा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मंगलवार को कहा कि 2008 के मुंबई आतंकी हमले से पाकिस्तान के साथ संबंधों में एक महत्वपूर्ण मोड़ आया क्योंकि उस समय भारतीयों ने सामूहिक रूप से महसूस किया कि पड़ोसी देश के इस तरह के व्यवहार को अब बर्दाश्त नहीं किया जा सकता।

चारोतार विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में एक संवाद सत्र को संबोधित करते हुए जयशंकर ने पिछले एक दशक में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत में आए परिवर्तन का जिक्र किया।

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इसके विपरीत, पाकिस्तान

जैसा था, वैसा ही बना हुआ है और वह अब भी ''गलत हरकतों में संलिप्त है।''

यह पूछने पर कि भारत सरकार अब सार्वजनिक रूप से पाकिस्तान पर शायद ही कभी चर्चा करती है, जयशंकर ने स्पष्ट किया कि उस (पाकिस्तान) पर 'कीमती समय' बर्बाद करने की कोई आवश्यकता नहीं है।

उन्होंने कहा, भारत बदल गया है। काश! मैं कह पाता कि पाकिस्तान बदल गया है। दुर्भाग्य से, वे कई मायनों में गलत हरकतों में अब भी लिप्त हैं। मैं कहूंगा कि 26 नवंबर का मुंबई आतंकवादी हमला एक महत्वपूर्ण मोड़ था। मुझे लगता है कि उस समय भारतीय जनता और सभी राजनीतिक दलों ने कहा था कि अब अति हो गई।

जयशंकर ने वर्ष 2008 में सत्ता में रही कांग्रेस के नेतृत्व वाले संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (संप्रग) सरकार पर परोक्ष रूप से कटाक्ष करते हुए, मुझे लगता है कि समाज में यह भावना बहुत प्रबल थी, लेकिन उस समय सरकार द्वारा इसे पूरी तरह से नहीं समझा गया होगा, जो एक अलग मामला है।

गुजरात से राज्यसभा सदस्य जयशंकर ने कहा, 2014 के बाद जब सरकार बदली तो पाकिस्तान को यह सख्त संदेश दिया गया कि अगर आतंकवादी गतिविधियां जारी रहीं तो इसके परिणाम भुगतने होंगे।

इस बार मानसून में देश में सामान्य से अधिक बारिश होने की संभावना : आईएमडी

नई दिल्ली/भाषा। भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने मंगलवार को कहा कि आगामी दक्षिण-पश्चिम मानसून मौसम में भारत में सामान्य से अधिक वर्षा होने की उम्मीद है, जिससे फसलों की अच्छी पैदावार की उम्मीद बढ़ गई है। आईएमडी ने कहा कि मानसून के दीर्घकालिक पूर्वानुमान के अनुसार, तमिलनाडु और पूर्वोत्तर क्षेत्र के बड़े हिस्से में सामान्य से कम वर्षा होने का अनुमान है, जबकि मराठवाड़ा और उससे सटे तेलंगाना के कम वर्षा वाले क्षेत्रों में सामान्य से अधिक वर्षा होने की संभावना है। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय में सचिव एम रविचंद्रन ने यहां संवाददाता सम्मेलन में कहा, ''भारत में चार महीने (जून से सितंबर) के मानसून के मौसम में सामान्य से अधिक वर्षा होने की संभावना है।

पंजाब किंग्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 16 रनों से हराया

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

मोहाली/एजेन्सी। प्रभसिमरन सिंह (30) और प्रियांश आर्य (22) रनों की पारी के बाद युजवेंद्र चहल (चार विकेट) और मार्को यानसन (तीन विकेट) की शानदार गेंदबाजी की बदौलत पंजाब किंग्स ने मंगलवार को इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) के 31वें मुकाबले में कोलकाता नाइट राइडर्स को 16 रनों से हरा दिया। पंजाब किंग्स की छह मैचों में यह चौथी जीत है।

112 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी कोलकाता नाइट राइडर्स की शुरुआत अच्छी नहीं रही और उसने महज सात रन के स्कोर पर अपने दोनों सलामी बल्लेबाजों के

विकेट गवां दिये। क्रिंटन डी कॉक (दो) और सुनील नारायण (पांच) रन बनाकर आउट हुये। ऐसे संकट के समय कप्तान अजिंक्य रहाणे और अंगकृष रघुवंशी ने पारी संभालने का प्रयास किया। दोनों बल्लेबाजों के बीच तीसरे विकेट के लिये 55 रनों की साझेदारी हुई। युजवेंद्र चहल ने आठवें ओवर में अजिंक्य रहाणे (17) को आउट किया उसके बाद 10वें ओवर में अंगकृष रघुवंशी 28 गेंदों में (37) रन को अपना शिकार बना लिया। वेंकटेश अय्यर (सात), रिंकू सिह (दो), रमनदीप सिंह (शून्य), हर्षित राणा (तीन), वैभव आरोड़ा (शून्य) और आंद्रे रसल (17) रन बनाकर आउट हुये। पंजाब किंग्स के गेंदबाजी आक्रमण के आगे कोलकाता नाइट राइडर्स की पूरी टीम 15.1 ओवर में 95 रन ही बना सकी और 16 रनों से मुकाबला हार गई।

सही समय आ गया है और उम्मीद है कि जम्मू-कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल होगा : मुख्यमंत्री उमर

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

श्रीनगर/भाषा। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने मंगलवार को कहा कि उन्हें उम्मीद है कि जम्मू-कश्मीर का राज्य का दर्जा जल्द ही बहाल कर दिया जाएगा तथा 'सही समय आ गया है'। अब्दुल्ला, पुलवामा जिले में एक पुल का उद्घाटन करने के बाद पत्रकारों को संबोधित कर रहे थे।

अब्दुल्ला ने कहा, हमें लगता है कि सही समय आ गया है, विधानसभा चुनाव के छह महीने बीत चुके हैं। (केंद्रीय गृह मंत्री अमित) शाह यहां आए थे, मैंने उनके साथ एक अलग बैठक की, जो अच्छी रही। मुझे अभी भी उम्मीद है कि जम्मू-कश्मीर को जल्द ही अपना राज्य का दर्जा वापस मिल जाएगा। उन्होंने सत्तारूढ़ दल पर वक्फ संशोधन अधिनियम पर चर्चा को बाधित करने के विपक्ष के आरोप पर कहा कि स्थगन प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया जा सकता था क्योंकि विधेयक संसद द्वारा पारित किया गया था।

मुख्यमंत्री ने कहा, अध्यक्ष (विधानसभा) ने आखिरी दिन सबकुछ स्पष्ट कर दिया था। शायद सदस्यों की गलतफहमी थी कि वे स्थगन प्रस्ताव लेकर आए। स्थगन प्रस्ताव केवल जम्मू-कश्मीर सरकार के कामों पर चर्चा के लिए लाया जाता है, क्योंकि सरकार को जवाब देना होता है। उन्होंने कहा, मुझे बताइए कि अगर स्थगन प्रस्ताव स्वीकार कर लिया जाता, तो हम कैसे जवाब देते, क्योंकि वक्फ विधेयक हम नहीं लाये थे। इसे केंद्र ने संसद में पारित किया था।

अब्दुल्ला ने कहा कि विधानसभा में अलग नियमों के तहत प्रस्ताव को स्वीकार किया जा सकता था। उन्होंने कहा, हालांकि, अब वह समय बीत चुका है। नेशनल कॉन्फ्रेंस सहित कई पार्टियां उच्चतम न्यायालय का रुख कर चुकी हैं और अपने विचार शीर्ष अदालत के समक्ष रखे हैं। अब हम देखेंगे कि न्यायालय क्या कहता है।

फीस वृद्धि : रेखा गुप्ता ने स्कूलों को नोटिस जारी करने की बात कही, कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

नई दिल्ली/भाषा। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मंगलवार को कहा कि उन विद्यालयों को नोटिस जारी किया गया है जिनके विरूद्ध मनमाने ढंग से फीस वृद्धि की शिकायतें मिली हैं। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार शिक्षा में पारदर्शिता एवं बच्चों के अधिकारों के संरक्षण के प्रति कटिबद्ध है।

मुख्यमंत्री ने 'पीटीआई-भाषा' से कहा कि इन विद्यालयों से जवाब मांगा गया है, जवाब नहीं मिलने पर उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जायेगी। उन्होंने कहा ''किसी भी विद्यालय को फीस के लिए अभिभावकों को परेशान करने या विद्यार्थियों को अनुचित तरीके से निकालने का अधिकार नहीं है।'' यहां एक 'जन संवाद' कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री को मॉडल टाउन के एक निजी विद्यालय के बारे में शिकायत मिली कि वह कथित तौर पर फीस बढ़ा रहा है और

विद्यार्थियों को निष्कासित कर रहा है। गुप्ता ने 'एक्स' पर एक पोस्ट में इस घटना को साझा करते हुए कहा, ''आज मॉडल टाउन स्थित क्वीन मैरी स्कूल से जुड़ा मामला सामने आया, जहां अभिभावकों ने अनुचित फीस वसूली और विद्यार्थियों को स्कूल से निकाले जाने की शिकायत की।'' मुख्यमंत्री ने एक अधिकारी से बात की और उन्हें मॉडल टाऊन के क्वीन मैरी स्कूल का पंजीकरण तत्काल रद्द करने का निर्देश दिया।

इस स्कूल की ओर से इस पूरे प्रकरण पर तत्काल कोई प्रतिक्रिया नहीं आयी है। इस विद्यालय की एक छात्रा के माता-पिता ने आरोप लगाया कि विद्यालय ने पिछले साल अपनी फीस अचानक बढ़ा दी। उन्होंने कहा, जब हमने अतिरिक्त राशि देने से इनकार कर दिया, तो स्कूल ने मेरी बेटी को पुस्तकालय में बिठा दिया और उसे किसी भी कक्षा में भाग लेने की अनुमति नहीं दी।''

मुख्यमंत्री ने कहा कि इस मामले को गंभीरता से लिया गया है और अधिकारियों को तत्काल जांच कर आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं।

उन्होंने कहा, ''किसी भी विद्यालय को फीस के लिए अभिभावकों को परेशान करने या विद्यार्थियों को गलत तरीके से निकालने का अधिकार नहीं है।'' उन्होंने कहा कि सभी विद्यालयों से निर्धारित नियमों और विनियमों का पालन करने की अपेक्षा की जाती है और किसी भी उल्लंघन के परिणामस्वरूप कार्रवाई की जाएगी।

देश में प्रति दस लाख जनसंख्या पर केवल 15 न्यायाधीश: 2025 'इंडिया जस्टिस' रिपोर्ट

नई दिल्ली/भाषा। देश में प्रति दस लाख आबादी पर केवल 15 न्यायाधीश हैं, जो विधि आयोग की प्रति दस लाख की आबादी पर 50 न्यायाधीशों की सिफारिश से बहुत दूर है। मंगलवार को जारी 'इंडिया जस्टिस सिस्टम रिपोर्ट' 2025 में यह जानकारी सामने आई है।

'इंडिया जस्टिस रिपोर्ट' के मुताबिक, 1.4 अरब लोगों के लिए भारत में 21,285 न्यायाधीश हैं या प्रति दस लाख की आबादी पर लगभग 15 न्यायाधीश हैं। यह 1987 के विधि आयोग की प्रति दस लाख की आबादी पर 50 न्यायाधीशों की सिफारिश से काफी कम है। इस रिपोर्ट में देश में न्याय प्रदान करने के मामले में राज्यों की स्थिति की जानकारी दी गयी है। रिपोर्ट के मुताबिक, उच्च न्यायालयों में रिक्तियां कुल स्वीकृत पदों का 33 प्रतिशत थीं।

रिपोर्ट में 2025 में 21 प्रतिशत रिक्तियों का दावा किया गया, जो मौजूदा न्यायाधीशों के लिए अधिक कार्यभार को दर्शाता है। रिपोर्ट में बताया गया, राष्ट्रीय स्तर पर जिला न्यायालयों में प्रति न्यायाधीश औसत कार्यभार 2,200 मामले है। इलाहाबाद और मध्यप्रदेश उच्च न्यायालयों में प्रति न्यायाधीश मुकदमों का बोझ 15,000 है। रिपोर्ट के मुताबिक, जिला न्यायपालिका में महिला न्यायाधीशों की कुल हिस्सेदारी 2017 में 30 प्रतिशत से बढ़कर 38.3 प्रतिशत हो गई है और 2025 में उच्च न्यायालयों में यह 11.4 प्रतिशत से बढ़कर 14 प्रतिशत हो गई है।

'फर्जी' हृदय रोग विशेषज्ञ मामला

अवैध कैथ लैब चलाने के आरोप में नौ लोगों पर मामला दर्ज

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

दमोह (मप्र)/भाषा। मध्यप्रदेश के दमोह में एक अस्पताल में कथित तौर पर अवैध 'कैथीटेराइजेशन प्रयोगशाला' या कैथ लैब चलाने के आरोप में नौ लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है।

यहां 'फर्जी' हृदय रोग विशेषज्ञ नरेंद्र यादव उर्फ नरेंद्र जॉन कैम ने मरीजों के ऑपरेशन किए, जिनमें से सात की मौत हो गई। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। पिछले सप्ताह अधिकारियों ने मिशनरी अस्पताल दमोह की कैथ लैब को सील कर दिया था।

अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (एएसपी) संदीप मिश्रा ने कहा, फर्जी दस्तावेजों के आधार पर ऑनलाइन माध्यम से कैथ लैब का पंजीकरण कराने के लिए मिशन अस्पताल के निदेशक और प्रबंध समिति सहित नौ लोगों पर मामला दर्ज किया गया है। उन्होंने कहा कि अस्पताल ने जबलपुर स्थित डॉ. अखिलेश दुबे के फर्जी हस्ताक्षर करके कैथ लैब के लिए पंजीकरण प्राप्त किया था।

मिश्रा ने बताया कि कैथ लैब में एंजियोप्लास्टी प्रक्रिया के बाद इस अस्पताल में कुछ मरीजों की मौत हो गई थी। कुछ मरीजों की मौत का कारण भी यही था। उन्होंने बताया कि नौ आरोपियों की पहचान आशिम न्यूटन, फ्रैंक हैरिसन, इंदु लाल, जीवन मैसी, रोशन प्रसाद, कादिर यूसुफ, अजय लाल, संजीव लैम्बार्ड और विजय लैम्बार्ड के रूप में हुई है।

पुलिस सूत्रों ने बताया कि अजय लाल मिशन अस्पताल के निदेशक हैं। दमोह के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी की शिकायत के आधार पर उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया। उन पर भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) और मध्यप्रदेश उपचारगृह तथा रुजोपचार संबंध स्थापना (पंजीकरण तथा अनुज्ञापन) अधिनियम, 1973 के प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया गया है।

मिशनरी अस्पताल में सात मरीजों की मौत की जांच शुरू होने के बाद पुलिस ने आठ अप्रैल को प्रयागराज से डॉ. नरेंद्र यादव उर्फ नरेंद्र जॉन कैम को कथित जालसाजी और अन्य अपराधों के लिए गिरफ्तार किया था। छह अप्रैल को, यहां पुलिस ने दमोह के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी एमके जैन की शिकायत पर यादव के खिलाफ फर्जी मेडिकल डिग्री रखने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की थी। मिशनरी अस्पताल में यादव उर्फ कैम द्वारा कथित तौर पर इलाज किए गए सात मरीजों की मौत की शिकायत मिलने के बाद राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) की टीम ने भी जांच की थी।

चीन पर अमेरिकी शुल्क भारतीय उपकरण उद्योग के लिए एक अवसर: नीति रिपोर्ट

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

नई दिल्ली/भाषा। नीति आयोग ने एक रिपोर्ट में कहा है कि चीन पर अमेरिकी शुल्क और बढ़ती लागत भारत के लिए वैश्विक उपकरण निर्यात बाजार में अपनी भूमिका को बढ़ाने का एक बड़ा अवसर है। रिपोर्ट में साथ ही स्थानीय उपकरण उद्योग को बढ़ावा देने के लिए वैश्विक स्तर के संकुल बनाने और लागत को कम करने के लिए जरूरी सहायता प्रदान करने जैसे उपाय सुझाए गए हैं। नीति आयोग ने 'भारत के हाथ और बिजली से चलने वाले उपकरण क्षेत्र: 25 अरब डॉलर से अधिक निर्यात अवसर' शीर्षक से जारी एक रिपोर्ट में कहा कि इस उद्योग में निर्यात की काफी संभावनाएं हैं, लेकिन बुनियादी ढांचे, उच्च विनिर्माण लागत और बड़े स्तर की विनिर्माण सुविधाओं की कमी से बाधा उत्पन्न होती है। रिपोर्ट के अनुसार, भारत एक महत्वपूर्ण मोड़ पर है, जिसके पास अपने हाथ और बिजली उपकरण उद्योग को वैश्विक निर्यात महाशक्ति में बदलने का एक उल्लेखनीय अवसर है। इस क्षेत्र में 2035 तक 25 अरब डॉलर से अधिक के निर्यात की क्षमता है।

मौजूदा समय में बफर पूंजी के उपयोग की जरूरत नहीं : आरबीआई

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

मुंबई/भाषा। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने मंगलवार को 'काउंटरसाइक्लिकल' यानी सुस्ती की स्थिति से निपटने के लिए तैयार बफर पूंजी (सीसीवाईबी) का उपयोग नहीं करने का निर्णय लिया है। केंद्रीय बैंक का मानना है कि मौजूदा परिस्थिति में इसकी जरूरत नहीं है।

आरबीआई ने सीसीवाईबी की रूपरेखा को फरवरी, 2015 में दिशानिर्देशों के रूप में पेश किया था। इसमें यह सलाह दी गई थी कि परिस्थितियों के अनुरूप सीसीवाईबी को लागू किया जाएगा और इसके बारे में पहले से घोषणा की जाएगी। रूपरेखा में मुख्य संकेतक के रूप में ऋण-जीडीपी अंतर की परिकल्पना की गई है। इसका उपयोग अन्य पूरक संकेतकों के साथ किया जा सकता है। आरबीआई ने बयान में कहा, ''सीसीवाईबी संकेतकों की समीक्षा के आधार पर यह निर्णय लिया गया है कि इस समय इसको लागू करना जरूरी नहीं है।''

इसे पहले 2015 में किया गया, लेकिन आरबीआई ने अबतक इसका उपयोग नहीं किया है। आरबीआई के अनुसार, सीसीवाईबी व्यवस्था के दो उद्देश्य हैं। सबसे पहले, इसके लिए बैंकों को अच्छे समय में पूंजी बफर बनाने की आवश्यकता होती है, जिसका उपयोग कठिन समय में ऋण के प्रवाह को बनाए रखने के लिए किया जा सकता है।

दूसरा, यह बैंक क्षेत्र को अत्यधिक ऋण वृद्धि की अवधि में अंधाधुंध कर्ज देने से रोकने के लक्ष्य को भी हासिल करने में मददगार है।

वर्ष 2008 के वैश्विक वित्तीय संकट के मद्देनजर केंद्रीय बैंक के प्रमुखों और पर्यवेक्षण प्रमुखों के समूह (जीएचओएस) ने प्रतिचक्रीय पूंजी उपायों पर एक रूपरेखा की शुरुआत की परिकल्पना की थी। जीएचओएस बासेल समिति के निर्धारित मानकों की निगरानी करने वाली इकाई है।

अमेरिकी शुल्क से निपटने के लिए भारत बेहतर स्थिति में: पुरी

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

नई दिल्ली/भाषा। आईटीसी के चेयरमैन संजीव पुरी ने कहा है कि अमेरिकी शुल्क से उत्पन्न बाधाओं से निपटने के लिए भारत बेहतर स्थिति में है। उन्होंने मंगलवार को कहा, ''इसकी मुख्य वजह यह है कि भारत की अमेरिका के साथ व्यापार समझौते पर बातचीत काफी तेजी से आगे बढ़ रही है और समझौते पर हस्ताक्षर की संभावना बन रही है।''

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत समेत कई देशों पर जवाबी शुल्क की घोषणा की है। हालांकि, चीन के अलावा बाकी देशों पर इसे तीन महीने के लिए टाल दिया गया है। अभी केवल चीन पर 145 प्रतिशत का शुल्क लागू है। हालांकि, अमेरिका को निर्यात पर 10 प्रतिशत का मूल शुल्क जारी रहेगा। अन्य जवाबी शुल्क अब नौ

जुलाई से लागू होंगे। घरेलू उद्योग पर इन शुल्क के प्रभाव के बारे में पूछे जाने पर पुरी ने कहा कि यह बताना मुश्किल है कि इसका क्या प्रभाव होगा, लेकिन भारत की स्थिति इस मामले में काफी बेहतर होगी। उन्होंने कहा, '' यह कहना मुश्किल है कि इसमें क्या बदलाव आएगा, लेकिन मेरा अपना मानना है कि अंत में भारत की स्थिति काफी बेहतर होगी। हम कई मुक्त व्यापार समझौतों (एफटीए) पर हस्ताक्षर की संभावना देख रहे हैं, जिनकी उद्योग जगत काफी समय से प्रतीक्षा कर रहा है।

ईडी ने सहारा समूह के धनशोधन मामले की जांच के तहत लोनावाला में 'एंबी वैली' को कुर्क किया

नई दिल्ली/भाषा। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मंगलवार को कहा कि उसने सहारा समूह के खिलाफ धनशोधन मामले की जांच के तहत महाराष्ट्र के लोनावाला में 707 एकड़ भूमि में फैली 'एंबी वैली सिटी' को कुर्क कर लिया है, जिसकी कीमत 1,460 करोड़ रुपए है। संघीय जांच एजेंसी ने एक बयान में कहा कि धनशोधन निवारण अधिनियम के तहत एक अनंतिम आदेश जारी किया गया है। इसमें कहा गया कि यह भूमि सहारा समूह की संस्थाओं से प्राप्त धनराशि से ''बेनामी'' नामों से खरीदी गई थी। एजेंसी ने कहा कि सहारा इंडिया और उसकी समूह संस्थाओं के खिलाफ धनशोधन मामले की जांच के तहत लोनावाला (पुणे जिला) स्थित 'एंबी वैली सिटी' और उसके आसपास की कुल 707 एकड़ जमीन को कुर्क कर लिया गया है, जिसकी बाजार में अनुमानित कीमत 1460 करोड़ रुपए है।

तिरुमला बोर्ड के सदस्य ने गायों की मौत के मामले में पूर्व अध्यक्ष के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई

तिरुपति/भाषा। तिरुमला तिरुपति देवस्थानम (टीटीडी) बोर्ड के सदस्य जी भानु प्रकाश रेड्डी ने गायों की मौत के संबंध में अपने आरोपों से मंदिर प्रबंधन को कथित रूप से ''बदनाम'' करने के लिए पूर्व अध्यक्ष बी करुणाकर रेड्डी के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। हालांकि, करुणाकर ने गायों की मौत की गहन जांच की मांग करते हुए कहा कि वह अपने बयान पर कायम हैं, क्योंकि उन्होंने ''कुछ भी गलत नहीं'' किया।

करुणाकर ने 11 अप्रैल को संवाददाता सम्मेलन में आरोप लगाया कि टीटीडी गोशाला में बड़ी संख्या में गायें मर रही हैं। उन्होंने दावा किया कि पिछले तीन महीनों में ''लापरवाही'' के कारण 100 गायों की मौत हुई है। भानु प्रकाश ने शिकायत में कहा, ''काल्पनिक आधार पर लगाए गए बेबुनियाद आरोप निश्चित रूप से मानहानि के बराबर हैं और वे आम जनता की नजर में मंदिर और उसके प्रशासन की प्रतिष्ठा को कम करते हैं। शिकायत को मंगलवार को 'पीटीआई-भाषा' के साथ साझा किया गया। शिकायत में करुणाकर के दावों का खंडन किया गया है। भानु प्रकाश ने कहा कि ये आरोप समाचारपत्रों और सोशल मीडिया पर सामने आए हैं, जिससे ''श्रद्धालुओं की भावनाएं आहत हुई हैं और उनकी आस्था को चोट पहुंची है।'' इसके मद्देनजर, भानु प्रकाश ने पुलिस अधीक्षक (एसपी) से पूर्व टीटीडी अध्यक्ष और ऐसे दावे करने वाले अन्य लोगों के खिलाफ उचित कार्रवाई करने का अनुरोध किया है। इस बीच, करुणाकर ने गायों की मौतों की गहन जांच की मांग दोहराते हुए कहा है कि वह अपने बयान पर कायम हैं।

उन्होंने कहा, ''मैं किसी भी धमकी से नहीं डरूंगा, क्योंकि मैंने कोई गलत काम नहीं किया।'' युवजन श्रमिक रायतु कांग्रेस पार्टी (वाईएसआरसीपी) की प्रेस विज्ञप्ति में करुणाकर रेड्डी ने कहा, ''टीटीडी के कार्यकारी अधिकारी (ईओ) श्यामला राव ने कहा कि 43 गायें मरी हैं, जबकि अध्यक्ष बी आर नायडू ने दावा किया कि यह संख्या 22 है। दोनों आंकड़े मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू के इस दावे का खंडन करते हैं कि गोशाला में कोई मौत नहीं हुई।''

विशिष्ट शिक्षण संस्थानों में भी संकट पैदा कर रहे हैं बेरोजगारी और वेतन स्थिरता: कांग्रेस

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

नई दिल्ली/भाषा। कांग्रेस ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों (आईआईटी), राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थानों (एनआईटी) और भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थानों (आईआईआईटी) में 'प्लेसमेंट' में गिरावट के दावे वाली एक खबर को लेकर मंगलवार को आरोप लगाया कि बेरोजगारी तथा वेतन स्थिरता केवल अनौपचारिक क्षेत्र और ग्रामीण आबादी को प्रभावित नहीं कर रहे हैं, बल्कि विशिष्ट शैक्षणिक संस्थानों में भी संकट पैदा कर रहे हैं।

पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने दावा किया कि शिक्षा, महिला, बाल, युवा एवं खेल संबंधी संसदीय स्थायी समिति ने उच्च शिक्षा विभाग की अनुदान मांगों पर अपनी 364वीं रिपोर्ट में भारत के शीर्ष शैक्षणिक संस्थानों जैसे आईआईटी, एनआईटी और आईआईआईटी में प्लेसमेंट में आई चिंताजनक गिरावट को दर्ज किया है रमेश ने एक बयान जारी कर कहा, ''आज एक प्रमुख अख़बार ने और आईआईटी में प्लेसमेंट के चिंताजनक रुझानों पर और भी विस्तार से एक खबर प्रकाशित की है।''

कांग्रेस नेता ने इस खबर का हवाला देते हुए दावा किया कि वर्ष 2021-22 से 2023-24 के बीच, भारत के 23 में से 22 आईआईटी में प्लेसमेंट में गिरावट दर्ज की गई तथा इनमें से 15 आईआईटी में प्लेसमेंट में गिरावट 10 प्रतिशत से अधिक थी। रमेश का कहना है, ''साल 2021-22 में प्लेसमेंट प्रक्रिया में शामिल हुए आईआईटी के 90.43 प्रतिशत बीटेक छात्रों को नौकरी मिल गई थी, जबकि 2023-24 में केवल 80.25 प्रतिशत छात्रों को ही नौकरी मिली। 2023-24 में, 25 में से 23 आईआईआईटी में प्लेसमेंट की दर 2021-

22 की तुलना में घटी। इनमें से 16 संस्थानों में प्लेसमेंट में 10 प्रतिशत से अधिक की गिरावट देखी गई।'' उन्होंने दावा किया कि 2022-23 और 2023-24 के बीच, 31 एनआईटी में से 27 एनआईटी में इंजीनियरिंग स्नातकों को दिए गए औसत वेतन पैकेज में गिरावट दर्ज की गई तथा इनमें से तीन संस्थानों में औसत पैकेज में तीन लाख रुपए प्रतिवर्ष से अधिक की गिरावट देखी गई। रमेश ने कहा, ''आईआईटी देश के प्रमुख इंजीनियरिंग संस्थान हैं, जहां सबसे प्रतिस्पर्धी प्रवेश प्रक्रिया होती है, जो देश के सर्वश्रेष्ठ शिक्षक और छात्र आकर्षित करती है। इंजीनियरिंग को वैसे भी सबसे अधिक नौकरी-योग्य डिग्रियों में से एक माना जाता है। अगर आईआईटी जैसे संस्थानों से हर पांच में से एक इंजीनियर नौकरी पाने में असमर्थ है, तो इससे बड़ा सवाल खड़ा होता है कि देश के बाकी पढ़े-लिखे युवाओं की बड़ी आबादी को रोजगार कैसे मिलेगा।'' उन्होंने दावा किया कि एनआईटी और आईआईआईटी जैसे संस्थानों में भी प्लेसमेंट में गिरावट देखी जा रही है, जो देश में बड़े पैमाने पर नौकरी के बाजार में ठहराव की ओर इशारा करता है। रमेश ने कहा, ''कांग्रेस कई वर्षों से बड़े पैमाने पर बेरोजगारी और वेतन स्थिरता के मुद्दे उठाती आ रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि प्लेसमेंट डेटा यह साबित करता है कि यह संकट केवल अनौपचारिक क्षेत्र और ग्रामीण आबादी को प्रभावित नहीं कर रहे हैं, बल्कि हमारे सबसे विशिष्ट शैक्षणिक संस्थानों में भी संकट पैदा कर रहे हैं।

राष्ट्रीय स्थिरता के लिए बड़े जोखिम पैदा कर सकते हैं साइबर हमले : कांत

नई दिल्ली/भाषा। देश के स्मार्ट मीटर और डिजिटल ग्रिड की ओर बढ़ने के साथ ही साइबर हमले राष्ट्रीय स्थिरता और रोजमर्रा की जिंदगी के लिए बड़े जोखिम पैदा कर सकते हैं। भारत के जी20 शेरपा अमिताभ कांत ने मंगलवार को यह बात कही। उन्होंने कहा कि 2024 में बैंकिंग, वित्तीय सेवाओं और बीमा क्षेत्रों में साइबर हमलों में भारी उछाल देखा गया और भारत में डेटा या किसी के ब्योरे में सेंध की औसत लागत लगभग 28 लाख अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गई। उन्होंने कहा कि पिछले साल, भारतीय व्यवसायों को प्रति सप्ताह 3,000 से अधिक साइबर हमलों का सामना करना पड़ा।

कांत ने राष्ट्रीय राजधानी में साइबर सुरक्षा समाधान कंपनी लिसिएंथस टेक के एक अध्ययन को जारी करते हुए कहा कि भारत ने सरकार प्रायोजित साइबर हमलों में बहुत तेज उछाल देखा है और 2021-24 के बीच ऐसी घटनाओं में लगभग 300 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। नीति आयोग के पूर्व मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) ने कहा कि जैसे-जैसे भारत स्मार्ट मीटर और अधिक डिजिटल पावर ग्रिड की ओर बढ़ रहा है, साइबर हमलों का जोखिम भी गहराता जा रहा है। उन्होंने कहा, ''हाल के वर्षों में, हमने बिजली इकाइयों, स्वास्थ्य सेवा आंकड़ों और उपग्रह संचार प्रणालियों पर भी हमले देखे हैं।''

सोनिया, राहुल के खिलाफ मामले में कोई तथ्य नहीं, सिर्फ राजनीतिक प्रतिशोध है : सिंघवी

नई दिल्ली/भाषा। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अभिषेक सिंघवी ने मंगलवार को कहा कि उनकी पार्टी के शीर्ष नेताओं सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ जिस 'नेशनल हेराल्ड' मामले में आरोप पत्र दाखिल किया गया है वो फर्जी है और उसमें कोई तथ्य नहीं है। सिंघवी ने यह आरोप भी लगाया कि यह सब राजनीतिक प्रतिशोध की भावना के तहत किया गया है।

वरिष्ठ अधिवक्ता सिंघवी ने एक वीडियो जारी करके कहा, ''नेशनल हेराल्ड मामले में जो

प्रक्रियाएं हो रही हैं वो कुछ भी नई नहीं है क्योंकि जब यह मामला शुरू हुआ तो मैंने कहा था कि यह बड़ा ही विचित्र मामला है, जिसमें एक रुपए की लेनदेन नहीं है।'' उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि एक गैर-लाभकारी कंपनी बनाई गई जिसमें सोनिया गांधी और कुछ अन्य लोग निदेशक बनाए गए तथा यह सिर्फ 'नेशनल हेराल्ड' की संपत्तियों के प्रबंधन के लिए था। सिंघवी ने कहा, ''एक मनगढ़ंत और झूठा मामला दर्ज किया गया और अब आरोप पत्र दायर किया गया है। इसका कानूनी रूप से सामना किया जा रहा है।'' उन्होंने दावा किया कि यह एक फर्जी मामला है और इसमें कोई तथ्य नहीं है। राज्यसभा सदस्य सिंघवी ने कहा, ''यह सब राजनीतिक प्रतिशोध की भावना से किया जा रहा है।''

दिग्विजय सिंह ने रामदेव के 'शरबत जेहाद' वाले बयान के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज कराई

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

भोपाल/भाषा। मध्यप्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने योग गुरु बाबा रामदेव के शरबत 'जेहाद' वाले बयान को देश में धार्मिक सद्भाव के माहौल को बिगाड़ने का 'कुत्सित प्रयास' करार देते हुए मंगलवार को यहां स्थानीय थाने में एक शिकायत दर्ज कराई और उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग की।

उन्होंने यहां एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि रामदेव का यह बयान धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला एवं वैमनस्यपूर्ण एवं धार्मिक भावनाओं पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला है तथा भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की विभिन्न धाराओं के अंतर्गत दंडनीय अपराध है। ज्ञात हो कि रामदेव का एक वीडियो पिछले कई दिनों से सोशल मीडिया पर वायरल है। इसमें वह पतंजलि के शरबत का प्रचार करने के दौरान यह कहते हुए देखे और सुने जा सकते हैं कि शरबत के नाम पर एक कंपनी है जो शरबत तो देती है लेकिन शरबत से जो पैसा मिलता है उससे मदरसे और मस्जिदें बनवाती है। रामदेव ने कहा, ''अगर आप वो शरबत पिएंगे तो मस्जिद और मदरसे

बनेंगे और पतंजलि का शरबत पिएंगे तो गुरुकुल बनेंगे, आचार्य कुलम बनेगा, पतंजलि विश्वविद्यालय और भारतीय शिक्षा बोर्ड आगे बढ़ेगा। इसलिए मैं कहता हूं ये 'शरबत जेहाद' है। जैसे 'लव जेहाद', 'वोट जेहाद' चल रहा है वैसे ही 'शरबत जेहाद' भी चल रहा है।'' राज्यसभा सदस्य सिंह ने कहा कि रामदेव ने अपने 'गुलाब' शरबत को बेचने के लिए 'रूह अफजा' शरबत को हिंदू-मुस्लिम विवाद में डाल दिया और मोहब्बत के शरबत को 'शरबत जेहाद' का नाम दे दिया। उन्होंने कहा, ''हमारा संविधान ऐसे नफरत भरे बयान देने की खिलाफत करता है जो आपस में बैर भाव उत्पन्न करें और देश का सद्भाव बिगाड़ने का प्रयास करें।'' उन्होंने कहा, ''रामदेव का यह बयान धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला, वैमनस्यपूर्ण एवं धार्मिक भावनाओं पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला है तथा भारतीय न्याय संहिता-2023 की धारा 196 (1) (क), 299 एवं आईटी कानून की विभिन्न धाराओं के अंतर्गत दण्डनीय अपराध है।'' सिंह ने कहा कि 'व्यापारी' रामदेव ने बिना नाम लिये जिस शरबत कंपनी का जिक्र किया है उस 'हमदर्द' कंपनी को पूरा देश जानता है और यह हमारे देश में लगभग 100 वर्षों से आयुर्वेदिक एवं यूनानी दवाओं का व्यापार कर रही है।

फियो का सरकार से निर्यात की गति बनाये रखने को रणनीतिक समर्थन देने का आग्रह

नई दिल्ली/भाषा। निर्यातकों के शीर्ष निकाय फियो ने मंगलवार को सरकार से निर्यात की गति बनाये रखने के लिए समर्थन उपायों को बढ़ाने का आग्रह किया। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, निर्यात वित्त वर्ष 2024-25 में मामूली 0.08 प्रतिशत बढ़कर 437.42 अरब डॉलर रहा। इस साल मार्च महीने में यह मामूली 0.7 प्रतिशत बढ़कर 41.97 अरब डॉलर रहा।

भारतीय निर्यात संगठनों के महासंघ (फियो) के अध्यक्ष एससी रल्हन ने निर्यात की गति को बनाए रखने के लिए रणनीतिक समर्थन का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि निर्यात प्रतिस्पर्धी क्षमता बढ़ाने, उत्पादों और बाजारों में विविधता लाने और लॉजिस्टिक तथा बुनियादी ढांचे की खामियों को दूर करने के लिए उपाय किये जाने की जरूरत है।

रल्हन ने नियामकीय बोझ को कम करने और सस्ता कर्ज सुलभ कराने भी सुझाव दिया। उन्होंने कहा कि वैश्विक चुनौतियों के बीच निरंतर वृद्धि सुनिश्चित करने के लिए सरकार और उद्योग के साथ मिलकर काम करने को लेकर फियो प्रतिबद्ध है।

यह जाति जनगणना है या नफरत की जनगणना? : कुमारस्वामी

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

बेंगलूरु/बेलगावी। केंद्रीय मंत्री एचडी कुमारस्वामी ने कर्नाटक मंत्रिमंडल के समक्ष पेश सामाजिक-आर्थिक और शिक्षा सर्वेक्षण रिपोर्ट (जाति जनगणना) की आलोचना करते हुए मंगलवार को सवाल किया कि यह जाति जनगणना है या नफरत की जनगणना? उन्होंने राज्य सरकार से कर्नाटक में वोक्कालिगा समुदाय की वास्तविक आबादी बताने की मांग भी की। वहीं, भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की कर्नाटक इकाई के अध्यक्ष विजयेंद्र येडीयुरप्पा ने मुख्यमंत्री सिद्दरामय्या पर आरोप लगाया कि वह 'जाति जनगणना' के जरिये समाज में विभाजन पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। विजयेंद्र ने दावा किया कि 'जाति जनगणना' का उद्देश्य सिद्दरामय्या के राजनीतिक हितों की रक्षा करना है और अब समय आ गया है कि वह मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दें।

इस्पात और भारी उद्योग मंत्री कुमारस्वामी ने एक बयान जारी कर पूछा कि कर्नाटक में प्रमुख कृषक समुदाय वोक्कालिगा की वास्तविक आबादी कितनी है। कुमारस्वामी खुद इस समुदाय से आते हैं। उन्होंने कहा, यह वास्तव में क्या है, जाति जनगणना या नफरत की जनगणना? क्या यह तथाकथित जनगणना राज्य में जानबूझकर अशांति भड़काने के लिए रची गई साजिश है? या यह केवल लगातार बढ़ती महंगाई और घोटालों से होने वाली शर्मिंदगी से ध्यान भटकाने की एक चाल है?

कुमारस्वामी ने कहा, इससे पूरा राज्य जातिगत विभाजन की आग में न झुलसने लगे। क्या कर्नाटक में कांग्रेस सरकार का यह कदम कुछ समुदायों को राजनीतिक और सामाजिक रूप से हाशिये पर धकेलने का एक पूर्व नियोजित प्रयास है? लीक हुई सामाजिक-आर्थिक और शिक्षा सर्वेक्षण रिपोर्ट पर चिंता जताते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इस रिपोर्ट के तथाकथित आंकड़ों पर अब हर जगह चर्चा हो रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि किसी अज्ञात स्रोत ने इन आंकड़ों को नियोजित तरीके से सार्वजनिक मंच पर लीक किया है।

कुमारस्वामी ने पुराने मैसूर क्षेत्र जैसे मांड्या, कोलार, चिक्काबल्लापुर, रामनगर, बेंगलूरु ग्रामीण, तुमकुरु और चित्रदुर्ग में रहने वाले वोक्कालिगा समुदाय की वास्तविक आबादी बताने की मांग की। उन्होंने जाति जनगणना पर अपना रुख बदलने के लिए कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार की आलोचना भी की और दावा किया कि शिवकुमार ने पहले इस कवायद का विरोध किया था।

कुमारस्वामी ने कहा, 'मुख्यमंत्री की कुर्सी की चाह में रातों की नींद गंवाने वाले शिवकुमार ने एक बार समुदाय से विनती की थी कि मुझे बस एक बार कलम और

कागज दे दो!' और अब क्या वही व्यक्ति सिर झुकाकर सिद्ध षड्यंत्र रिपोर्ट का समर्थन कर रहा है? सिद्ध से उनका इशारा मुख्यमंत्री सिद्दरामय्या की ओर था।

कुमारस्वामी ने कहा, मैं इस रिपोर्ट का समर्थन नहीं करता। मैं इस अन्याय के खिलाफ लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार हूं। वहीं, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष विजयेंद्र ने सिद्दरामय्या पर 'जाति जनगणना' के जरिये समाज को बांटने की कोशिश करने का आरोप लगाया। उन्होंने बेलगावी में संवाददाताओं से बातचीत में दावा किया कि सामाजिक-आर्थिक एवं शिक्षा सर्वेक्षण रिपोर्ट पहले लागू नहीं की जा सकी और मौजूदा सरकार इस पर आगे नहीं बढ़ेगी, क्योंकि यह अब पुरानी हो चुकी है।

विजयेंद्र ने कहा, भाजपा पिछड़े और वंचित वर्गों के आर्थिक, शैक्षणिक एवं सामाजिक उत्थान तथा उन्हें न्याय दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है। इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन सिद्दरामय्या ने इस मुद्दे (जाति जनगणना) का इस्तेमाल करके अपनी राजनीतिक जड़ें मजबूत करने की साजिश रची है। अगर सिद्दरामय्या को न्याय की सच्ची चिंता थी, तो उन्होंने मुख्यमंत्री के रूप में अपने पिछले कार्यकाल के दौरान इस सर्वेक्षण को लागू क्यों नहीं किया?

उन्होंने कहा, बाद में जब कांग्रेस-जनता दल (सेक्युलर) गठबंधन की सरकार बनी, तो सिद्दरामय्या समन्वय समिति के प्रमुख थे। उन्होंने उस समय जाति जनगणना क्यों नहीं करवाई? यही नहीं, मौजूदा सरकार को भी सत्ता में आए बीस महीने बीत चुके हैं। विजयेंद्र ने आरोप लगाया, सिद्दरामय्या को यह मुद्दा अब याद आ रहा है, क्योंकि उनके इस्तीफे का समय नजदीक आ रहा है। उन्हें किसी और के लिए मुख्यमंत्री पद खाली करना पड़ सकता है। इसलिए, चीजों को भड़काने के लिए, वह इसका दुरुपयोग कर रहे हैं। किसी को भी यह गलतफहमी नहीं होनी चाहिए कि मुख्यमंत्री को इस मामले में वाकई चिंता है।

कर्नाटक राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट 11 अप्रैल को मंत्रिमंडल के समक्ष रखी गई थी। 17 अप्रैल को होने वाली विशेष कैबिनेट बैठक में इस पर चर्चा की जाएगी। सिद्दरामय्या के नेतृत्व वाली पिछली कांग्रेस सरकार (2013-2018) ने 2015 में यह सर्वेक्षण कराया था। राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग को उसके तत्कालीन अध्यक्ष एच कंथाराजू के नेतृत्व में यह रिपोर्ट तैयार करने का काम सौंपा गया था।

सर्वेक्षण का काम 2018 में पूरा हुआ था, जब मुख्यमंत्री के रूप में सिद्दरामय्या का पहला कार्यकाल समाप्त हो रहा था। राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष के रूप में कंथाराजू की जगह लेने वाले जयप्रकाश हेगड़े ने फरवरी 2024 में रिपोर्ट को अंतिम रूप दिया। विजयेंद्र ने दावा किया कि इस जाति जनगणना रिपोर्ट को लागू करना संभव नहीं है और यह सरकार ऐसा नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि रिपोर्ट पुरानी हो चुकी है, क्योंकि सर्वेक्षण को हुए 10 साल बीते चुके हैं।

प्रदेश भाजपा अध्यक्ष ने कांग्रेस सरकार पर जाति जनगणना के मुद्दे पर पाखंड करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि सिद्दरामय्या सरकार के खिलाफ भाजपा की जनाक्रोश यात्रा' सफल हो रही है और मुख्यमंत्री इससे ध्यान भटकाने की कोशिशों में जुटे हुए हैं। कर्नाटक भाजपा ने सात अप्रैल को 16 दिवसीय 'जनाक्रोश यात्रा' शुरू की, जो आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि, कथित मुस्लिम तुष्टीकरण और दलित कल्याण के लिए निर्धारित धन के कथित दुरुपयोग के लिए कांग्रेस सरकार के खिलाफ एक राज्यव्यापी अभियान है।

अदालत ने गूगल इंडिया, अधिकारियों से फेमा जुर्माने की 50 प्रतिशत राशि बतौर बैंक गारंटी देने को कहा

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

बेंगलूरु। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने गूगल इंडिया और इसके तीन वरिष्ठ अधिकारियों को विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा) के उल्लंघन के आरोप में लगाए गए जुर्माने की 50 प्रतिशत राशि बैंक गारंटी के रूप में जमा करने का निर्देश दिया है। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गूगल इंडिया पर पांच करोड़ रुपये तथा इसके तीन अधिकारियों पर संयुक्त रूप से 45 लाख रुपये का जुर्माना लगाया था। यह मामला फेमा की धारा 6(3)(डी) के कथित उल्लंघन से संबंधित है, जिसमें 364 करोड़ रुपये के लेनदेन की बात शामिल है।

ईडी के अनुसार, उल्लंघन का मामला गूगल इंडिया द्वारा गूगल आयरलैंड को वितरक शुल्क के रूप में किए गए भुगतान और गूगल यूएस से उपकरण खरीद से संबंधित हैं। एजेंसी ने दलील दी कि गूगल आयरलैंड को देय 363 करोड़ रुपये का भुगतान मई 2014 तक चार वर्षों से अधिक समय तक नहीं किया गया, जबकि गूगल यूएस से प्राप्त एक करोड़ रुपये मूल्य के उपकरणों का भुगतान जनवरी 2014 तक सात वर्षों से अधिक समय तक नहीं किया गया।

ईडी ने इन्हें वाणिज्यिक ऋण के रूप में वर्गीकृत किया, जिसके लिए भारतीय रिजर्व बैंक से पूर्व अनुमोदन की आवश्यकता होगी। हालाँकि, गूगल इंडिया ने इन आरोपों का खंडन करते हुए कहा कि सवालों के घेरे में आया लेनदेन विदेशी मुद्रा उधारी नहीं था। कंपनी ने इस बात पर जोर दिया कि इसमें कोई ऋण समझौता, आस्थगित भुगतान या ब्याज शामिल नहीं है, तथा उसने 1 जुलाई 2014 को जारी रिजर्व बैंक के परिपत्र का अनुपालन करने का दावा किया।

इससे पहले, 11 जनवरी, 2019 को दिल्ली में फेमा के लिए अपीलीय न्यायाधिकरण ने यह कहते हुए जुर्माने पर रोक लगा दी थी कि गूगल इंडिया की अपील में दम है। इसके बाद ईडी ने रोक को चुनौती देते हुए दूसरी अपील दायर की। न्यायमूर्ति वी कामेश्वर राव और न्यायमूर्ति एस रचैया की खंडपीठ ने कहा कि न्यायाधिकरण का स्थगन केवल प्रारंभिक राय पर आधारित था। उन्होंने अब गूगल इंडिया और संबंधित अधिकारियों को दो सप्ताह के भीतर कुल जुर्माने की आधी राशि के लिए बैंक गारंटी उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है।

कांग्रेस पार्टी को सिर्फ सत्ता के लिए अंबेडकर याद आते हैं : विजयेन्द्र

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

निप्पाणी। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष व विधायक विजयेन्द्र येडीयुरप्पा ने कांग्रेस पार्टी पर आरोप लगाया कि कांग्रेस केवल सत्ता के लिए अंबेडकर और संविधान को याद करती है। कांग्रेस के पास अपनी कोई ताकत नहीं है। वे मंगलवार को यहां आयोजित 'भीम न्यामी' शताब्दी समारोह कार्यक्रम के ऐतिहासिक समापन समारोह में बोल रहे थे। उन्होंने उन पर आरोप लगाया कि कांग्रेसी सिर्फ चुनाव जीतने के लिए डॉ. अंबेडकर को याद करती है। भारत सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। इस देश को संविधान देने वाली पुण्य आत्मा डॉ. अंबेडकर को सम्मान देने वाला देश है। उन्होंने कहा कि यह देश

अंबेडकर को सम्मान देने वाला देश है। देश पर लगभग 60 वर्षों तक शासन करने वाली कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व डॉ. अंबेडकर ने किया और उनका लगातार अपमान किया गया। उन्होंने याद दिलाया कि वी.पी. सिंह सरकार ने अटल बिहारी वाजपेयी के आग्रह पर अंबेडकर को भारत रत्न से सम्मानित किया था। जिस कांग्रेस सरकार ने बाबा साहेब के अंतिम संस्कार के लिए दिल्ली में जगह तक नहीं दी, वह कांग्रेस की सरकार है। कांग्रेस ने बाबासाहेब अंबेडकर को दो बार चुनाव में हराया था। उन्होंने अंबेडकर को हराने वाले व्यक्ति को पद्म विभूषण देने के लिए कांग्रेस की आलोचना की। इस मौके पर यहां डॉ. अंबेडकर का रथ लाने वाले नेताओं ने कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए शशिकला जोले को उनके प्रयासों के लिए उन्होंने बधाई दी।

उन्होंने कहा कि एकमात्र गारंटी कांग्रेसियों द्वारा मूल्य वृद्धि है। यह जनविरोधी सरकार है। मूल्य वृद्धि की सरकार 50 से अधिक आवश्यक वस्तुओं की कीमतें बढ़ा दी गई हैं। उन्होंने आपत्ति जताई कि दलितों के हजारों करोड़ रुपये का दुरुपयोग किया गया है।

उन्होंने अपील की कि हमें आने वाले दिनों में भाजपा को स्पष्ट बहुमत से जिताना होगा। आइये, हम सब मिलकर जनता के विश्वास से भाजपा को उसकी ताकत के बल पर सत्ता में लायें। उन्होंने लोगों से जनविरोधी कांग्रेस शासन को हटाने की अपील की।

इस मौके पर विपक्षी नेता आर. अशोक, विधान परिषद में विपक्ष के नेता चलावादी नारायणस्वामी, पूर्व उप मुख्यमंत्री और सांसद गोविंदा कारजोल, विधान परिषद विपक्ष के मुख्य सचेतक एन. रविकुमार, पूर्व मंत्री शशिकला जोला, भाजपा के राज्य महासचिव और पूर्व विधायक पी. राजीव, भाजपा के राज्य उपाध्यक्ष और पूर्व मंत्री एन. महेश, विधायक डॉ. अविनाश जाधव, दुर्योधन एहोल, बसवराज मैटिमोड, निखिल कट्टी, डॉ. चंद्रू लमानी, विधान परिषद सदस्य हनुमंत निरानी, पूर्व सांसद डॉ. उमेश जाधव, एस. मुनीस्वामी सहित अनेक नेतागण कार्यक्रम में उपस्थित थे।

एनआईए ने भाजपा नेता की हत्या मामले में चार और आरोपियों के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

बेंगलूरु/नई दिल्ली। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की कर्नाटक इकाई के नेता प्रवीण नेट्टारू की प्रतिबंधित पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) के सदस्यों द्वारा वर्ष 2022 में की गई नृशंस हत्या में कथित संलिप्तता को लेकर चार और आरोपियों के खिलाफ मंगलवार को आरोपपत्र दाखिल किया। इनमें से तीन फरार हैं। एनआईए ने अपने दूसरे पूरक आरोपपत्र में अब्दुल नासिर, नौशाद, अब्दुल रहमान और अतीक अहमद का नाम शामिल किया है। इसके साथ ही इस मामले में जिन आरोपियों के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया गया है उनकी संख्या बढ़कर 27 हो गई है, जिनमें से छह फरार हैं।

एजेंसी की ओर से जारी एक बयान के मुताबिक, आज (मंगलवार को) जिन चार आरोपियों के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया गया है, उनमें से तीन फरार हैं और उनकी पहचान अब्दुल नासिर, नौशाद और अब्दुल रहमान के रूप में की गई है। भाजपा युवा मोर्चा जिला कार्यकारी समिति सदस्य नेट्टारू की 26 जुलाई 2022 को दक्षिण कन्नड़ जिले के बेल्लारे गांव में मोटरसाइकिल सवार दो हमलावरों ने हत्या कर दी थी।

एनआईए की जांच के अनुसार, नासिर, नौशाद व अब्दुल रहमान ने कर्नाटक के मैसूरु और चामराजनगर जिलों और तमिलनाडु के इरोड जिले में तीन मुख्य हमलावरों को पनाह दी थी। एजेंसी ने दावा किया है कि नासिर और रहमान बेंगलूरु में एक अन्य आरोपी थुफैल एमएच को पनाह देने में भी शामिल थे। बयान के मुताबिक, एनआईए मामले में जारी जांच के तहत फरार आरोपियों का पता लगाने की कोशिश कर रही है। एजेंसी ने कर्नाटक पुलिस से जांच का जिम्मा संभाला था।

बेलगावी में मालगाड़ी के डिब्बे पटरी से उतरे, सेवाएं बाधित

बेलगावी। कर्नाटक के बेलगावी रेलवे स्टेशन में प्रवेश करते समय मंगलवार की सुबह एक मालगाड़ी के दो डिब्बे पटरी से उतर गए, जिससे मार्ग पर ट्रेन सेवाएं बाधित हो गईं। रेलवे के अधिकारियों ने यह जानकारी दी। अधिकारियों ने बताया कि इस हादसे में किसी के हताहत होने या घायल

होने की कोई खबर नहीं है। यह हादसा बेलगावी में कांग्रेस रोड पर मिलिट्री महादेव मंदिर के सामने पटरी पर हुआ। मालगाड़ी महाराष्ट्र के मिराज की ओर जा रही थी। दक्षिण पश्चिम रेलवे द्वारा जारी एक बयान में कहा गया है कि हुबली से एक दुर्घटना राहत ट्रेन घटनास्थल पर भेजी गई है ताकि मरम्मत कार्य जल्द पूरा किया जा सके। इस बयान में कहा गया है कि प्रभावित यात्रियों को उनके गंतव्य तक पहुंचाने के लिए आवश्यक प्रबंध किए गए हैं। बयान में कहा गया है, दक्षिण-पश्चिम रेलवे के महाप्रबंधक और अन्य वरिष्ठ अधिकारी स्थिति पर बारीकी से नजर रख रहे हैं और यातायात बहाली का काम जारी है।

नशीले पदार्थों के साथ विदेशी नागरिक समेत 10 गिरफ्तार

बेंगलूरु। बेंगलूरु पुलिस ने नशीले पदार्थों की तस्करी से जुड़े तीन अलग-अलग मामलों में एक विदेशी नागरिक समेत 10 लोगों को गिरफ्तार किया है और इनके पास से 6.77 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य के मादक पदार्थ, नकदी और वाहन जब्त किए हैं। पुलिस ने मंगलवार को बताया कि गिरफ्तार किए गए 10 आरोपियों में से नौ केरल के निवासी हैं।

पहले मामले में केरल के एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर उसके पास से 3.5 किलोग्राम हाइड्रोपोनिक गांजा, एक मोबाइल फोन और 26 लाख रुपये नकद बरामद किए गए। दूसरे मामले में एक विदेशी नागरिक को एक किलोग्राम एमडीएमए क्रिस्टल, एक मोबाइल फोन और एक दोपहिया वाहन के साथ पकड़ा गया। एमडीएमए क्रिस्टल की कुल कीमत दो करोड़ रुपये आंकी गई है। तीसरे मामले में केरल के आठ लोगों को गिरफ्तार किया गया है। उनके पास से 110 ग्राम एमडीएमए (एक्स्टेसी गोलियां) बरामद की गईं, जिसकी कीमत 27 लाख रुपये बताई गई है।

संख्याः भा.ति.सी.पु./21वीं वा./स्था-2/न्या.
जॉच/सि (जी.डी.) रमेश के./2025-2224

कार्यालय सेनानी, 21वीं वाहिनी
भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल
गृह मंत्रालय/भारत सरकार
पत्रालय : पंथाचौक, श्रीनगर (ज.व क.)

दिनांक 01/04/25

नोटिस

दल संख्या 070271402 कॉस्टेबल (जी.डी.) रमेश काराबन्नावर, पुत्र श्री आदिवेप्पा काराबन्नावर, गांव-चंदनहोजुर, डाकघर-तरीहाल, पुलिस स्टेशन-हीरेबागेवाड़े, जिला-बेलगांव, राज्य-कर्नाटक, पिन कोड-590020 को सूचित किया जाता है कि आप दिनांक 06.02.2025 (पूर्वा.) से बिना किसी सक्षम अधिकारी की अनुमति एवं पूर्व सूचना के अवकाश से अनुपस्थित चल रहे है। 21वीं वाहिनी के पंजीकृत कार्यालय ज्ञापन संख्या 873-74 दिनांक 10.02.2025 एवं 1190-93 दिनांक 23.02.2025 के तहत आपको बार-बार ड्यूटी पर आमद देने के लिए निर्देशित किया गया परन्तु आपने अभी तक अपनी आमद नहीं दी है। 21वीं वाहिनी के आदेश संख्या 1991-2007 दिनांक 24.03.2025 के तहत आपको दिनांक 06.02.2025 (पूर्वा.) से '' भगौड़ा'' घोषित किया जा चुका है तथा अब '' सेवा से बर्खास्त'' किया जाना प्रस्तावित है।

2. अतः दल संख्या 070271402 कॉस्टेबल (जी.डी.) रमेश काराबन्नावर पुत्र श्री आदिवेप्पा काराबन्नावर को इस नोटिस के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि आप अपने बचाव पक्ष में कोई अभ्यावेदन प्रस्तुत करना चाहते है तो इस नोटिस के समाचार पत्र में प्रकाशित होने के 30 दिन के अन्दर 21वीं वाहिनी भा.ति.सी.पु. बल, पंथाचौक, श्रीनगर (जवक) में उपस्थित होकर अपना बचाव पक्ष प्रस्तुत करें अन्यथा यह समझ लिया जायेगा कि आप भा.ति.सी.पु. बल में सेवा करने के इच्छुक नहीं है तथा तदानुसार आपको '' सेवा से बर्खास्त'' किये जाने के आदेश पारित कर दिये जाएगें।

कमाण्डेंट
21वीं वाहिनी भा.ति.सी.पु. बल

CBC 19110/11/0003/2526

अदालत ने एमयूडीए भूमि आवंटन मामले में 'बी रिपोर्ट' के खिलाफ ईडी की याचिका पर फैसला टाला

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

यह मामला एमयूडीए द्वारा भूखंड के आवंटन में कथित अनियमितताओं से संबंधित है, जिसमें मुख्यमंत्री सिद्दरामय्या पर अपने पद का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया गया है। आरोप लगाया गया है कि आवासीय भूखंडों का आवंटन नियमों और प्रक्रियाओं का उल्लंघन करके किया गया।

बेंगलूरु। बेंगलूरु में जनप्रतिनिधियों के लिए एक विशेष अदालत ने मैसूरु शहरी विकास प्राधिकरण (एमयूडीए) भूखंड आवंटन मामले में कर्नाटक लोकायुक्त पुलिस द्वारा दाखिल 'बी रिपोर्ट' के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की याचिका पर अपना आदेश मंगलवार को टाल दिया। रिपोर्ट कहा गया है कि मुख्यमंत्री सिद्दरामय्या ने कोई गलत काम नहीं किया है। हालांकि, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) और शिकायतकर्ता स्नेहमयी कृष्णा ने रिपोर्ट को चुनौती देते हुए आपत्ति दर्ज करायी है और एक गहन जांच का अनुरोध किया है।

सुनवायी के दौरान पीठासीन न्यायाधीश संतोष गजानन भट ने कहा कि लोकायुक्त पुलिस द्वारा पूरी जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने के बाद ही 'बी रिपोर्ट' पर निर्णय लिया जाएगा। परिणामस्वरूप, अदालत ने कार्यवाही स्थगित कर दी और अगली सुनवाई सात मई के लिए निर्धारित की। अदालत ने एजेंसी द्वारा किए गए अनुरोध के बाद लोकायुक्त पुलिस को अपनी जांच जारी रखने की अनुमति भी दे दी। इससे पहले, लोकायुक्त पुलिस की मैसूरु डिवीजन ने सिद्दरामय्या और तीन अन्य के खिलाफ आरोपों की जांच के आधार पर एक प्रारंभिक रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। हालांकि, अदालत ने कहा कि जांच सिर्फ चार व्यक्तियों तक सीमित नहीं होनी चाहिए और पुलिस को इसमें शामिल सभी लोगों की जांच करने तथा एक व्यापक रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया।

यह मामला एमयूडीए द्वारा भूखंड के आवंटन में कथित अनियमितताओं से संबंधित है, जिसमें मुख्यमंत्री सिद्दरामय्या पर अपने पद का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया गया है। आरोप लगाया गया है कि आवासीय भूखंडों का आवंटन नियमों और प्रक्रियाओं का उल्लंघन करके किया गया, जिससे सिद्दरामय्या के परिवार के सदस्यों सहित कुछ व्यक्तियों को संभावित रूप से लाभ हुआ। कार्यकर्ता स्नेहमयी कृष्णा द्वारा दायर की गई शिकायत के बाद लोकायुक्त ने जांच शुरू की।

बाद में एक 'बी रिपोर्ट' दायर की गई - जो दर असल एक क्लोजर रिपोर्ट थी, जिसमें गलत काम किये जाने के कोई सबूत नहीं होने का संकेत दिया गया था। इसमें कहा गया है कि आरोपियों के खिलाफ मामला चलाने के लिए पर्याप्त सामग्री नहीं है। हालांकि, अब इस रिपोर्ट को चुनौती दी गई है। ईडी और शिकायतकर्ता दोनों ने दलील दी है कि मामले के महत्वपूर्ण पहलुओं को नजरअंदाज किया गया या ठीक तरह से जांच नहीं की गई।

ट्रक चालकों की हड़ताल शुरू

बेंगलूरु। कर्नाटक में ट्रक चालकों के एक प्रमुख संघ ने ईंधन की कीमतों में वृद्धि और टोल संबंधी मुद्दों के खिलाफ सोमवार और मंगलवार की मध्यरात्रि से अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी है, जिससे कर्नाटक में और राज्य के बाहर माल परिवहन करने वाले ट्रकों का परिचालन ठप हो गया है। फेडरेशन ऑफ कर्नाटक स्टेट लॉरी ओनर्स एंड एजेंट्स एसोसिएशन' ने ईंधन की कीमतों में बढ़ोतरी और टोल प्लाजा पर कथित उत्पीड़न की निंदा करते हुए यह हड़ताल शुरू की है। हड़ताल शुरू होने के कारण ट्रक सड़कों से नदारद हैं। ट्रक चालकों की हड़ताल से राज्य में आर्थिक गतिविधियां बुरी तरह प्रभावित हो सकती हैं, जिसके परिणामस्वरूप आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि हो सकती है। 'ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस' के अध्यक्ष हरीश सभरवाल ने 'पीटीआई-भाषा' को बताया कि शुरुआती प्रतिक्रिया से पता चलता है कि आंदोलन सफल हो रहा है। उन्होंने कहा कि न तो भारत के किसी भी हिस्से से ट्रक कर्नाटक में प्रवेश करेंगे और न ही राज्य से ट्रक बाहर जाएंगे।

भारत सरकार, अंतरिक्ष विभाग
सामानव अंतरिक्ष उड़ान केन्द्र (एचएसएफसी)
निर्माण एवं रखरखाव समूह (सीएमजी), अंतरिक्ष भवन,
बेंगलूरु - 560094, फोन : (080) 2217 2614/2613

ई-निविदा सूचना

भारत के राष्ट्रपति की ओर से निम्नलिखित कार्य के लिए ई-निविदा के माध्यम से ऑनलाइन मद दर निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं।

क्र स.	कार्य का नाम एवं एन.आई.टी.सं.	निविदा हेतु अनुमानित लागत	पूर्ण करने की अवधि	निविदा दस्तावेज़ डाउनलोड करने की अवधि	अंतमि तिथि एवं प्रस्तुत करने की अवधि	निविदा का दिनांक	बयाना राशि जमा (ई.एम.डी.)
01.	सुरक्षा भवन से एचएसएफसी, देवनहल्ली, बेंगलूरु में प्रस्तावित कियोस्क तक बाहरी केबलिंग कार्य प्रदान करना HSFC/CMG/MM/E/145/2025-26, दिनांक : 15.04.2025	₹ 7.55 लाख	02 माह	16.04.2025 को (11.00 बजे) से 23.04.2025 को (23.30 बजे) तक	25.04.2025 को 11.00 बजे तक	25.04.2025 को 11.30 बजे	₹. 15,100/-

निविदा दस्तावेज़ को, www.tenderwizard.com/ISRO वेबसाइट पर टेंडर विजाड में पंजीकरण करते हुए और निविदा प्रक्रम शुल्क का भुगतान कर डाउनलोड किया जा सकता है। विक्रता पंजीकरण की विधि उपरोक्त वेबसाइट में दर्शाई गई है। निविदा प्रक्रम शुल्क ई-गेटवे के जरिए मेसर्स् आई.टी.आई. लि. को देय है।

इच्छुक निविदाकार अधिक जानकारी के लिए www.isro.gov.in वेबसाइट पर निविदा आमंत्रित करती विस्तृत सूचना (एन.आई.टी.) को देख सकते हैं और क्रय दस्तावेज़ के लिए www.tenderwizard.com/ISRO वेबसाइट देखें।

ह/- प्रमुख सीएमडी, सीएमजी, एचएसएफसी

कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री खाचरियावास समेत अन्य के कई परिसर पर ईडी की छापेमारी

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

जयपुर। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मंगलवार को 48,000 करोड़ रुपये के पीएसीएल पोंजी धोखाधड़ी से जुड़े धन शोधन मामले की जांच के तहत कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास तथा कुछ अन्य के कई परिसर पर छापेमारी की। आधिकारिक सूत्रों ने यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि ईडी द्वारा खाचरियावास के जयपुर स्थित घर और एक अन्य व्यक्ति कुलवंत सिंह के घर समेत करीब 15 परिसर की तलाशी ली जी रही है। ईडी के साथ केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) की एक सुरक्षा टीम तैनात की गई है।

उल्लेखनीय है कि 55 वर्षीय कांग्रेस नेता खाचरियावास, पूर्ववर्ती अशोक गहलोत सरकार में परिवहन, खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री रह चुके हैं। वे सिविल लाइंस (जयपुर) सीट से विधायक रहे हैं। वे पूर्व उपराष्ट्रपति भैरों सिंह शेखावत के भतीजे हैं। यहां अपने पैतृक घर के बाहर संवाददाताओं से बातचीत में खाचरियावास ने कहा कि ईडी की कार्रवाई राजनीति से प्रेरित है, क्योंकि वह (राज्य की मौजूदा भाजपा सरकार) के खिलाफ बोलते रहते हैं। उन्होंने कहा कि उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया है और वह ईडी से डरते नहीं हैं। धन शोधन मामले की जांच वर्ष 2015 में शुरू की गई। यह मामला पीएसीएल इंडिया लिमिटेड, पीजीएफ लिमिटेड, पीएसीएल के दिवंगत प्रवर्तक निर्मल सिंह भंगू और अन्य के खिलाफ निवेशकों को धोखा देने के लिए धोखाधड़ीपूर्ण निवेश योजनाएं चलाने के मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की ओर से दर्ज प्राथमिकी पर आधारित है।

ईडी के अनुसार, इन योजनाओं के माध्यम से, पीएसीएल और उसके निदेशकों ने निवेशकों को लगभग 48,000 करोड़ रुपये का धोखा दिया। सूत्रों ने दावा किया कि कथित अपराध की आय के खाचरियावास से जुड़ी संस्थाओं सहित अन्य संस्थाओं को प्राप्त होने का संदेह है। ईडी की छापेमारी की खबर सामने आने पर खाचरियावास के समर्थक उनके आवास के बाहर एकत्र हो गए और नारे लगाने लगे।

खाचरियावास ने संवाददाताओं से कहा, वे परिसर की तलाशी के लिए नोटिस लेकर आए हैं। उन्होंने किसी कंपनी से संबंधित नोटिस नहीं दिया है। देश में कहीं भी परिसर की तलाशी ली जा सकती है, यह उनका अधिकार है। मैं न तो डरता हूं और न ही घबराता हूं। उन्होंने कहा, अगर कोई मुद्दा है, तो मैं जवाब दूंगा। मेरी ओर से छह वकील हैं। ईडी ने इस मामले में मार्च में भंगू की बेटी बरिंदर कौर, उसके पति हरसतिंदर पाल सिंह हेयर और उसके करीबी सहयोगी मनोज कुमार के खिलाफ छापेमारी की थी। इन छापेमारी से पहले एजेंसी ने हेयर को गिरफ्तार किया था। भंगू की पिछले साल अगस्त में मौत हो गई थी। एजेंसी ने ऑस्ट्रेलिया में 462 करोड़ रुपये की दो अचल संपत्तियों सहित 706 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की है और पीएसीएल, भंगू और अन्य के खिलाफ दो आरोपपत्र दायर किए हैं।

खाचरियावास ने दावा किया कि ईडी उन्हें डराने के लिए उनके घर की तलाशी लेने आई थी। उन्होंने कहा, भाजपा अहंकारी है। केंद्र में उनकी 11 साल से सरकार है, राजस्थान में भी उनकी सरकार है। मैं उनके खिलाफ बोलता रहा हूं, इसलिए उन्होंने यह कार्रवाई की है, लेकिन मैं डरने वाला नहीं हूं।

खाचरियावास ने आरोप लगाया कि ईडी बिना किसी कारण के कार्रवाई करती है। उन्होंने कहा, उन्होंने हमारे नेता राहुल गांधी को बुलाया। जब वे कोई कारण बताएंगे, तो मैं जवाब दूंगा। अभी तक ईडी ने तलाशी का कोई कारण नहीं बताया है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार को ईडी के जरिए राजनीति नहीं करनी चाहिए। पूर्व मंत्री ने कहा कि उनका किसी कंपनी से कोई लेना-देना नहीं है। संघीय जांच एजेंसी इस मामले में अन्य स्थानों पर स्थित कुछ अन्य परिसर की तलाशी ले रही है। खाचरियावास ने कहा कि वह संयुक्त परिवार में रहते हैं और इस तरह की हरकतें पूरे परिवार को परेशान करती हैं। उन्होंने कहा, मैं अब नया घर बनाऊंगा, उसका नाम 'क्रांति हाउस' रखूंगा और वहीं से विद्रोह शुरू करूंगा, ताकि मेरे परिवार को कोई परेशानी न हो। राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने खाचरियावास के खिलाफ कार्रवाई को राजनीतिक बदला करार दिया।

जूली ने 'एक्स' पर लिखा, पूर्व मंत्री एवं वरिष्ठ कांग्रेस नेता प्रताप सिंह खाचरियावास मुखरता से भाजपा सरकार के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। इसी से डरकर भाजपा सरकार ने केन्द्रीय एजेंसियों को उनके घर भेज दिया है। 2020 में भी उन्हें इसी तरह परेशान करने का प्रयास किया गया था। उन्होंने लिखा,प्रताप सिंह खाचरियावास के खिलाफ राजनीतिक प्रतिशोध की भावना से की जा रही यह कार्रवाई निंदनीय है।'

दक्षिण पश्चिम कमान ने मनाया अपना 21वाँ स्थापना दिवस

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

जयपुर। भारतीय सेना की 15 अप्रैल 2005 को स्थापित हुई सप्त शक्ति कमान ने मंगलवार को राजस्थान की राजधानी जयपुर में अपना 21वां स्थापना दिवस मनाया। राजस्थान में सेना के जनसम्पर्क अधिकारी कर्नल अमिताभ शर्मा ने बताया कि सप्त शक्ति कमान भारतीय सेना की सातवीं और सबसे युवा कमान है, जिसने पिछले 21 वर्षों में सप्त शक्ति कमान ने सफलता की ऊंचाइयों को छूते हुए पश्चिमी सीमाओं पर मज़बूत सुरक्षा स्थापित की है। 'सर्वदा विजयी भव' के आदर्श वाक्य के साथ इस कमान ने न केवल देश की सीमाओं की सुरक्षा सुनिश्चित की है, बल्कि संचालन तैयारियों और व्यावसायिक गुणवत्ता के उच्चतम मानकों को भी प्राप्त किया है।

उन्होंने बताया कि यह मुख्य उपलब्धि सुदृढ़ प्रशिक्षण, नवीन तकनीकों को शामिल करने और नवीन तकनीकी एवं सामरिक प्रक्रियाओं के विकास से संभव हुई है। इन्हीं प्रयासों से, यह कमान भविष्य के युद्धक्षेत्र की चुनौतियों से प्रभावी रूप से निपटने के लिए भविष्य के लिये तैयार, प्रौद्योगिकी संचालित घातक एवं चुस्त सेना के रूप में उभरी है। कर्नल शर्मा ने बताया कि स्थापना दिवस के अवसर पर प्रेरणा स्थल पर श्रद्धांजलि समारोह का आयोजन किया गया जिसमें देश की सेवा में अपने प्राण न्योछावर करने वाले वीर सैनिकों को पुष्पांजलि अर्पित की गई।

यह आयोजन कमान की मूल भावना में निहित वीरता और निःस्वार्थता का एक मार्मिक स्मरण था। उन्होंने बताया कि इस अवसर पर, लेफ्टिनेंट जनरल मनजिंदर सिंह, आर्मी कमांडर, सप्त शक्ति कमान ने सभी रैंक, पूर्व सैनिकों, रक्षा कर्मचारियों और उनके परिवारों को शुभकामनाएं और बधाई दी। इस अवसर पर ले. जनरल सिंह ने सम्बोधित करते कमान की इस गौरवशाली यात्रा में योगदान देने वाले सभी भूतपूर्व और वर्तमान सैनिकों के निस्वार्थ समर्पण, साहस और बलिदान की सराहना की साथ ही भारतीय सेना की सबसे युवा कमान को इतने कम समय में विशिष्ट पहचान ,गौरवपूर्ण विरासत स्थापित करने और सफलता के शिखर पर पहुँचाने में उनके अहम योगदान को सराहा।

अपने संबोधन में ले. जनरल मनजिंदर सिंह ने कहा कि कमान ने सेना की दूरदृष्टि के अनुरूप स्वयं को ढालते हुए, नई रणनीतियों को अपनाकर और बहु क्षेत्र संचालनर में समन्वय के माध्यम से अपनी संचालन तैयारियों को सशक्त बनाने की दिशा में उल्लेखनीय प्रगति की है। उन्होंने नयी तकनीकों के समावेश की आवश्यकता पर बल देते हुए कमान द्वारा किए गए प्रयासों एवं आधारभूत ढांचागत विकास से जुड़ी विभिन्न पहलों को रेखांकित किया।

ले. जनरल सिंह ने कहा कि सेवानिवृत्त सैनिक और वीर नारियाँ कमान की निरंतर प्रेरणा और शक्ति रही हैं और उनका कल्याण कमान की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने उनके कल्याण एवं सशक्तीकरण के लिये अब तक की गई पहलों और भविष्य में प्रस्तावित योजनाओं के बारे में भी जानकारी दी । ले. जनरल सिंह ने कमान के प्रत्येक सदस्य से राष्ट्र की संप्रभुता की रक्षा के लिये स्वयं को पुनः समर्पित करने का आह्वान करते हुए नयी चुनौतियों का व्यावसायिकता एवं साहस के साथ सामना करने का संदेश दिया। उन्होंने आग्रह किया कि सब एक साथ मिलकर, एक ही उद्देश्य और दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ें और हमारे लोकतंत्र की नींव को मजबूत करें और कमान के आदर्श 'सर्वदा विजयी भव' का दृढ़ता से पालन करें।

महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय ने अरुण योगीराज को दी पीएचडी की मानद उपाधि

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

जयपुर। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने कहा कि कला और कलाकारों का सम्मान भारतीय संस्कृति की परम्परा रही है। शिल्पी अरुण योगीराज को पीएचडी की पहली मानद उपाधि प्रदान कर महाराजा गंगासिंह राज्यपाल ने मंगलवार को महाराजा गंगासिंह विश्वविद्यालय में अरुण योगीराज के मानद उपाधि सम्मान कार्यक्रम के दौरान यह बात कही।

राज्यपाल ने कहा कि योगीराज इस उपाधि के लिए सर्वथा योग्य हैं। योगीराज ने अत्यंत कम उम्र में शिल्प की गहरी साधना की है। उन्होंने कहा कि अयोध्या के श्रीराम मंदिर में योगीराज द्वारा बनाई गई मूर्ति जीवंत है। उन्होंने योगीराज के कला कौशल्य की सराहना की और कहा कि हमारे देश में हजारों वर्षों से अच्छी मूर्तियां बनाने की परंपरा रही है।

आज भी देश और प्रदेश में ऐसे कलाकार हैं, जिनकी कला को बेहतर पहचान मिली है। राज्यपाल ने कहा कि योगीराज सिर्फ एक मूर्तिकार नहीं बल्कि भारतीय शिल्प कला की समृद्ध परंपरा के जीवंत प्रतीक हैं। योगीराज ने मूर्तिकला की विरासत को अपनाया और इसे नई ऊंचाइयां दी।

राज्यपाल ने कहा कि योगीराज को दिए गए अभिनंदन पत्र को विश्वविद्यालय में भी प्रदर्शित किया जाए, जिससे युवा विद्यार्थियों को प्रेरणा मिले और वे भी इनका अनुसरण कर सकें। मानद उपाधि प्राप्त करने के पश्चात अरुण योगीराज ने कहा कि यह भारत की समृद्ध कला परंपरा का सम्मान है। उन्होंने कहा कि वह पांच पीढ़ियों से शिल्प की साधना कर रहे हैं।

महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय के कुलपति आचार्य मनोज दीक्षित ने कहा कि योगीराज ने लोह पथ पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस, केदारनाथ में आदि शंकराचार्य, अमरनाथ में नंदी की प्रतिमा भी बनाई। उन्होंने कहा कि योगीराज ऐसे ऋषि हैं, जिन्होंने अपनी शिल्पकला के माध्यम से सांस्कृतिक विरासत की संजीता और मूल्यों को विशेष पहचान दी है। इससे पहले राज्यपाल ने अरुण योगीराज को पीएचडी की मानद उपाधि प्रदान की।

देश को विकसित बनाने में भौतिक विकास के साथ बौद्धिक-चारित्रिक विकास की महत्ती भूमिका : राज्यपाल

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

जयपुर। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने कहा कि देश के विकास के लिए सड़क, भवन और पुल जैसे भौतिक संसाधनों की जरूरत होती है लेकिन देश सही मायनों में विकसित तब होता है, जब प्रत्येक नागरिक शारीरिक, बौद्धिक और चारित्रिक रूप से सशक्त होगा। उन्होंने युवाओं के कौशल्य विकास पर जोर दिया और अध्ययनशीलता के विकास का आह्वान किया। राज्यपाल बागड़े ने मंगलवार को राजस्थान पशु विज्ञान एवं पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय, बीकानेर के 8वें दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता करते हुए यह उद्गार व्यक्त किए। महाराजा गंगासिंह विश्वविद्यालय के मीरा बाई सभागार में आयोजित समारोह के दौरान राज्यपाल ने कहा कि गुरुकुल शिक्षा पद्धति में विद्यार्थी को शिक्षा के साथ कौशल विकास और चरित्र निर्माण की शिक्षा मिलती थी। आज भी शिक्षार्जन और डिग्री हासिल करने के साथ विद्यार्थी खेल, शारीरिक व्यायाम आदि गतिविधियों में भी भागीदारी निभाएं। उन्होंने विद्यार्थियों का आह्वान करते हुए कहा कि वे गुरु दक्षिणा के रूप में विश्वविद्यालय परिसर में एक-एक पौधा लगाएं और उसकी देखभाल करें। यह आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणादायी होगा।

राज्यपाल ने कहा कि हमारा देश पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान के क्षेत्र में आरम्भ से ही समृद्ध रहा है। ऋग्वैदिक काल में भी पशुपालन पूर्णतया विकसित था। अथर्ववेद में पशुओं की बीमारियों, आयुर्वेदिक दवाओं और बीमारियों के इलाज के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियां हैं। शालिहोत्र दुनिया के पहले ज्ञात पशु चिकित्सक थे। उनका लिखा ग्रंथ शालिहोत्र संहिता, पशु चिकित्सा पर महत्वपूर्ण ग्रंथ है। उन्होंने विश्वविद्यालय में यह ग्रन्थ उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए जिससे विद्यार्थियों को इनकी जानकारी हो सके। राज्यपाल ने कहा कि पशु चिकित्सा और विज्ञान के प्राचीन ज्ञान से नई पीढ़ी को अवगत करवाया जाए। उन्होंने कहा कि भारत विश्व का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश है। यहां गिर, साहीवाल और मुर्रा जैसी नस्लें उच्च गुणवत्ता का दुध देती हैं। इसके अलावा बकरी, भेड़ और मुर्गी पालन भी विकसित अवस्था में है। इस दिशा में और कार्य करने की जरूरत है। उन्होंने विश्वविद्यालय की गतिविधियों की सराहना की।

इस दौरान राज्यपाल ने विश्वविद्यालय के त्रैमासिक न्यूज़लेटर के नवीनतम अंक, विश्वविद्यालय की एक वर्ष की प्रगति पुस्तिका का लोकार्पण किया, विश्वविद्यालय में 2 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले अरुधंति कन्या छात्रावास का शिलान्यास किया। उन्होंने निजी महाविद्यालयों के एफिलेशन मैनेजमेंट सिस्टम, पुनर्निर्मित वेबसाइट और कार्मिकों की उपस्थिति के फेस रिकॉग्नेशन सिस्टम की शुरुआत की।

बैरवा ने 48वें राष्ट्रीय जनसंपर्क दिवस के पोस्टर का किया विमोचन

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

जयपुर। उपमुख्यमंत्री डॉ. प्रेमचंद बैरवा ने मंगलवार को 48वें राष्ट्रीय जनसंपर्क दिवस के पोस्टर का विमोचन किया। इस अवसर पर उन्होंने देश- प्रदेश के जनसंपर्क क्षेत्र के पेशेवरों को शुभकामनाएँ दीं और देश में सूचनात्मक एवं उत्तरदायी संप्रेषण को बढ़ावा देने में उनके प्रयासों की सराहना की। इस अवसर पर सूचना एवं जनसंपर्क आयुक्त सुनील शर्मा को भी 48वें राष्ट्रीय जनसंपर्क दिवस का पोस्टर भेंट किया।

उन्होंने कहा कि जनसंपर्क के माध्यम से समाज में सकारात्मक परिवर्तन संभव है और इस दिशा में कार्यरत सभी जनसंपर्क पेशेवरों की महत्वपूर्ण भूमिका है। इस दौरान जयपुर चैप्टर के अध्यक्ष वीरेंद्र पारीक, उपाध्यक्ष श्रीमती कविता जोशी एवं सचिव मनीष हूजा मौजूद रहे।

ऊँटनी का दूध अमृत तुल्य, ऊँटपालकों को मिले इसका उचित मूल्य : बागड़े

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

जयपुर। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने मंगलवार को बीकानेर स्थित भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के उष्ट्र अनुसंधान केन्द्र का अवलोकन किया। राज्यपाल ने यहां के उष्ट्र संग्रहालय का भ्रमण किया। यहां ऊँटों की विविध नस्लों, ऊँटों के बहुआयामी उपयोग, ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में ऊँटों के योगदान, उष्ट्र व्यवहार तथा लक्षण, उष्ट्र दुग्ध तथा उष्ट्र पर्यटन संबद्ध गतिविधियों की सामग्री का अवलोकन किया। बागड़े ने ऊँट के बाल, खाल व हड्डी से बने विभिन्न उत्पादों को देखा। इस दौरान राज्यपाल ने ऊंटनी के दूध से बनी लस्सी का स्वाद भी चखा। उन्होंने केन्द्र द्वारा ऊँटनी के दूध पाउडर की सराहना की। राज्यपाल ने उष्ट्र सवारी स्थल का भ्रमण किया तथा उष्ट्र पालकों से संवाद भी किया। राज्यपाल ने प्रदेश में ऊँटनी के दूध की आपूर्ति के बारे में जानकारी ली और कहा कि राजस्थान को-ऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन के माध्यम से ऊँटनी के दूध को और अधिक बढ़ावा दिया जाना चाहिए, जिससे यह उपभोक्ताओं के लिए सुलभ हो सके। उन्होंने केन्द्र के अनुसंधान कार्यों के बारे में जाना और उष्ट्र संरक्षण व विकास के लिए वैज्ञानिकों को प्रोत्साहित किया।

लंबित जांच प्रकरणों के निस्तारण को लेकर शिक्षामंत्री ने दिए सख्त निर्देश

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

जयपुर। राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद के सभागार में मंगलवार को शिक्षा मंत्री मदन दिलावर की अध्यक्षता में एक अहम बैठक आयोजित की गयी। निदेशालय माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर की ओर से आयोजित बैठक में 16-17 सीसीए, एसपी प्रकरण सहित अन्य लंबित जांच के संबंध में चर्चा की गयी। चर्चा में वर्ष 1989 से लेकर वर्ष 2025 तक के 16 सीसीए, 17 सीसीए, 17 सीसीए न्यून परीक्षा परिणाम प्रधानाचार्य, 17 सीसीए न्यून परीक्षा परिणाम व्याख्याता और राज्य स्तर पर 16 सीसीए के लंबित एवं विचाराधीन प्रकरणों पर विस्तार से चर्चा की गयी।

शिक्षा मंत्री ने अधिकारियों एवं पदाधिकारियों को पेंडिंग मामलों के शीघ्र निस्तारण के लिए निर्देशित किया। साथ ही विभाग की ओर से आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए। इस अवसर पर विशिष्ठ शासन सचिव विश्व मोहन शर्मा, राज्य परियोजना आयुक्त एवं निदेशक, समग्र शिक्षा राजस्थान श्रीमती अनुपमा जोरवाल, निदेशक प्राथमिक शिक्षा सीताराम जाट, संयुक्त शासन सचिव मनीष गोयल सहित अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।

इस मानसून ईसरदा बांध में होगा जल संग्रहण, बांध का 90 प्रतिशत कार्य पूर्ण

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा प्रदेश में अंतिम छोर तक सुचारू पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित कर रहे हैं। शर्मा के निर्देशन के सवाई माधोपुर और दौसा जिले में पेयजल आपूर्ति की दृष्टि से महत्वपूर्ण ईसरदा बांध का निर्माण कार्य मिशन मोड पर किया जा रहा है। बांध के निर्माण का 90 प्रतिशत कार्य पूरा हो चुका है। बांध के पियर्स एवं गेटों का कार्य पूरा हो चुका है। मिट्टी के बांध का आंशिक कार्य ही शेष है। जल संसाधन विभाग द्वारा जुलाई माह तक निर्माण कार्य पूर्ण कराने के हरसंभव प्रयास किए जा रहे हैं। इससे आगामी मानसून के दौरान बांध में जल संग्रहित किया जा सकेगा। इसके बाद दौसा के 1079 ग्राम व 5 शहरों तथा सवाई माधोपुर के बौंली शहर तथा 177 ग्रामों व एक शहर में पेयजल की सुचारू आपूर्ति हो सकेगी।

यह परियोजना जलसंकट समाधान के साथ-साथ बीसलपुर बांध के अधिशेष पानी और बनास नदी के बारिश के जल का कुशल प्रबंधन भी सुनिश्चित करेगी। साथ ही, ईसरदा बांध से राम जल सेतु लिंक परियोजना (संशोधित पीकेसी-ईआरसीपी लिंक परियोजना) के तहत रामगढ़ बांध, बुचारा, छितोली इत्यादि बांधों में पेयजल के लिए आपूर्ति हो सकेगी। इससे बांधों के आसपास के क्षेत्र एवं जयपुर जिले को भी पानी मिल सकेगा। ईसरदा बांध बीसलपुर बांध के डाउनस्ट्रीम में ग्राम बनेठा (तहसील उनियारा जिला टोंक) के पास बनास नदी पर बनाया जा रहा है। इसका निर्माण दो चरणों में किया जाना निर्धारित है।

प्रथम चरण में डैम का निर्माण पूर्ण भराव स्तर आरएल 262.0 मी (भराव क्षमता 10.77 टीएमसी) तक पूर्ण किया जाएगा। इसमें पानी का भंडारण आरएल 256.0 मी भराव क्षमता (3.24 टीएमसी) तक ही किया जाना है। द्वितीय चरण में बांध में पूर्ण भराव क्षमता आरएल 262.0 मीटर तक पानी संग्रहित हो सकेगा। परियोजना के प्रथम चरण की संशोधित प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति 1038.65 करोड़ रुपए की दी गई, जिससे कार्य प्रगतिरत है। बांध निर्माण में ओवर फ्लो वाले भाग में स्पिलवेय ब्रिज में स्लैब निर्माण का कार्य प्रगतिरत है। अभी तक 28 के विरूद्ध 28 स्लैब डाली जा चुकी है। साथ ही, 28 पियर्स के विरूद्ध 28 पियर्स वांछित ऊंचाई तक पूर्ण किए जा चुके हैं। बांध में 84 गर्डर के विरूद्ध 84 गर्डर लॉन्च किए गए है। बांध में 28 ब्लॉक एप्रेन के विरूद्ध 22 ब्लॉक एप्रेन का निर्माण किया जा चुका है। बांध में 28 पावर पैक रूम के विरूद्ध 28 में पावर पैक रूम और 28 रेडियल गेट विरूद्ध 28 रेडियल गेट का निर्माण हो गया है। बांध में 56 हाईड्रोलिक सिंलेडर के विरूद्ध 56 हाईड्रोलिक सिंलेडर भी लगाए जा चुके हैं। मिट्टी के बांध का कार्य लगभग 82.08 प्रतिशत पूर्ण हो चुका है। मुख्य बांध का कार्य लगभग 90 प्रतिशत पूर्ण हो चुका है।

पश्चिम बंगाल में हिंसा पर योगी आदित्यनाथ ने कहा,

दंगाइयों का एकमात्र इलाज ‘डंडा’ है

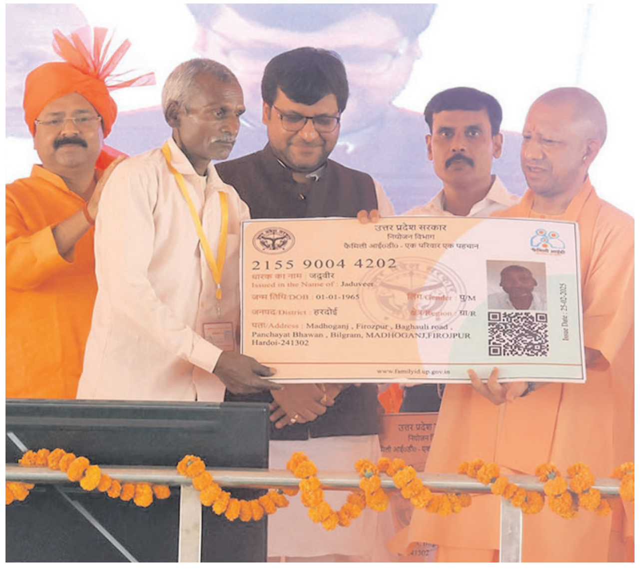

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

हरदोई/भाषा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में जारी हिंसा पर मंगलवार को कहा कि दंगाइयों का इलाज सिर्फ ‘डंडा’ है और ‘डंडे’ के बिना वे नहीं मानेंगे।

योगी आदित्यनाथ ने आरोप लगाया कि बंगाल जल रहा है लेकिन मुख्यमंत्री ममता बनर्जी चुप्पी साधे हुए हैं और दंगाइयों को शांतिदूत कहती हैं। उन्होंने यह भी कहा कि इन दंगाइयों का इलाज ‘डंडा’ है और ‘डंडे’ के बिना वे नहीं मानेंगे। योगी ने कहा, लातों के भूत बातों से कहा मानने वाले हैं? उन्होंने मंगलवार को हरदोई में 650 करोड़ रुपए की 729 विकास योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया।

मुख्यमंत्री ने कहा, आप देख रहे हैं कि बंगाल जल रहा है, उस राज्य की मुख्यमंत्री चुप हैं और ‘दंगाइयों को शांतिदूत’ कहती हैं। अरे लातों के भूत बातों से कहां मानने वाले हैं? लेकिन धर्मनिरपेक्षता के नाम पर दंगाइयों को दंगे करने की पूरी छूट दे दी गई है। सरकार चुप है। इस तरह की अराजकता पर नियंत्रण होना चाहिए। पूरा मुर्शिदाबाद पिछले एक हफ्ते से जल रहा है। उन्होंने कहा, ‘‘हम प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आभारी हैं, जिन्होंने वक्फ संशोधन विधेयक पारित करवाया और इस अधिनियम के माध्यम से गरीबों की जमीन और सार्वजनिक भूमि की डकैती पर लगाम लगाई। अब जो जमीन वापस आएगी, उस पर अस्पताल, गरीबों के लिए घर, स्कूल, विश्वविद्यालय और निवेश के लिए भूमि बैंक बनाए जाएंगे। लेकिन अब किसी को भी जमीन हड़पने और गुंडागर्दी करने की इजाजत नहीं दी जाएगी।’’ उन्होंने कहा, ‘‘इसलिए ये लोग परेशान हैं, क्योंकि जमीन के नाम पर जो लूट होती थी, वह बंद होने जा रही है। उन्हें इस बात की चिंता है कि उनके गुंडे बेरोजगार हो जाएंगे, जो पहले जनता को लूटते थे। आदित्यनाथ ने कहा, ‘‘उन्हें डर है कि अगर उनके गुंडे भस्मासुर बन गए तो वे (गुंडे) उन्हें लूटना शुरू कर देंगे, उन्होंने जो अपार संपत्ति जमा की है, वह लूट ली गई है। इसलिए वक्फ के नाम पर वे लोगों को बेवकूफ बनाने और उन्हें गुमराह करने का काम कर रहे हैं।’’ हिंदू धर्म में भस्मासुर एक राक्षस है, जिसे यह शक्ति दी गई थी कि वह जिस किसी के सिर को अपने हाथ से छूएगा वह तुरंत जलकर राख (भस्म) हो जाएगा।

आदित्यनाथ ने कहा, मैं वहां की अदालत को धन्यवाद देना चाहता हूं, जिसने वहां केंद्रीय बलों की तैनाती की अनुमति दी और अल्पसंख्यक हिंदुओं की सुरक्षा के लिए कदम उठाए।

बंगाल सरकार को वक्फ अधिनियम के विरोध में हिंदुओं पर हो रहे ‘जिहादी’ हमले रोकने चाहिए : विहिप

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

कोलकाता/भाषा। विश्व हिंदू परिषद ने पश्चिम बंगाल प्रशासन से वक्फ अधिनियम से संबंधित विरोध प्रदर्शनों के दौरान राज्य के कुछ हिस्सों में हिंदुओं और उनकी संपत्तियों पर किए जा रहे हमलों को तत्काल रोके जाने की मंगलवार को अपील की तथा पीड़ितों के लिए मुआवजे की मांग की। विहिप ने कहा कि यदि राज्य में कहीं और ऐसी घटनाएं दोहराई जाती हैं तो केंद्र का हस्तक्षेप आवश्यक हो जाएगा।

विहिप के राष्ट्रीय महासचिव (संगठन) मिलिंद परांडे ने सिलीगुड़ी में पत्रकारों से बात करते हुए राज्य में तृणमूल कांग्रेस के दो मंत्रियों–सिद्दीकुल्ला चौधरी और फिरहाद हकीम–के कथित बयानों की आलोचना की और उन्हें ‘‘भड़काऊ एवं असंवेदनशील’’ करार दिया। मुर्शिदाबाद जिले के धुलियान इलाके में ‘‘जिहादी उपद्रवियों’’ के हमले से बचने के लिए बंगाली हिंदुओं का घरों से भागकर मालदा जिले में शरण लेना ‘‘अतीत में जम्मू–कश्मीर से हुए कश्मीरी पंडितों के पलायन’’ की याद दिलाता है। उन्होंने कहा पश्चिम बंगाल सरकार को सुनिश्चित करना चाहिए कि ‘‘वक्फ (संशोधन) अधिनियम विरोधी किसी भी आंदोलन के दौरान’’ सिलीगुड़ी में या राज्य के अन्य स्थानों पर कानून–व्यवस्था खराब न हो।

फर्जी पासपोर्ट गिरोह: ईडी ने बंगाल में कई जगहों पर छापेमारी की

कोलकाता/भाषा। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने फर्जी पासपोर्ट गिरोह की जांच के सिलसिले में पश्चिम बंगाल के कई स्थानों पर मंगलवार को छापेमारी की। एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। अधिकारी ने बताया कि कोलकाता के बेकबागान इलाके के अलावा उत्तर 24 परगना जिले के बिराटी, –नदिया जिले के गेदे और पांच अन्य स्थानों पर छापेमारी की जा रही है। ईडी के एक अधिकारी ने कहा, ‘‘तलाश अभियान जारी है। घोटाले (फर्जी पासपोर्ट) में शामिल एजेंट की कॉन्टेक्ट सूचियों से (छापे के लिए) स्थानों की पहचान की गई।’’ कोलकाता पुलिस ने इससे पहले फर्जी पासपोर्ट गिरोह में कथित संलिप्तता के लिए एक सेवानिवृत्त उपनिरीक्षक सहित कम से कम 10 लोगों को गिरफ्तार किया था। पुलिस के सूत्रों ने बताया कि कोलकाता पुलिस ने मार्च में शहर की एक अदालत में आरोपपत्र दाखिल किया था। आरोपपत्र में नामजद 130 लोगों में से 10 भारतीय हैं और बाकी पड़ोसी देश बांग्लादेश के हैं।

सोनिया, राहुल के खिलाफ आरोप पत्र बदले की राजनीति और डराने-धमकाने की कोशिश: कांग्रेस

नई दिल्ली/भाषा। कांग्रेस ने मंगलवार को आरोप लगाया कि उसके शीर्ष नेताओं सोनिया गांधी और राहुल गांधी तथा कुछ अन्य लोगों के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा आरोप पत्र दाखिल किया जाना प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह द्वारा की गई बदले की राजनीति और डराने–धमकाने की कोशिश के अलावा कुछ नहीं है। पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने यह भी कहा कि इस मामले में कांग्रेस और उसका नेतृत्व चुप बैठने वाला नहीं है। ईडी ने नेशनल हेराल्ड मामले में धनशोधन के आरोप में कांग्रेस नेता सोनिया गांधी, राहुल गांधी और अन्य के खिलाफ आरोप–पत्र दाखिल किया है। विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने ने नौ अप्रैल को दाखिल आरोप–पत्र के संज्ञान के महत्वपूर्ण बिंदुओं पर पड़ताल की और सुनवाई की अगली तारीख 25 अप्रैल निर्धारित की। रमेश ने ‘एक्स’ पर पोस्ट किया, ‘‘नेशनल हेराल्ड की संपत्तियों को ज़ब्त करना कानून के शासन का मुखौटा लगाकर किया गया एक राज्य प्रायोजित अपराध है।’’ उन्होंने आरोप लगाया कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी और कुछ अन्य लोगों के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल करना, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री द्वारा की गई बदले की राजनीति और डराने–धमकाने की कोशिश के अलावा कुछ नहीं है।

पुणे के व्यवसायी की बिहार में अपहरण के बाद हत्या, कई संदिग्ध हिरासत में

पुणे/भाषा। पुणे के 55 वर्षीय व्यवसायी का पटना हवाई अड्डे के बाहर से कथित तौर पर अगवा कर लिया गया और उनकी हत्या कर दी गई। पुलिस ने मंगलवार को यह जानकारी दी। पटना से लगभग 50 किलोमीटर दूर जहानाबाद जिले में लक्ष्मण शिंदे का शव मिलने के बाद पुलिस ने पूछताछ के लिए आसपास के गांवों से कई संदिग्धों को हिरासत में लिया है। पुणे के खेड़शिवपुर स्थित सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग बियरिंग कंपनी के मालिक शिंदे 11 अप्रैल को विमान से पटना पहुंचे थे। रात करीब 8:30 बजे उन्होंने अपनी बेटी को संदेश भेजा कि वह झारखंड जा रहे हैं। इसके बाद उनसे कोई संपर्क नहीं हो सका। पुणे के पुलिस उपायुक्त (जोन 3) संभाजी कदम ने बताया कि जब परिवार शिंदे से संपर्क नहीं कर सका तो उन्होंने 12 अप्रैल को कोथरूड पुलिस थाने में गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई। कदम ने बताया, इसके बाद पुणे पुलिस की एक टीम को जांच के लिए पटना भेजा गया।

बोलनगीर में बीजू पटनायक की मूर्ति को आग लगायी गयी

भुवनेश्वर/भाषा। ओडिशा के बोलनगीर जिले के पटनागढ़ कस्बे में मंगलवार को पूर्व मुख्यमंत्री बीजू पटनायक की एक मूर्ति को आग लगा दी गयी। यह जानकारी पुलिस ने दी।

बीजू जनता दल (बीजद), भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (भाकपा) और अन्य वाम दलों ने घटना की निंदा की। पुलिस महानिरीक्षक (उत्तरी रेंज) हिमांशु कुमार लाल ने बताया कि मूर्ति को आग लगाने के मामले में एक व्यक्ति को हिरासत में लिया गया है। उन्होंने बताया कि व्यक्ति मानसिक रूप से अस्थिर प्रतीत हो रहा है।

वरिष्ठ बीजद नेता प्रमिला मलिक ने विभिन्न स्थानों पर बीजू पटनायक की मूर्ति पर बढ़ते हमलों के लिए राज्य सरकार की आलोचना की। पूर्व मंत्री एवं बीजद नेता प्रसन्ना आचार्य ने कहा, ‘‘यह केवल बीजू पटनायक की मूर्ति को आग लगाने की बात नहीं है, बल्कि ओडिशा के गौरव को भी आग लगायी गई है। कोई भी इस तरह की बर्बरता का समर्थन नहीं करेगा।’’

बीजद नेता संजय दास बर्मा ने कहा कि राज्य की भाजपा सरकार द्वारा बीजू पटनायक के जन्मदिन पांच मार्च को पंचायती राज दिवस के रूप में मनाना बंद किये जाने के बाद इस तरह की घटनाएं हो रही हैं।

बीजद नेता ने कहा कि यह हाल के दिनों में तीसरी ऐसी घटना है। उन्होंने कहा कि मार्च में शरारती तत्वों ने कटक जिले के महांगा इलाके में बीजू पटनायक की एक मूर्ति क्षतिग्रस्त कर दी थी। उन्होंने कहा कि एक अन्य घटना में पिछले महीने कटक शहर में बीजू पटनायक की मूर्ति का रंग बदल दिया गया था। बीजद नेता ने कहा कि बोलनगीर की घटना ऐसी तीसरी घटना है।

भाजपा सरकार जाने से पहले सब कुछ ‘जीरो’ कर देगी : अखिलेश

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

लखनऊ/भाषा। समाजवादी पार्टी (सपा) के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मंगलवार को आरोप लगाया कि केंद्र और उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेतृत्व वाली सरकार जनता को गुमराह करने के लिए पुरानी योजनाओं को नए नामों से पेश कर रही है।

सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में भाजपा पर निशाना साधते हुए यादव ने कहा, ‘‘‘जीरो’ होने से पहले हर तरफ ‘जीरो’ नजर आ रहा है।’’ उन्होंने कहा, ‘‘जैसे इनका ‘जीरो टॉलरेंस’ ‘जीरो’ हो गया, वैसे ही ‘जीरो पॉवर्टी’ का जुमलाई–भाजपाई दावा भी होगा। हमारे देश की महान परंपरा ने ‘जीरो’ गणित के लिए दिया था, जनता के बीच झूठ बांटने के लिए नहीं।’’ यादव ने कहा, ‘‘‘पावर्टी’ या गरीबी कामों से जाती है, बातों से नहीं और काम में भाजपा सरकार जीरो है। ये जाते–जाते सब कुछ शून्य करके जाएंगे।’’ उन्होंने ग्रामीण विकास योजनाओं का नाम बदलने के लिए भी भाजपा की आलोचना की। सपा नेता ने कहा, ‘‘भाजपाई ‘अंबेडकर गांव’ और ‘लोहिया गांव’ जैसी पुरानी योजनाओं का नाम बदलकर नये तरह से पेश करने का अपना परंपरागत छलावा कर सकते हैं और कुछ नहीं।’’ उन्होंने भाजपा से अपने वादे को पूरा करने का आह्वान किया। सपा नेता ने कहा, ‘‘भाजपाई नया वादा करने से पहले 15 लाख रुपए खातों में भिजवा दें और गोद लिए गांव की बदहाली भी जाकर देख लें और पहले हर किसी को घर और हर घर में जल जैसे झूठे वादों पर कई परतों तक जमा हो चुकी धूल को झाड़ें।’’ उन्होंने कहा, ‘‘कम–से–कम गरीबों से तो झूठ न बोलें। यह निंदनीय है।’’ उत्तर प्रदेश सरकार ने सोमवार को घोषणा की थी कि राज्य में ‘जीरो पॉवर्टी कार्यक्रम’ (शून्य गरीबी अभियान) बाबा साहेब डॉ. भीमराव अंबेडकर के नाम पर होगा।

प. बंगाल में पारंपरिक उत्साह एवं उल्लास के साथ मनाया गया बंगाली नववर्ष

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

कोलकाता/भाषा। बंगाली नववर्ष (पोइला बैसाख) मंगलवार को पूरे पश्चिम बंगाल में पारंपरिक उत्साह एवं उल्लास के साथ मनाया गया और इस दौरान लोगों ने मंदिरों में पूजा–अर्चना की, दुकानों पर जाकर नए खाता–बही खोले और रेस्तरां में विशेष रूप से तैयार किए गए व्यंजनों का आनंद लिया।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सी वी आनंद बोस और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बंगाली नववर्ष के अवसर पर राज्य के लोगों को शुभकामनाएं दीं।

सुबह से ही हजारों लोग शहर के दक्षिणेश्वर और कालीघाट समेत विभिन्न मंदिरों में पहुंचे और उन्होंने ‘हाल खाता’ नामक नई खाता बही खोलकर ईश्वर का आशीर्वाद लिया।

विभिन्न इलाकों में रंगारंग प्रभात फेरी निकली। पुरुष एवं महिलाएं टैगोर की कविता ‘हे नोतुन देखा दिक अर्बार’ (नई सुबह नई उम्मीद के साथ हमारा स्वागत करे) गाते हुए प्रभात फेरियों में शामिल हुए। इस दौरान बंगाल के ग्रामीण जीवन दर्शाने वाली रंगारंग प्रस्तुतियां दी गईं।

कोलकाता समेत विभिन्न जिलों में भी शॉपिंग मॉल खरीदारों से खचाखच भरे रहे और सिंगल स्क्रीन एवं मल्टीप्लेक्स सिनेमा घरों में फिल्मों के शो हाउसफुल रहे।

बड़ी संख्या में लोगों ने विभिन्न बंगाली रेस्तरां में व्यंजनों का आनंद लिया और रेस्तरां में भारी भीड़ के कारण पारंपरिक पोशाक पहने ग्राहक उनके बाहर खड़े होकर घंटों इंतजार करते दिखे। विभिन्न इलाकों में बंगाली विरासत और संस्कृति को प्रदर्शित करते हुए विशेष संगीत समारोह और रंगमंच प्रस्तुतियां आयोजित की गईं।

मुर्शिदाबाद के कुछ हिस्सों में सांप्रदायिक हिंसा का असर जिले के धुलियान, शमशेरगंज, सुती और जंगीपुर में नववर्ष समारोहों पर देखने को मिला और कई व्यापारियों ने अपनी दुकानें बंद रखीं।

पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने इस अवसर पर अपनी शुभकामनाएं दीं। अधिकारी ने तामलुक में चैतन्य महाप्रभु मंदिर से मां वर्गभीमा मंदिर तक अपनी रैली का वीडियो संलग्न करते हुए सोशल मीडिया पर एक ‘पोस्ट’ में लिखा, ‘‘आइए बंगाली नववर्ष में इस नई उम्मीद के साथ शुरुआत करें कि बंगाल में बदलाव आएगा। हम बदलाव लाएंगे।’’

हेमंत सोरेन झामुमो के केंद्रीय अध्यक्ष निर्वाचित हुए, उनके पिता शिबू सोरेन ‘संस्थापक संरक्षक’ बने

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

रांची/भाषा। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को मंगलवार को सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) का केंद्रीय अध्यक्ष चुना गया वहीं उनके पिता शिबू सोरेन को पार्टी का ‘‘संस्थापक संरक्षक’’ बनाया गया। पार्टी के एक नेता ने यह जानकारी दी।

उन्होंने कहा कि शिबू सोरेन पिछले 38 वर्षों से झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रमुख थे, जबकि उनके बेटे हेमंत 2015 से पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में काम कर रहे थे।

झामुमो के 13वें केंद्रीय अधिवेशन के दौरान पार्टी के वरिष्ठ नेता नलिन सोरेन ने संस्थापक संरक्षक के रूप में शिबू सोरेन के नाम का प्रस्ताव रखा, जिसका समर्थन स्टीफन मरांडी ने किया।

इसके बाद शिबू सोरेन ने झामुमो के केंद्रीय अध्यक्ष के रूप में हेमंत सोरेन के नाम का प्रस्ताव रखा, जिसे सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया।

असमिया भाषा को राज्य में सभी आधिकारिक कार्यों के लिए अनिवार्य घोषित किया गया

गुवाहाटी/भाषा। असम में बराक घाटी के तीन जिलों और बोडोलैंड प्रादेशिक क्षेत्र (बीटीआर) के अंतर्गत पांच जिलों को छोड़कर पूरे राज्य में सभी आधिकारिक कार्यों में असमिया भाषा का इस्तेमाल अनिवार्य रूप से किया जाएगा। यह जानकारी एक आधिकारिक अधिसूचना में दी गयी है।

अधिसूचना के अनुसार, हालांकि सभी सरकारी अधिसूचनाएं, कार्यालय ज्ञापन, अधिनियम, नियम, विनियम, योजना दिशानिर्देश, स्थानांतरण और पोस्टिंग आदेश अंग्रेजी और असमिया दोनों में जारी किए जाएंगे।

दंपति ने नाबालिग बेटी को पांच लाख रुपए में बेचा, खरीदार ने किया दुष्कर्म

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

कौशांबी (उप्र)/भाषा। जिले के करारी थाना क्षेत्र में एक दलित नाबालिग किशोरी को उसके ही मां–बाप ने एटा जनपद निवासी एक व्यक्ति को पांच लाख रुपए में बेच दिया और उस व्यक्ति ने किशोरी से दो दिनों तक दुष्कर्म किया।

कौशांबी के पुलिस क्षेत्राधिकारी अभिषेक सिंह ने यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि करारी थाना क्षेत्र की एक दलित नाबालिग किशोरी ने प्रार्थना पत्र देकर बताया कि उसके माता–पिता ने उसे किसी व्यक्ति को पांच लाख में बेच दिया था।

जिले के करारी थाना क्षेत्र के एक गांव की निवासी 13 वर्षीय दलित किशोरी ने करारी थाने में 13 अप्रैल, 2025 की शाम को दी गई तहरीर में बताया कि कमलेश पासी एटा जनपद के एक व्यक्ति को लेकर उसके घर आता था। पीड़िता ने बताया कि गत 14 मार्च को भी कमलेश पासी एटा के उस व्यक्ति को लेकर उसके घर आया था। तहरीर के मुताबिक, 14 मार्च को शाम करीब 7:00 बजे किशोरी के माता–पिता ने उसे खाना खिलाया जिसके बाद उसे नींद और चक्कर आने लगे और जब नींद खुली तो किशोरी एटा जनपद के निवासी उस व्यक्ति के घर पर थी। किशोरी ने उस व्यक्ति से पूछा कि वह यहां कैसे आ गई, तो उस व्यक्ति ने कहा, ‘‘मैंने तुम्हारे मां–बाप को पांच लाख देकर तुम्हें खरीदा है।’’ किशोरी ने वहां से भागने की कोशिश की तो उस व्यक्ति ने उसे बंधक बना लिया और उससे दो दिनों तक जबरदस्ती दुष्कर्म करता रहा। लेकिन किशोरी 16 मार्च को मौका पाकर रात तीन बजे दीवार फांदकर भाग निकली और किसी तरह अलीगंज स्टेशन से ट्रेन पकड़ कर कौशांबी जनपद के भरवारी रेलवे स्टेशन पर उतरी।

घर पहुंचने पर उसके मां–बाप ने उसे घर में घुसने नहीं दिया और कहा कि उस व्यक्ति के पास लौट जाओ क्योंकि उन्होंने उससे पांच लाख रुपए लिए हैं। इसके बाद मारपीट कर किशोरी को घर से भगा दिया। इसके बाद पीड़िता जिले के मंझनपुर थाना क्षेत्र के गांव निवासी फूफा के घर गई और उन्हें सारी बात बताई। अभिषेक सिंह ने बताया कि पीड़िता की तहरीर पर करारी थाना में पीड़िता के माता–पिता, एटा निवासी उस व्यक्ति और करारी थाना क्षेत्र के एक व्यक्ति सहित चार लोगों के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में अभियोग दर्ज किया है। पीड़िता का बयान दर्ज कराया गया है और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए टीम गठित की है। बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष कमलेश चंद ने बताया कि नाबालिग को बेचने के मामले की जांच बाल कल्याण समिति ने भी शुरू कर दी है।

नीतीश कुमार ही होंगे बिहार विस चुनाव में राजग के मुख्यमंत्री पद का चेहरा: जदयू

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

नई दिल्ली/भाषा। जनता दल यूनाइटेड (जदयू) ने मंगलवार को कहा कि बिहार विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार ही राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) के मुख्यमंत्री पद का चेहरा होंगे।

एक दिन पहले हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने यह कहकर बिहार में राजनीतिक हलचल मचा दी थी कि भाजपा नेता और बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी चुनाव में जीत दिलाएंगे। सैनी के बयान का हवाला देते हुए विपक्ष ने सहयोगी दलों के साथ बर्ताव को लेकर भाजपा पर निशाना साधना शुरू कर दिया। जदयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन प्रसाद ने हरियाणा के नेता की टिप्पणी को खारिज कर दिया और कहा कि बिहार में मुख्यमंत्री पद के चेहरे को लेकर सत्तारूढ़ गठबंधन के सामने कोई संकट नहीं है।

सैनी ने सोमवार को एक कार्यक्रम में कहा था कि चुनावों में भाजपा की विजय यात्रा जारी रहेगी और बिहार में यह चौधरी के नेतृत्व में हासिल होगी।

प्रसाद ने कहा, ‘‘बिहार विधानसभा चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में होंगे और वह राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का चेहरा होंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राजग सरकार का नेतृत्व करेंगे, जो निश्चित ही चुनाव के बाद 2030 तक पूर्ण कार्यकाल के लिए बनेगी।’’ उन्होंने कहा कि वरिष्ठ भाजपा नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अतीत में इसी तरह की बातें कही हैं । उन्होंने यह दावा करते हुए विपक्षी ‘इंडिया’ गठबंधन पर कटाक्ष किया कि यह बिहार में भी बिखरने वाला है, जैसा कि कई अन्य राज्यों में हुआ है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय जनता दल (राजद) तेजस्वी यादव को अपने मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित कर चुका है, जबकि कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने हाल में कहा था कि बिहार में उनके गठबंधन के नेता पर निर्णय चुनाव के बाद लिया जाएगा। प्रसाद ने दावा किया कि यादव कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और पार्टी के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी के साथ अपनी बैठक से खाली हाथ लौटे हैं। उन्होंने कहा कि आगामी बिहार चुनाव में राजग अपनी अब तक की सबसे बड़ी जीत दर्ज करेगी। बिहार में इस साल के अंत तक विधानसभा चुनाव होने की उम्मीद है।

शाह ने कहा है ‘पापा’ मुख्यमंत्री बने रहेंगे: नीतीश के पुत्र निशांत

पटना/भाषा। जनता दल (यूनाइटेड) प्रमुख नीतीश कुमार के पुत्र निशांत ने मंगलवार को दावा किया कि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने यह स्पष्ट कर दिया है कि इस साल के अंत में होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव के बाद भी कुमार राज्य के मुख्यमंत्री बने रहेंगे।

सैतालीस–वर्षीय निशांत ने यहां अपने एक रिश्तेदार की सगाई समारोह में पत्रकारों से बातचीत की। इस समारोह में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी मौजूद थे, लेकिन उन्होंने पत्रकारों के किसी सवाल का जवाब नहीं दिया। जब निशांत का ध्यान विपक्ष के इस दावे की ओर आकृष्ट किया गया कि विधानसभा चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) उनके पिता को हटा सकती है, क्योंकि वह (भाजपा) जद(यू) प्रमुख कुमार (74) के सहयोगी की भूमिका निभाकर अब उकता चुकी है, तो निशांत ने आश्चर्य व्यक्त किया। निशांत ने कहा, ‘‘चुनावों में राजग (राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन) की जीत के बाद मेरे पिता के मुख्यमंत्री बने रहने को लेकर कोई संदेह नहीं है। अमित शाह ‘अंकल’ ने हाल ही में बिहार के दौरे के दौरान ऐसा कहा था। सम्राट चौधरी (उपमुख्यमंत्री) ने भी यही कहा है।’’

सुविचार

अपना दिल, दिमाग और आत्मा अपने छोटे से छोटे काम में भी लगा दो। यही सफलता का रहस्य है।

दक्षिण भारत राष्ट्रमत

नशे की लत, बुद्धि भ्रष्ट

मध्य प्रदेश के नीमच जिले में जैन मुनियों पर हुआ हमला एक सामाजिक चेतावनी है। लोग अपने कल्याण के लिए साधु-संतों के चरणों में बैठकर उपदेश सुनते हैं, अपनी बुराइयों का त्याग करते हैं, लेकिन नीमच जिले के सिंगोली थाना क्षेत्र में कुछ लोग शराब पीने के लिए जैन मुनियों से ही रुपए मांगने लगे! उन्होंने उन पर लाठी और धारदार हथियारों से हमला किया! हमारा समाज किस दिशा में जा रहा है? ऐसी घटनाएं किसी के साथ नहीं होनी चाहिएं। खासकर साधु-संतों, जिनके प्रति भारतीय समाज सदैव सम्मान की भावना रखता आया है, पर हमला होना अत्यंत निंदनीय है। मध्य प्रदेश पुलिस ने हमले के आरोपियों को पकड़ने में तेजी दिखाई और मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कार्रवाई का भरोसा दिलाते हुए ऐसी मानसिकता रखने वालों को कठोर संदेश दिया है। नशे की लत मनुष्य की बुद्धि भ्रष्ट कर देती है, विवेक को खत्म कर देती है। अगर ये (आरोपी) शराब की लत से मुक्ति पाने के लिए जैन संतों की शरण में जाते और उनके उपदेशों को जीवन में उतारते तो इनका उद्धार हो सकता था। इन्होंने जो अपराध किया, उसके लिए कठोर दंड मिलना चाहिए। प्राचीन काल में साधु-संतों को सताने वालों, उनका अनादर करने वालों, तपस्या एवं यज्ञ आदि में विघ्न डालने वालों को प्रभु श्रीराम और श्रीकृष्ण ने कठोर दंड दिया था। नीमच की घटना ने एक बार फिर यह दिखा दिया कि अपराधियों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। शराब जैसी बुराई उन्हें तेजी से पतन की ओर लेकर जा रही है। जिन्हें शराब की लत लग जाती है, वे घर या बाहर, हंगामा करते ही हैं।

याद करें, कोरोना काल में जब शराब की दुकानों को खोलने की इजाजत दी गई, तो सोशल मीडिया पर मारपीट के कई वीडियो आने लगे थे। कई शराबियों ने कोरोना संबंधी नियमों का उल्लंघन करते हुए गली-मोहल्लों में खूब हुड़दंग मचाया था। ऐसी घटनाएं गंभीर सामाजिक समस्या की ओर संकेत करती हैं। इन्हें सिर्फ इस आधार पर नज़रअंदाज़ नहीं करना चाहिए कि संबंधित राज्य में शराब की बिक्री पर प्रतिबंध नहीं है। शराब के नशे में डूबे मनुष्य का इतना नैतिक पतन हो सकता है कि वह मंदिर में विश्राम करने के लिए रुके साधु-संतों पर हमला करने से नहीं हिचकता। इन लोगों का अपने घरों में कैसा बर्ताव रहा होगा? जो बाहर मारपीट कर सकते हैं, क्या वे घरों में किसी पर हाथ नहीं उठाते होंगे? जो नशे के लिए साधु-संतों से रुपए मांगने में लज्जा महसूस नहीं करते, क्या वे धन प्राप्ति के लिए अनैतिक तरीके नहीं अपनाते होंगे? जो मंदिर जैसे पवित्र स्थान की मर्यादा का उल्लंघन कर सकते हैं, क्या वे अन्य स्थानों पर मर्यादा का पालन करते होंगे? शराब की एक बोतल कितनी बुराइयां पैदा कर देती है! सरकार को इस पर पूर्ण प्रतिबंध लगाना चाहिए। अगर तुरंत ऐसा संभव न हो तो इसके उपयोग को सख्ती से नियंत्रित करते हुए प्रतिबंध की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। हमारे गांवों-शहरों में पुस्तकालय आसानी से नहीं मिलते। योगाभ्यास एवं ध्यान केंद्र ढूंढ़ने के लिए चक्कर लगाने पड़ सकते हैं। युवाओं को सही राह दिखाने के लिए नि:शुल्क परामर्श केंद्र तो शायद ही कहीं देखने को मिलें। हां, शराब के ठेके आसानी से मिल जाते हैं। उन पर खूब भीड़ उमड़ती है। कुछ 'तेजस्वी' लोग ऐसे सुझाव देते हैं कि साबुन, तेल, सब्जी आदि की तरह शराब की ऑनलाइन होम डिलिवरी शुरू होनी चाहिए। यानी जिन घरों में अब तक शराब नहीं पहुंची, वहां भी तुरंत पहुंचाने का इंतज़ाम! क्या हम नशाखोरी को बढ़ावा देकर स्वस्थ और खुशहाल समाज बना पाएंगे? शराब की बोतलें मुंह को लगाकर कई लोग बर्बाद हो गए। यह बुराई जड़ से खत्म करने के लिए सरकार और समाज, दोनों को आगे आना चाहिए।

ट्वीटर टॉक

अंतर्राष्ट्रीय लैब टेक्नीशियन दिवस के अवसर पर आज जयपुर में अखिल राजस्थान लैब टेक्नीशियन कर्मचारी संघ द्वारा आयोजित कार्यक्रम में सम्मिलित होकर सभी लैब टेक्नीशियन कर्मचारियों को इस सुअवसर पर बधाई एवं शुभकामनाएं प्रेषित की।

–दीया कुमारी

प्रकृति के उपहार से सजे, अनुपम आभामयी हिमाचल प्रदेश के सभी वासियों को हिमाचल दिवस की हार्दिक शुभकामनाएँ। श्रद्धा के केंद्र मंदिर, ऊँचे पहाड़, मनोरम घाटियों और प्राकृतिक समृद्धता से परिपूर्ण यह प्रदेश प्रगति के सोपान चढ़ें, यहाँ के लोग खुशहाल रहें।

–ओम बिरला

हमने पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली स्कीम शुरू की है। अपने छत पर सोलर पैनल लगाकर आप अपना बिजली का बिल जीरो कर सकते हैं। इतना ही नहीं, जो अतिरिक्त बिजली का उत्पादन होगा, उसे बेचकर कमाई भी कर सकते हैं।

–नरेन्द्र मोदी

प्रेरक प्रसंग

सिक्के से सीख

सिंहगढ़ राज्य की सीमा के पार बसे गांव सोनपुर में कहीं से एक महात्मा आकर विराजे। वे अपने दो शिष्यों के साथ भिक्षाटन हेतु जा रहे थे, तभी राह में उन्हें एक कीमती सिक्का मिला। महात्मा ने वह सिक्का अपनी झोली में रख लिया। शिष्यों के मन में कौतूहल जागा'वीतरागी संत का सिक्के से क्या काम?' गुरुजी उनके अंतर्मन की हलचल भांप गए। मुस्कराकर बोले, 'बच्चो! यह सिक्का मुझे प्रभु ने इसलिए दिया है, ताकि मैं इसे किसी सुपात्र को सौंप सकूं।' कई दिन बीत गए, पर महात्मा ने वह सिक्का किसी को नहीं दिया। तभी समाचार मिला कि सिंहगढ़ के राजा पड़ोसी राज्य पर चढ़ाई करने आ रहे हैं। महात्मा ने अपने शिष्यों से कहा, 'सोनपुर छोड़ने का समय आ गया है, चलो।' तभी राजा की सवारी वहां आ पहुंची। वह हाथी से उतरकर साधु को प्रणाम करते हुए बोला, 'महाराज! आपके दर्शन पाकर मैं धन्य हो गया। कृपया मुझे आशीर्वाद दें।' महात्मा ने झोली से वह सिक्का निकाला और राजा को सौंपते हुए बोले, 'नृपति! तुम्हारा राज्य वैभव के शिखर पर हैधन है, सेना है, यश है और प्रजा में सुख-शांति भी है। फिर भी तुम दरिद्र हो, क्योंकि इतना सब कुछ होते हुए भी तुम्हारे मन में संतोष नहीं है।

सामयिक

अराजकता में डूबे बंगाल में नाउम्मीदी का अंधेरा

ललित गर्ग
मोबाइल : 9811051133

बंगाल में वक्फ कानून को लेकर हिंसा का सिलसिला जिस तरह तेज और सांप्रदायिक होता जा रहा है, जिस तरह से हिन्दुओं को निशाना बनाया जा रहा है, उन्हें मुर्शिदाबाद से पलायन को विवश किया जा रहा है, वह मुस्लिम तुष्टीकरण और दुष्प्रचार की खतरनाक राजनीति का प्रतिफल तो है ही, वह कुशासन एवं अराजकता की भी चरम पराकाष्ठा भी है। नए वक्फ कानून को लेकर कुछ राजनीतिक दल मुस्लिम समाज को विशेषत: किशोर बच्चों को हिंसा एवं तोड़फोड के लिये जानबूझकर सड़कों पर उतारने में लगे हुए हैं। वे उन्हें अराजकता एवं उन्माद के लिए उकसा भी रहे हैं और तरह-तरह से प्रोत्साहन दे रहे हैं। अराजकता फैलाने वाले किस तरह बेखौफ हैं, इसकी पुष्टि इससे होती है कि वे सरकारी-गैरसरकारी वाहनों को तोड़ने, जलाने के साथ पुलिस पर भी हमले कर रहे हैं। बंगाल के विभिन्न जिलों में वक्फ कानून के विरोध के बहाने फैलाई जा रही अराजकता इसलिए भी थमने का नाम नहीं ले रही हैं, क्योंकि खुद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इस कानून के खिलाफ खड़ी होकर राजनीतिक रोटियां सेंकने का काम कर रही हैं। पश्चिम बंगाल में हिंसा का बढ़ना, हिन्दुओं में डर पैदा होना, भय का वातावरण बनना, आम जनजीवन का अनहोनी होने की आशंकाओं से घिरा होना चिंताजनक भी है और राष्ट्रीय शर्म का विषय भी है।

यह बंगाल पुलिस के नाकारापन एवं ममता सरकार के मुस्लिम तुष्टिकरण का ही दुष्परिणाम है कि मुर्शिदाबाद के साथ ही अन्य शहरों में भी वक्फ कानून के विरोध की आड़ में हिंसा, तोड़फोड, आगजनी हो रही है। खतरनाक यह है कि इस दौरान हिंदुओं को जानबूझकर निशाना बनाया जा रहा है। इससे संतुष्ट नहीं हुआ जा सकता कि कलकत्ता उच्च न्यायालय ने वक्फ कानून विरोधियों की अराजकता से उपजे हालात का संज्ञान लिया। मामला सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच गया है। इससे शर्मनाक एवं दर्दनाक और कुछ नहीं हो सकता कि मुर्शिदाबाद में 11 अप्रैल को हुई हिंसा के बाद करीब 500 हिंदू पलायन कर गए हैं। हिंदू परिवारों का आरोप है कि हिंसा के दौरान उनको चुन-चुनकर निशाना बनाया गया। उनके पीने के पानी में जहर तक मिला दिया गया है। इस हिंसा की जांच एजेंसियों ने पोल खोल दी है, यह हिंसा पूरी प्लानिंग के तहत की गई थी, जिसमें तुर्की से फंडिंग और स्थानीय मदरसों की मिलीभगत सामने आई है। हमलावरों को ट्रेनिंग दी गई और इनाम की व्यवस्था भी की गई थी। ममता बनर्जी एवं उनकी सरकार देश में एकमात्र ऐसी सत्तारुढ़ पार्टी एवं नेता बन गई है जिसका देश के संविधान, न्यायपालिका एवं लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भरोसा नहीं रह गया है।

वक्फ कानून का विरोध करने सड़क पर उतरे तत्वों के दुस्साहस का पता इससे चलता है कि वे सीमा सुरक्षा बल के जवानों को भी निशाना बनाने से नहीं हिचक रहे हैं। उनके इसी दुस्साहस के चलते मुर्शिदाबाद के हिंदुओं ने खुद को असहाय पाया। बंगाल में कानून के शासन ने सुनियोजित हिंसा के दुष्चक्र के समक्ष एक बार फिर समर्पण कर दिया। बंगाल में इसके पहले भी ऐसा हो चुका है। मई 2021 में विधानसभा चुनावों के बाद वहां तृणमूल समर्थक तत्वों ने अपने राजनीतिक विरोधियों को इतना आतंकित किया था कि वे जान बचाने के लिए असम में शरण लेने को मजबूर हुए थे। तब भी वहां पुलिस मूकदर्शक बनी हुई थी। ताजा हिंसक हालातों में राज्य सरकार और उसके नेता यह झूठ देश के गले में उतारने में लगे हुए हैं कि बंगाल में स्थितियां नियंत्रण में हैं। यह कैसा नियंत्रण है? यह कैसी शासन-व्यवस्था है? यह कैसा दोगलापन है? जिसमें एक समुदाय खुलेआम दूसरे समुदाय को निशाना बना रहा है। खुलेआम सार्वजनिक मंचों पर राष्ट्र-विरोधी विचारों का जहर घोला जा रहा है।

वक्फ कानून में संशोधन का विरोध विडम्बनापूर्ण होने के साथ देश में अराजकता फैलाने का माध्यम बना हुआ है। वक्फ कानून में संशोधन के तहत किसी मस्जिद, मदरसे आदि को लेकर किसी भी तरह के नुकसान, कब्जा करने या दखल की बात नहीं कही गयी है। इसके विरोधी चाहे जो तर्क दें, इससे कोई इंकार नहीं कर सकता कि वक्फ बोर्ड भ्रष्टाचार का अड्डा बने हुए थे और सरकारी-निजी जमीनों पर मनमाने तरीके से दावा कर दिया करते थे। उनकी इस मनमानी का शिकार अनेक मुस्लिम भी थे। क्या वक्फ कानून के विरोधी यह बताने की स्थिति में हैं कि वक्फ बोर्डों ने अभी तक कितने गरीब मुसलमानों की सहायता की? यह पहली बार नहीं है, जब किसी कानून के खिलाफ सड़कों पर उतरकर उपद्रव, हिंसा, आगजनी की जा रही हो। इसके पहले नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ भी ऐसा ही किया गया था। तब यह झूठ फैलाया जा रहा था कि इस कानून के जरिये मुसलमानों की नागरिकता छीन ली जाएगी। अब यह झूठ फैलाया जा रहा है कि नए वक्फ कानून के जरिये सरकार मस्जिदों और कब्रिस्तानों पर कब्जा करना चाहती है। यह निरा झूठ और शरारत ही है। वक्फ कानून के विरोधी भले ही लोकतंत्र और संविधान की दुहाई दे रहे हों, लेकिन ये उसकी धज्जियां ही उड़ा रहे हैं। वे वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले की प्रतीक्षा करने के लिए तैयार नहीं।

मुर्शिदाबाद हिंसा के जरिए पूरे बंगाल में हिंसा फैलाने का प्लान तुर्की में बनाया गया था, इसके जरिए बंगाल के हालात भी ठीक बांग्लादेश की तरह करने की कोशिश थी। हिंसा को लेकर बाकायदा एक लिस्ट तैयार की गई थी कि कौन कहां नुकसान करेगा और लूटपाट मचाएगा। इसके साथ ही इनाम देने को लेकर योजनाएं बनाई गयी। हिंसा के दौरान इस बात का खास ध्यान देने का अलर्ट किया गया कि रेल और नॉर्मल ट्रांसपोर्ट न चल पाए। मौका मिलने पर हिंदुओं की हत्या करना भी टारगेट था। कुछ हिन्दुओं को मारा भी गया है। हिंदुओं के घरों के साथ मंदिरों पर हमले किए गए, घर जलाए गए, आजीविका नष्ट की गई, बलात्कार की धमकियां दी गयी, उससे यही स्पष्ट हो रहा है कि नए वक्फ कानून का विरोध करने वाले न केवल सांप्रदायिक घृणा में डूबे हैं, अराजकता एवं उन्माद पर सवार है, आतंकी माहौल बनाकर हिन्दुओं को भयभीय-आतंकित करना चाहते है। क्योंकि उन्हें यह भरोसा है कि ममता बनर्जी की सरकार और उनकी पुलिस उनके खिलाफ कुछ नहीं करने वाली। ज्यादा चिन्ताजनक तो यह है कि अराजक लोग चाहते हैं पलायन करने के लिए मजबूर लोग फिर कभी अपने घरों को न लौट पाएं। इन जटिल एवं अनियंत्रित होते अराजक हालातों में शांति, सौहार्द एवं सामान्य हालातों को निर्मित करने के लिये आवश्यक है कि केंद्र सरकार बंगाल में हस्तक्षेप करने के लिए आगे आए, बल्कि यह भी अपेक्षित है कि सुप्रीम कोर्ट वहां के हालात का स्वत: संज्ञान ले। उसे वक्फ कानून विरोधी हिंसक तत्वों के उपद्रव के लिए ममता सरकार को जवाबदेह बनाना ही होगा।

ममता वोट बैंक की राजनीति के लिये कानून एवं सुरक्षा व्यवस्था की धज्जियां बार-बार उड़ाती रही है। ममता ने देश की एकता-अखंडता और सुरक्षा से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों को नजरअंदाज किया है, कानून से खिलवाड़ जितना पश्चिमी बंगाल में हुआ है उतना शायद ही देश के किसी दूसरे राज्यों में हुआ हो। ममता अपने बलबूते चुनाव जीतने का माद्दा रखती है तो फिर हिंसा का सहारा क्यों लेती है? अराजकता फैलाकर अपने ही शासन को क्यों दागदार बनाती है? क्यों अपने प्रांत की जनता को डराती है, भयभीत करती है? क्या ये प्रश्न ममता की राजनीतिक छवि पर दाग नहीं है? ममता एवं तृणमूल कांग्रेस का एकतरफा रवैया हमेशा से समाज को दो वर्गों में बांटता रहा है एवं सामाजिक असंतुलन तथा रोष का कारण रहा है। ताजा हिंसक हालात इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण है कि किसी भी एक वर्ग की अनदेखी कर कोई भी दल राजसत्ता का आनंद नहीं उठा सकता। राज्य में शीर्ष संवैधानिक पद पर रहते हुए भी ममता बनर्जी ने अलोकतांत्रिक, गैर-कानूनी एवं राष्ट्र-विरोधी कार्यों को अंजाम दिया है। बंगाल में तो भ्रष्टाचार और साम्प्रदायिकता के जबड़े फैलाए, हिंसा की जीभ निकाले, मगरमच्छ सब कुछ निगल रहा है। ममता अपनी जातियों, ग्रुपों और वोट बैंक को मजबूत कर रही हैं-- देश को नहीं।

बोध कथा

सुनने की क्षमता का महत्व

एक साल जंगल में बिताने के बाद युवराज अपने राज्य को लौटना चाहता था, पर गुरु की बात को टाल भी नहीं सकता था, इसलिए वह बेमन ही जंगल की ओर बढ़ चला। कई दिन गुजर गए पर युवराज को कोई नई आवाज़ नहीं सुनाई दी। वह परेशान हो उठा। उसने निश्चय किया कि अब वह हर आवाज़ को बड़े ध्यान से सुनेगा। फिर एक सुबह उसे कुछ अनजानी सी आवाजें हल्की- हल्की सुनाई देने लगीं। इस घटना के कुछ दिनों बाद वह गुरु के पास वापस लौटा और बोला- पहले तो मुझे वही ध्वनियां सुनाई दीं जो पहले देती थीं, लेकिन एक दिन जब मैंने बहुत ध्यान से सुनना शुरू किया तो मुझे वो सुनाई देने लगा जो पहले कभी नहीं सुनाई दिया था। मुझे कलियों के खिलने की आवाज सुनाई देने लगी। मुझे धरती पर पड़ती सूर्य की किरणों, तितलियों के गीत और घांस द्वारा सुबह की ओस पीने की ध्वनियां सुनाएं देने लगीं। यह सुनकर गुरुजी खुश हो गए और मुस्कुराकर बोले- अनसुने को सुनने की क्षमता होना एक अच्छे राजा की निशानी है। क्योंकि जब कोई शासक अपने लोगों के दिल की बात सुनना सीख लेता है। बिना उनके बोले, उनकी भावनाओं को समझ लेता है, जो दर्द बयां न किया गया हो उसे समझ लेता है, अपने लोगों की अनकही शिकायतों को सुन लेता है, केवल वही अपनी प्रजा का विश्वास जीत सकता है। कुछ गलत होने पर उसे समझ सकता है और अपने नागरिकों की वास्तविक आवश्यकताओं को पूरी कर सकता है। अगर हमें अपनी फील्ड का लीडर बनना है तो हमें भी वो सुनना, सीखना चाहिए जो नहीं कहा गया है। यानी हमें उस युवराज की तरह बिलकुल अलर्ट होकर अपना काम करना चाहिए और अपने साथ काम करने वालों की ज़रूरतों और भावनाओं का ख्याल रखना चाहिए। तभी हम खुद को एक ट्रू लीडर की तरह स्थापित कर सकेंगे।

नजरिया

अंबेडकर के बहाने दलितों को रिझाने का सियासी प्रयास

बाल मुकुन्द ओझा
मोबाइल : 9414441218

भारत की सियासत में जाति विशेष के महत्व को नकारा नहीं जा सकता। जातियों के कारण बहुत से नेता राजनीति में बलशाली बने हुए है। सभी पार्टियों में कमोवेश ऐसे नेता मिल जायेंगे जिनकी सियासत जाति से ही शुरू होकर वहीं जाकर थम जाती है। यहाँ हम दलित सियासत की बात कर रहे है। संविधान निर्माता बाबा साहेब अंबेडकर की जयंती पर सियासी पार्टियों ने उन्हें अपने अपने हिसाब से याद किया और उनके विचारों को अंगीकृत करने का संकल्प दोहराया। इस अवसर पर दलित एकता की गूँज भी देशभर में सुनाई दी गई। चूंकि इसी साल बिहार में विधानसभा चुनाव होने है ऐसे में सियासी दलों को अंबेडकर की याद भी जोर शोर से आनी स्वाभाविक थी। बताते है जो पार्टी दलितों की अधिकतम सीटें प्राप्त करेगी वही राज करेगी। चुनाव के मद्देनजर राजनीतिक पार्टियां दलित वोटो को रिझाने में जुटी हैं। सत्तारूढ़ और विपक्षी दोनों धड़े दलितों पर डोरे डाल रहे हैं। राजनीतिक दलों ने अपने तरकश के तीरों को धार देनी शुरू कर दी है। जातीय वोटों को हासिल करने के लिए नए नए दांव और पैंतरे आजमाए जा रहे है। बताया जाता है दलित वोट जिधर जाते है सत्ता की चाबी उसे ही मिलती है। दलित जिस दल की ओर जाएंगे, उसकी काफी हद तक राह आसान कर देंगे। इनकी संख्या को देखते हुए सभी राजनीतिक दलों ने इनको अपने पाले में खींचने की कवायद तेज कर दी है। इसी को ध्यान में रखते हुए भाजपा सहित सभी सियासी पार्टियों ने दलित मतदाताओं को रिझाने के लिए साम दाम दंड भेद की नीति अख्तियार करली है। दलित का मतलब पीड़ित, शोषित व्यक्ति से है। अनुसूचित जाति को दलित बताया जाता है। संवैधानिक भाषा में इन्हें अनुसूचित जाति कहां गया है। भारतीय जनगनणा 2011 के अनुसार भारत की जनसंख्या में लगभग 16.6 प्रतिशत या 20.14 करोड़ आबादी दलितों की है।

देश के राजनीतिक हल्कों में अक्सर इस बात की जोरदार चर्चा होती रहती है की भाजपा को सत्ता सुख देने वाले दलित वोटर्स 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा से विमुख क्यों हुए। लोकसभा चुनावों में दलितों ने भाजपा के खिलाफ मतदान किया। दलितों की बेरुखी ने भाजपा का 400 पार का नारा ध्वस्त कर दिया। उन्हें यह डर था सत्ता रहा था कि फिर मोदी सरकार बनी तो वह आरक्षण खत्म कर देगी। या यूँ कहे विपक्ष के बनाये भ्रम का दलित शिकार हो गए। चुनाव में विपक्ष ने संविधान खतरे में का मुद्दा जोर शोर से उठाया जिससे दलित मतदाता बिदक गए।

आजादी के बाद दलितों को चुनावी हथियार समझा गया। कांग्रेस पार्टी का इस वर्ग के वोटों पर एकाधिकार स्थापित हो गया। जगजीवन राम

1977 तक दलितों के एकछत्र नेता के रूप में स्थापित हुए। दरअसल 1977 के बाद दलित सियासत में एक नए युग की शुरुआत हुई। दलित वोट कांग्रेस से छिटक कर दूसरे दलों की तरफ जाने लगे। इंदिरा गाँधी ने एक बार फिर दलितों का विश्वास जीता। राजीव गाँधी को भी दलितों का हितचिंतक समझा गया। जनता पार्टी के विघटन के बाद दलित भी बिखर गए। महाराष्ट्र के कुछ नेताओं ने दलित सियासत की कमान सँभालने का प्रयास किया मगर सफल नहीं हुए। जगजीवन राम के बाद कांशीराम दलितों के बड़े नेता के रूप में उभरे और कुछ हद तक यूपी के दलितों के एक बड़े तबके ने उन्हें अपने रहनुमा के रूप में स्वीकारा। शुरू में उन्होंने सवर्णों के विरुद्ध आग उगली मगर जल्दी ही उन्हें समझ में आ गया की ऊँची जातियों से गठजोड़ किये बिना दलितों का भला नहीं होगा। मुलायम सिंह से गठजोड़ कर कांशीराम ने दलित सियासत को धार दी जिसके फलस्वरूप यूपी की राजनीति में उन्हें पैर जमाने में सफलता मिली। बाद के दिनों में मायावती को साथ लेकर कांशीराम ने स्वर्ण जातियों से गठजोड़ कर दलित सियासत को शिखर पर पहुँचाया।

इसी बीच भारतीय जनता पार्टी ने दलित वोटों को अपनी झोली में डाल कर दलित वोटों पर अपनी पकड़ मजबूत की। मायावती से यूपी का ताज छीनने के बाद भाजपा ने दलितों में अपना आधार बढ़ाया। दलित वोटों का कांग्रेस से मोह भंग होने से यह पार्टी सत्ताविहीन हो गयी। मायावती का जनाधार खिसकने से दलितों के पास शक्तिशाली नेतृत्व नहीं रहा। दलित नेतृत्व भाजपा ने हथिया लिया। मगर भाजपा को सबसे बड़ा झटका हालिया लोकसभा चुनावों में तब मिला जब दलितों के एकमुश्त वोट भाजपा से छिटक गए फलस्वरूप भाजपा अकेले दम पर बहुमत से पिछड़ गई।

महत्त्वपूर्ण
Printed& Published by Devendra Sharma on behalf of owners M/s. New Media Company,6/4 , Ist floor, Cantonment station road, Bengaluru-51and printed at Dinasudar Printing Division, 116, Queens Road, Bengaluru-560052. **Editor-Shreekant Parashar**, (*Responsible for selection of news under PRB Act.) Reproduction of any matter from this newspaper in whole or in part or any suchmanner without prior written permission from the publisher is strictly prohibited and punishable by law.**RNI No. 58061/93. Regn No.: RNP/KA/BGS/2050/2015-2017 posted at Bengaluru PSO Mysore Road Bengaluru-560 026**

पाठकों से अनुरोध है कि इस प्रकाशन में प्रकाशित किए जाने वाले किसी भी तरह के विज्ञापन (वैवाहिक, वर्गीकृत, टैंड़र एवं सजावटी इत्यादि) पर कोई भी कार्यवाही, प्रतिबद्धता या धनराशि का व्यय करने से पूर्व इन विज्ञापनों के बारे में समस्त जानकारी वह स्वयं प्राप्त कर लें। दक्षिण भारत राष्ट्रमत समूह उत्पादों की गुणवत्ता तथा सेवाओं के लिए विज्ञापनदाताओं द्वारा किए जा रहे किसी प्रकार के दावों के लिए जिम्मेदार नहीं है। अगर विज्ञापनदाता विज्ञापन में किया जा रहा दावा पूरा नहीं करता है तो दक्षिण भारत राष्ट्रमत समूह के संपादक, मुद्रक एवं प्रकाशक या मालिकान को पाठक किसी भी रूप में उत्तरदाई नहीं बना सकता।– दक्षिण भारत राष्ट्रमत

प्रतियोगिता

पटना में गंगा नदी पर दीघा घाट पर एडवेंचर सेलर प्रतियोगिता के दौरान प्रतिभागी हिंदू देवताओं की वेशभूषा में सजे श्रद्धालु।

भारत-तंजानिया संबंधों को नई दिशा देने की तैयारी, साइबर सुरक्षा और आतंकवाद विरोधी सहयोग पर जोर

नई दिल्ली/भाषा। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने तंजानिया के रक्षा और राष्ट्रीय सेवा मंत्री स्टरगोमेना लॉरेंस टैक्स से दार एस सलाम में मुलाकात कर द्विपक्षीय रक्षा सहयोग को और मजबूत करने के नए उपायों पर चर्चा की। यह बैठक 14 अप्रैल को आयोजित की गई थी।

भारतीय रक्षा मंत्रालय ने मंगलवार को बताया कि सेठ ने तंजानिया के उपराष्ट्रपति फिलिप इसडोर मपांगो से भी मुलाकात की।

बैठक के दौरान भारत और तंजानिया के बीच जारी रक्षा सहयोग की समीक्षा की गई तथा उसे और मजबूत करने के संभावित नए क्षेत्रों पर चर्चा हुई। मंत्रालय के बयान के अनुसार, भारतीय सैन्य प्रशिक्षण संस्थानों में तंजानिया के अधिकारियों का प्रशिक्षण, रक्षा उद्योग सहयोग, आतंकवाद-निरोध और उग्रवाद-रोधी अभियानों में सहयोग तथा साइबर सुरक्षा जैसे प्रमुख क्षेत्रों पर विस्तार से बातचीत हुई। इससे पहले, 13 अप्रैल को सेठ और टैक्स ने भारतीय नौसेना की पहल पर अफ्रीका-भारत के बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास के हार्बर फेज का उद्घाटन किया। यह अभ्यास दार एस सलाम में आईएनएस चेन्नई पर आयोजित किया गया जिसमें कोमोरोस, जिबूती, केन्या, मेडागास्कर, मॉरीशस, मोजाम्बिक, सेशेल्स और दक्षिण अफ्रीका जैसे देश भी भाग ले रहे हैं। सेठ ने अपने संबोधन में समुद्री सुरक्षा से जुड़े बड़े और साझा खतरों को रेखांकित करते हुए शांति और समृद्धि सुनिश्चित करने के लिए एकता और साझा उद्देश्य पर जोर दिया। द्विपक्षीय बैठक के अलावा, सेठ ने तंजानिया के उपराष्ट्रपति को भारतीय रक्षा उद्योग और रक्षा प्रदर्शनी से जुड़ी जानकारी दी। उन्होंने तंजानिया पीपुल्स डिफेंस फोर्स की रक्षा जरूरतों को पूरा करने का भी प्रस्ताव रखा।

मंत्रालय ने कहा, यह अभ्यास हिंद महासागर क्षेत्र को स्वतंत्र, खुला और सुरक्षित बनाए रखने की साझेदार देशों की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। भारत-अफ्रीका संबंधों में आज एक नया अध्याय जुड़ गया है। संजय सेठ ने 14 अप्रैल को सनातन धर्म मंदिर और स्वामीनारायण मंदिर का दौरा भी किया। उन्होंने भारतीय समुदाय से मुलाकात की और अंबेडकर जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित समारोह में भी भाग लिया। उन्होंने प्रवासी भारतीयों को संबोधित करते हुए भारत की हालिया उपलब्धियों को साझा किया।

मुस्लिम तुष्टिकरण की राजनीति करते-करते कांग्रेस खुद पंक्चर हो गई : केशव

लखनऊ/भाषा। उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने मंगलवार को कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि वह दशकों तक की गई अपनी मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति के चलते दयनीय हालत में पहुंच गई है।

मौर्य ने मंगलवार को कटाक्ष करते हुए 'एक्स' पर एक पोस्ट में कहा, ''राजनीति का इतिहास 'गवाह' है कि दशकों तक मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करते-करते कांग्रेस खुद 'पंक्चर' हो गई है।'' उन्होंने कहा, ''इस कड़वी सच्चाई के बावजूद वह (कांग्रेस) अभी भी ज़मीनी हक़ीक़त से कोसों दूर है। सच यह भी है कि क्षेत्रीय दलों की बैसाखियों पर घिसटने के अलावा उसके सामने कोई दूसरा रास्ता ही नहीं है।''

मौर्य ने कहा, ''इस सबके बावजूद उसमें अकड़ ऐसी है जैसे देश का भार उसी पर हो। विपक्ष में होने के बावजूद उसका व्यवहार सत्ता पक्ष जैसा है। लोकतंत्र के बजाय गांधी परिवार की छाया में 'राजशाही' में यकीन करने वाली कांग्रेस को संविधान की कभी फ़िक्र नहीं रही है।''

उपमुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस के इतिहास में बस एक फर्क यह आया है कि अब वह गांधी जी के 'खादी' को तिलांजलि देकर 'टी-शर्ट' पर आ गई है।

मौर्य ने कहा, ''इसका प्रभाव भी जनता पर बेअसर है क्योंकि पांच बार सांसद बनने के बाद भी श्री राहुल गांधी का मतलब ही 'नामुमकिन' है। दूसरी तरफ यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी का मतलब ही 'मुमकिन' है। उनके नेतृत्व में भाजपा देश की 'तस्वीर' बदल रही है, जबकि कांग्रेस केवल मुस्लिम समाज को 'पंक्चर' वाला ही देखना चाहती है।''

सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर एक अलग हमले में मौर्य ने 'एक्स' पर कहा, 2027 में सपा की सफाई तय देखकर अखिलेश यादव जी पूरी तरह बौखला चुके हैं। अब समाज को बांटने और सामाजिक ताना-बाना तोड़ने वाले गैर जिम्मेदाराना बयान दे रहे हैं और दिलवा रहे हैं। उन्होंने आगे कहा, लेकिन सपा को इस नीति से अभी फायदा कम और नुकसान ज्यादा होगा। भाजपा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास के मंत्र पर काम करती रहेगी। बाबा साहेब अंबेडकर जी की जयंती पर मिले ऐतिहासिक जनसमर्थन से सपा का हाजमा खराब हो चुका है।

मौर्य ने कहा, इनके फर्जी पीडीए का गुब्बारा भी फूट चुका है। कुछ का साथ, परिवार और गुंडो के विकास का फार्मूला ही सपा को 'समाप्तवादी पार्टी' बनाने के लिए पर्याप्त है। सपा और सैफई खानदान को गरीबों, पिछड़ों और दलितों का विकास कभी रास नहीं आएगा। भाजपा ही वर्तमान, भाजपा ही भविष्य। 2027 में 2017 दोहराएंगे। तीसरी बार उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार।

मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कंगना को बताया 'बड़ी बहन'

शिमला/भाषा। हिमाचल प्रदेश सरकार में मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने अपनी धुर विरोधी कंगना रनौत को 'बड़ी बहन' करार दिया। उन्होंने मंडी से लोकसभा सदस्य कंगना को विकास कार्यों के लिए केंद्रीय निधि लाने को कहा और उन्हें राज्य सरकार की ओर से पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया।

पीडब्ल्यूडी और शहरी विकास मंत्री सिंह ने मंगलवार को कुल्लू में हिमाचल दिवस के अवसर पर आयोजित एक समारोह से इतर संवाददाताओं से बातचीत में भाजपा सांसद के लिए कहा, ''हम उनका सम्मान करते हैं। वह बड़ी बहन की तरह हैं।'' उन्होंने कहा, अब कंगना एक सांसद हैं और उन्हें केंद्र व सांसद निधि से धन प्राप्त करना चाहिए। हम उनके साथ खड़े हैं और इसमें कोई राजनीति नहीं है।

मंत्री ने कहा, उन्हें (कंगना को) हिमाचल प्रदेश में योगदान देना चाहिए। हम उनके साथ खड़े हैं और प्रशासन पूरी तरह से उनका समर्थन करेगा। सिंह और कंगना के बीच अतीत में कई बार जुबानी जंग देखने को मिली है, खासकर पिछले वर्ष हुए लोकसभा चुनावों के दौरान, जब दोनों मंडी सीट पर आमने-सामने थे।

सिंह ने कंगना रनौत को 'विवादों की रानी' करार दिया था, जबकि भाजपा सांसद (कंगना) ने राज्य सरकार में मंत्री को अप्रत्यक्ष रूप से 'छोटा पप्पू' कहा था।

मुझे गर्व है कि मैं वर्सेटाइल अभिनेत्री हूं : ईशा मालवीय

नई दिल्ली/एजेन्सी

फिल्म के साथ टेलीविजन और म्यूजिक वीडियो के लिए काम करने वाली अभिनेत्री ईशा मालवीय हर भूमिका को जुनून के साथ निभाती हैं। अभिनेत्री ने समाचार एजेंसी आईएएनएस से बात की। उन्होंने बताया कि स्क्रीन पर कोई भी किरदार निभाने में उन्हें खुशी मिलती है। ईशा ने कहा कि उन्हें गर्व है कि वह वर्सेटाइल अभिनेत्री हैं। इस बारे में पूछे जाने पर कि उन्हें काम के दौरान क्या मुश्किल लगता है, खुद से बिल्कुल अलग किरदार निभाना या अभिनेत्री से मिलता-जुलता किरदार निभाना, ईशा ने बताया, मुझे काम से एक अलग तरह की खुशी मिलती है और इससे मेरा आत्मविश्वास बढ़ता है। मुझे गर्व महसूस होता है कि मैं एक वर्सेटाइल अभिनेत्री हूं, जो कोई भी भूमिका निभा सकती है। मालवीय ने कहा, ईमानदारी से कहूं तो, किसी भी किरदार को निभाते समय मेरे मन में कभी दूसरे विचार नहीं आए। मैं बस काम पर फोकस करती हूं। 21 वर्षीय अभिनेत्री ने कहा कि इंडस्ट्री में उनसे बेहतर काम की अपेक्षाएं की जाती है। हालांकि, यह उनके लिए अच्छा है और वह इससे दबाव महसूस नहीं करती हैं। उन्होंने कहा, मैं काम को लेकर खुद पर प्रेशर नहीं लेती क्योंकि मेरा मानना है कि हम सभी को खुश नहीं कर सकते। इसलिए दूसरों के सामने कुछ साबित करने के लिए काम करना मेरा तरीका नहीं है। मैं अपने लिए काम करती हूं। मेरे लिए, एक स्पष्ट लक्ष्य होना बहुत जरूरी है। इसके बिना, कोई दिशा नहीं है। मैं हमेशा ध्यान में रखती हूं कि मैं क्या हासिल करना चाहती हूं, चाहे वह अगले 30 दिनों में हो, 30 महीनों में या फिर 30 सालों में। यही स्पष्टता मुझे आगे बढ़ने में मदद करती है। ईशा ने साल 2021 में टेलीविजन शो उड़ारियां से अभिनय की शुरुआत की थी, जिसमें उनके किरदार का नाम जैस्मीन रहता है। शो में उनके साथ अभिनेता अंकित गुप्ता और प्रियंका चाहर चौधरी भी मुख्य भूमिकाओं में थे। इसके बाद ईशा को साल 2023 में सलमान खान के होस्ट किए जाने वाले रियलिटी शो 'बिग बॉस' के 17वें सीजन में देखा गया। अभिनेत्री 'पांव की जुत्ती' म्यूजिक वीडियो के साथ ही गौहर खान स्टारर शो 'लवली लोला' में भी काम कर चुकी हैं।

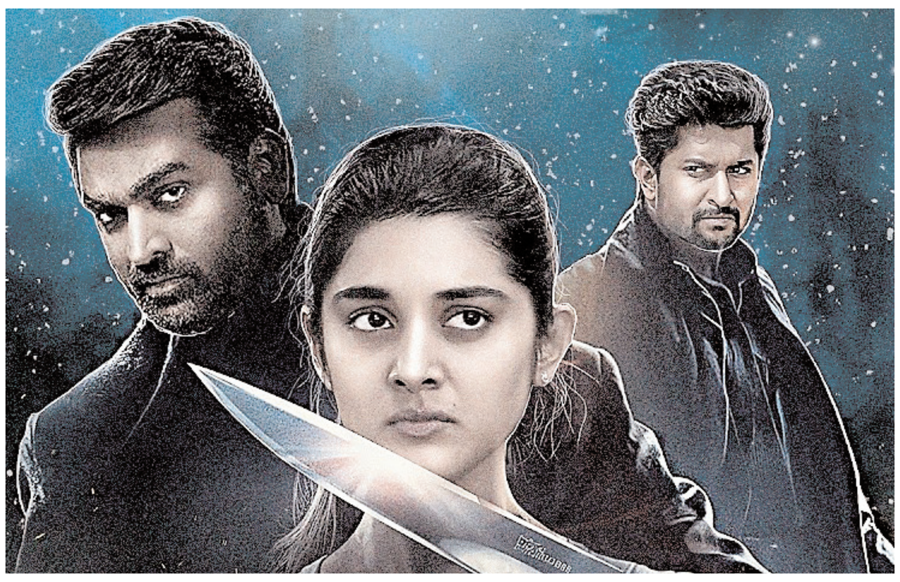

नानी की फिल्म 'हिट: द थर्ड केस' का ट्रेलर रिलीज

मुंबई/एजेन्सी

नेचुरल स्टार नानी की आने वाली फिल्म 'हिट: द थर्ड केस' का ट्रेलर रिलीज हो गया है। सैलेश कोलानू के निर्देशन में बनी फिल्म 'हिट: द थर्ड केस' के ट्रेलर में नानी खूब एक्शन करते नजर आ रहे हैं। फिल्म 'हिट: द थर्ड केस' में नानी एक सख्त पुलिस अधिकारी की भूमिका में हैं, जिसका नाम अर्जुन सरकार है। शुरुआत से ही ट्रेलर एक तेज़, थ्रिल से भरपूर माहौल सेट करता है, जहां नानी का किरदार अर्जुन सरकार सामने आता है। उसका एक ही उसूल है,एक अपराधी की दो ही मंज़िलें होती हैं। एक 10 फुट की जेल या 6 फुट की क़ब्र। कहानी शुरू होती है नौ महीने की बच्ची के अपहरण से। परेशान मां से जानकारी मिलने के बाद अर्जुन इस केस की कमान संभालता है और एक कड़वी सच्चाई से भरी अपराधी दुनिया में प्रवेश कर जाता है। न्याय की राह पर वो किसी भी हद तक जाने को तैयार है। इस फिल्म में नानी के साथ श्रीनिधि शेट्टी मुख्य भूमिका में हैं। यह फिल्म इस साल एक मई को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। इस फिल्म का निर्माण वॉल पोस्टर सिनेमा और यूनिनस प्रोडक्शंस ने किया है। एडवाइज मूवीज़ की ओर से हिंदी रिलीज़ को आदित्य भाटिया प्रस्तुत कर रहे हैं, और जय विराट्रा एंटरटेनमेंट लिमिटेड द्वारा हिंदी वितरण किया जा रहा है।

सलमान खान को जान से मारने की धमकी देने वाला शख्स गुजरात में पाया गया, निकला मानसिक रोगी

मुंबई/एजेन्सी

अभिनेता सलमान खान को जान से मारने की धमकी देने वाला शख्स गुजरात के वडोदरा जिले के वाघोडिया तालुका का निवासी निकला है। पुलिस के अनुसार धमकी देने वाला शख्स मानसिक रोगी है और उसे पूछताछ के लिए नोटिस भेजा गया है। एफआईआर दर्ज होने के 24 घंटे के भीतर पुलिस ने संदेश भेजने वाले शख्स को वडोदरा से खोज निकाला है। पुलिस ने बताया कि वडोदरा के वाघोडिया तालुका के एक गांव के निवासी 26 वर्षीय व्यक्ति का नाम मयंक पांड्या है, जो मानसिक रोगी है। उल्लेखनीय है कि सोमवार को वर्ली में परिवहन विभाग के नंबर पर धमकी भेजी गई, जिसमें अज्ञात शख्स ने अभिनेता को जान से मारने के साथ ही उनकी कार को भी बम से उड़ाने की बात कही थी। अभिनेता को धमकी मिलने के बाद वर्ली पुलिस स्टेशन में अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज किया गया और अभिनेता के गैलेक्सी अपार्टमेंट की सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है।

वडोदरा जिला पुलिस एसपी रोहन आनंद ने बताया, तकनीकी खुफिया जानकारी का इस्तेमाल करते हुए हमने मयंक पांड्या को उसके घर से ट्रैक किया। चूंकि वह मानसिक बीमारी का इलाज करा रहा है, इसलिए हमने उसे नोटिस भेजा है और जांच में शामिल होने को कहा है।

हमने मयंक पांड्या के मोबाइल फोन और व्यवहार पर नजर रखी तो जांच में पाया कि वह मानसिक रूप से बहुत स्वस्थ नहीं है और उपचार करवा रहा है। वह सोशल मीडिया पर एक्टिव रहता है और लोकप्रियता पाने की उसकी चाह है। इसके लिए उसने यह काम किया। मुंबई पुलिस ने पूछताछ के लिए समन भेज दिया है। गौरतलब है कि सलमान खान को पहले भी कई बार धमकी मिल चुकी है। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में गिरफ्तार आरोपियों ने पूछताछ के दौरान खुलासा किया था कि उनकी हिट लिस्ट में सलमान खान भी थे। लॉरेंस बिश्नोई गिरोह से जुड़े शूटर्स मुंबई में सलमान खान के गैलेक्सी अपार्टमेंट पर कई बार रेकी कर चुके थे। हालांकि, कड़ी सुरक्षा की वजह से वे अपने मकसद में नाकाम रहे। पिछले साल अप्रैल में सलमान खान के घर 5 राउंड फायरिंग की गई थी, जिसके कुछ महीने बाद सलमान के करीबी और एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या भी कर दी गई थी। लॉरेंस बिश्नोई ने एक टीवी इंटरव्यू में कहा था कि उसके जीवन का एकमात्र लक्ष्य सलमान खान को जान से मारना है। इससे पहले मुंबई पुलिस ने पिछले साल 12 नवंबर को सलमान खान को धमकी भरे मैसेज भेजने के आरोप में 24 वर्षीय एक व्यक्ति को कर्नाटक से गिरफ्तार किया था। पुलिस ने बताया था कि आरोपी का नाम सोहेल पाशा है। पिछले साल सलमान खान के घर के बाहर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। सलमान खान की उस बालकनी पर खास तौर पर बुलेट प्रूफ ग्लास लगाया गया, जहां से वह अपने प्रशंसकों का अभिवादन करते हैं। गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर भी हाई सिक्योरिटी तैनात की गई है।

मुलाकात

अभिनेता अक्षय कुमार ने मंगलवार को नई दिल्ली में दिल्ली सचिवालय में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और दिल्ली के मंत्रियों मनजिंदर सिंह सिरसा, कपिल मिश्रा और आशीष सूद से मुलाकात की।

गोपीचंद मलिनेनी के साथ 'हार्ट ऑफ जाट लैंड' पहुंचे रणदीप हुड्डा

मुंबई/एजेन्सी

बॉलीवुड अभिनेता रणदीप हुड्डा हाल ही में अपनी फिल्म जाट के निर्देशक गोपीचंद मलिनेनी के साथ रोहतक स्थित अपने पैतृक गांव पहुंचे। रणदीप हुड्डा इन दिनों फिल्म 'जाट' को लेकर चर्चा में हैं। गोपीचंद मलिनेनी निर्देशित फिल्म 'जाट' 10 अप्रैल को सिनेमाघरों में रिलीज हुई है। इस फिल्म में रणदीप ने खलनायक राणातुंगा का किरदार निभाया है, जिसे काफी पसंद किया जा रहा है। फिल्म जाट चार दिनों में भारतीय बाजार में 40 करोड़ की कमाई कर चुकी है। इस बीच रणदीप निर्देशक गोपीचंद मलिनेनी के साथ वैशाखी के अवसर पर रोहतक स्थित अपने पैतृक गांव पहुंचे, जिसे उन्होंने 'हार्ट ऑफ जाट लैंड' बताया। रणदीप हुड्डा चंडीगढ़ के एक स्थानीय सिनेमाघर में भी अचानक से पहुंचे और प्रशंसकों को चौंका दिया। रणदीप हुड्डा ने इंस्टाग्राम पर तस्वीरों को शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा, अंतरराष्ट्रीय जाट दिवस पर मैं अपने रोहतक स्थित पैतृक गांव 'हार्ट ऑफ जाट लैण्ड' पहुंचा। मेरे साथ मेरे भाई, निर्देशक गोपीचंद भी इस सफर में शामिल हुए। हमने अपने काका के घर पर बना स्वादिष्ट हरियाणवी भोजन और चूरमा खाया। रणदीप ने कहा, यहां सिनेमाघरों में 'जाट' देखने के लिए भरे सिनेमाघरों को देखने से बेहतर और क्या हो सकता है! जहां दर्शक सीटी और ताली के साथ ढेर सारा प्यार बरसा रहे हों। फिल्म जाट में सनी देओल, रणदीप हुड्डा, विनीत कुमार सिंह, सैयामी खेर और रेजिना कैसेंड्रा अहम भूमिकाओं में हैं। इस फिल्म का निर्माण मायथ्री मूवी मेकर्स और पीपल मीडिया फैक्टरी के सहयोग से किया गया है।

सेलिना ने सौरव गांगुली से कहा, 'फिर जन्म हुआ तो भीमराव अंबेडकर बनना चाहूंगी'

मुंबई/एजेन्सी

संविधान निर्माता बाबासाहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती के अवसर पर अभिनेत्री सेलिना जेटली ने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। सेलिना ने एक वीडियो भी शेयर किया, जिसमें वह पूर्व क्रिकेटर सौरव गांगुली के एक प्रश्न का जवाब देते हुए कहती नजर आईं फिर जन्म हुआ तो भीमराव अंबेडकर बनना चाहूंगी। सोमवार को भारतीय संविधान के प्रमुख निर्माता डॉ. भीमराव रामजी अंबेडकर की 135वीं जयंती है। इंस्टाग्राम पर मिस इंडिया यूनिवर्स से जुड़े एक वीडियो को शेयर करते हुए सेलिना ने बताया कि उनसे कौन से प्रश्न पूछे गए थे और उन्होंने क्या जवाब दिया था। इंस्टाग्राम पर वीडियो को शेयर करते हुए सेलिना ने कैप्शन में लिखा, आज अंबेडकर जयंती है। भीमराव रामजी अंबेडकर (14 अप्रैल 1891 - 6 दिसंबर 1956) की विरासत को याद करते हुए मेरे दिवंगत फौजी पिता और माता ने मुझे डॉ. भीमराव रामजी अंबेडकर की जन्मभूमि से जुड़ी प्रेम की विरासत का तोहफा देते हुए एमएचओडब्ल्यू (मध्य प्रदेश में स्थित डॉ. अंबेडकर नगर) को अपने घर के रूप में चुना था। उनके जरिए मैं एक ऐसे व्यक्ति की यात्रा से जुड़ सकी, जिसने देश और मुझे दोनों को बदल दिया...। वहीं, वीडियो में भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली को सेलिना से यह सवाल पूछते हुए देखा जा सकता है, यदि आप दोबारा जन्म लें, तो आप किस रूप में जन्म लेना चाहेंगी और क्यों? इस पर जेटली जवाब देती नजर आईं, मैं एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जन्म लेना चाहूंगी, जिसकी मैं बहुत प्रशंसा करती हूं और वह कोई और नहीं, बल्कि डॉ. भीमराव अंबेडकर हैं। मैं आपको बता दूं कि ऐसा क्यों है, क्योंकि मैं उनके ज्ञान, उनके दर्शन, उनके सामाजिक सुधारों और भारत की जाति व्यवस्था को खत्म करने तथा भारत का संविधान लिखने वाले व्यक्ति बनने के लिए उनकी प्रशंसा करती हूं।

RNI No. 58061/93. Regn No.:
RNP/KA/BGS/2050/2018-2020
Posted at Bengaluru PSO
Mysore Road Bengaluru-560 026.

अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक संगठन प्रजापिता ब्रह्माकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय द्वारा शहर के प्रकाश भवन में आयोजित तीन दिवसीय ग्रीष्मकालीन शिविर के उद्घाटन के मौके पर राजयोगिनी ब्रह्माकुमारी दानेश्वरीजी ने कहा कि गर्मी की छुट्टियां बच्चों के लिए तरोताजा महसूस करने का एक मंच होना चाहिए।

स्थानकवासी जैन महासंघ के पदाधिकारियों ने साध्वीद्वय के दर्शन किए

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

बेंगलूरु। श्वेतांबर स्थानकवासी जैन महासंघ बेंगलूरु के अध्यक्ष डा.भीकमचंद सकलेचा के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने मंगलवार को कम्मनहल्ली स्थानक में विराजित साध्वीश्री आगमश्रीजी एवं धैर्यश्रीजी के दर्शन कर स्वास्थ्य की सुख साता पूछी। महासंघ के महामंत्री अभयकुमार बांठिया ने धैर्यश्रीजी के जैन यूनिवर्सिटी से जैनलॉजी में पढ़ाई के बारे में जानकारी प्राप्त की। ज्ञातव्य है कि साध्वीश्री धैर्यश्रीजी जैनालॉजी में एमए की पढ़ाई कर ही हैं। वे पांडुलिपि और अन्य धर्म पर शोध विषय के अलावा भक्तामर स्तोत्र की महिमा पर भी निबंध लिख रही हैं। महासंघ के कोषाध्यक्ष हस्तीमल बाफना ने बताया कि साध्वीद्वय उदयनगर में ओली संपन्न कराकर कम्मनहल्ली आई हैं, आगामी जून माह में उनकी परीक्षा है जिसकी वे तैयारी कर रही है। अध्यक्ष भीकमचंद सकलेचा ने परीक्षा के लिए अग्रिम शुभकामनाएं दी। कम्मनहल्ली संघ के अध्यक्ष विजयराज चुतर एवं कोषाध्यक्ष सुधीर सिंघवी ने प्रतिनिधिमंडल का स्वागत किया।

बच्चों की जीवनशैली में बदलाव लाएगा ग्रीष्मकालीन शिविर : ब्रह्माकुमारी दानेश्वरी

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

चामराजनगर। अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक संगठन प्रजापिता ब्रह्माकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय द्वारा शहर के प्रकाश भवन में आयोजित तीन दिवसीय ग्रीष्मकालीन शिविर के उद्घाटन के मौके पर राजयोगिनी ब्रह्माकुमारी दानेश्वरीजी ने कहा कि गर्मी की छुट्टियां बच्चों के लिए तरोताजा महसूस करने का एक मंच होना चाहिए। उन्होंने कहा कि गर्मी की छुट्टियां बच्चों की मानसिक शक्ति, बुद्धिमत्ता और सीखने में रुचि बढ़ाने का एक शानदार तरीका है। ईश्वर की सृष्टि में सबसे सुन्दर फूल बच्चे हैं। बच्चों का जीवन बहुत सुन्दर है। बच्चे भगवान के समान होते हैं, उनका मन बहुत शुद्ध और निष्कलंक होता है। हर बच्चे में प्रतिभा होती है। प्रतिभा एक अमूल्य खजाना है। उन्होंने कहा कि प्रतिभा को एक मंच की जरूरत है, तभी वह आगे आ सकती है। इस मौके पर उपस्थित पर्यावरणविद् सीएम वेंकटेश ने कहा कि जहां भी बच्चे इकट्ठा होते हैं, वहां पेड़-पौधे लगाना मेरा शौक है। पेड़-पौधे उगाएं, पारिस्थितिकी तंत्र बचाएं, यही सबका आदर्श वाक्य होना चाहिए।

जिला पंचायत के जिला प्रशिक्षण समन्वयक टीजे सुरेश ने कहा कि चूंकि यह शिविर बच्चों को उनकी छिपी प्रतिभा को उजागर करने में मदद करता है, इसलिए बच्चों को इस शिविर में खुलकर अपनी छिपी प्रतिभा को सामने लाने का प्रयास करना चाहिए। ग्रीष्मकालीन शिविर बच्चों के नवोदित मन को फूलों की तरह खिलने में मदद करेगा। चूंकि आज के बच्चे कल के महान भारत के निर्माता हैं, इसलिए इससे बच्चों को नए विचार सीखने और उपलब्धियां हासिल करने में मदद मिलेगी।

स्क्रीनिंग

दल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी, अभिनेता अक्षय कुमार, आर. माधवन और अन्य लोग मंगलवार को नई दिल्ली में फिल्म 'केसरी चैप्टर 2' की स्क्रीनिंग में शामिल हुए।

व्यावहारिक विकास के साथ आध्यात्मिक विकास होना भी जरूरी: साध्वीश्री संयमलता

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

बेंगलूरु। तेरापंथ सभा गांधीनगर के तत्वावधान में साध्वीश्री संयमलताजी के सान्निध्य में इंदिरानगर स्थित भूपेंद्र मुथा के निवास पर श्रावक संगोष्ठी का आयोजन रखा गया। इस मौके पर सभा को संबोधित करते हुए साध्वीश्री संयमलताजी ने कहा कि तेरापंथ जैसा महान धर्मसंघ हमें मिला है। आचार्यश्री महाश्रमणजी समय समय पर हम सभी को अनेकों आध्यात्मिक प्रेरणाएं प्रदान करते हैं। हमें उनका अनुसरण करना चाहिए। साध्वीश्री ने कहा कि व्यावहारिक जीवन के साथ हमारा आध्यात्मिक विकास होता रहे इस दृष्टि में भी जागरूकता रखनी है। साध्वी मार्धवश्रीजी ने कहा कि आधुनिकता एवं वैज्ञानिकता के इस युग में आध्यात्मिकता का समावेश ही पूर्ण विकास दे सकता है। भीतर की शांति ही आनंद की अनुभूति करवा सकती है। उन्होंने अनेकों उदाहरणों तथा रोचक तथ्यों के आधार पर प्रेरणा दी। साध्वीश्री मनीषाश्रीजी एवं रौनक प्रभाजी ने गीतिका का संगान किया ।

मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित बहादुर सेठिया ने मधुर गीतिका के साथ प्रेरणात्मक भाव रखे।

तेरापंथ सभा गांधीनगर के मंत्री विनोद छाजेड़ ने कहा कि साध्वीश्री क्षेत्रों की अच्छी सार सम्भाल के साथ धर्म प्रभावना करवा रही हैं। सभा के उपाध्यक्ष विनय बैद ने आध्यात्मिक प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में भाग लेने वाले बच्चों, श्रावक श्राविकाओं का उत्साह बढ़ाया। वरिष्ठ श्रावक भूपेंद्र मुथा ने साध्वीश्रीजी के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित की।इस अवसर पर यशवंतपुर, राजाजीनगर, मागडी रोड, विजयनगर, हनुमंतनगर, चामराजपेट, जीवनहल्ली, डमलूर, शांतिनगर, श्रीरामपुरम, कोल्स पार्क आदि अनेक क्षेत्रों से श्रावक श्राविकाएं उपस्थित थे। संदीप मुथा ने स्वागत किया। संचालन नवनीत मुथा ने किया और राजेन्द्र बैद ने धन्यवाद दिया।

टीटीवी, पनीरसेल्वम को सीट देने पर भाजपा, अन्नाद्रमुक मिलकर विचार करेंगी : नैनार

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

चेन्नई। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की तमिलनाडु इकाई के अध्यक्ष नैनार नागेंद्रन ने कहा है कि 2026 के तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के लिए टीटीवी दिनाकरन के नेतृत्व वाली अम्मा मक्कलमुनेत्र कषगम (एएमएमके) और पूर्व मुख्यमंत्री ओ पनीरसेल्वम (ओपीएस) को सीट बंटवारे के सवाल पर अन्नाद्रमुक और उनकी पार्टी का नेतृत्व मिलकर विचार करेगा। नागेंद्रन से जब पूछा गया कि भाजपा की तमिलनाडु इकाई के प्रमुख के तौर पर 12 अप्रैल को पदभार ग्रहण करने के बाद उन्होंने अपनी टिप्पणी में कहा था कि वह सिर्फ हवा के झोंके की तरह हैं, जबकि के. अन्नामलाई तूफान की तरह काम करते हैं और इस पृष्ठभूमि में उन्होंने सत्तारूढ़ द्रविड़ मुनेत्र कषगम (द्रमुक) से मुकाबला करने की किस प्रकार योजना बनाई है, नागेंद्रन ने कहा कि जिन मुद्दों पर चर्चा या बहस की आवश्यकता है, उन्हें उठाया जाना चाहिए और इसमें कोई संदेह नहीं है।

नवनिर्वाचित भाजपा नेता ने 'पीटीआई-भाषा' को दिए एक साक्षात्कार में कहा कि लोगों को प्रभावित करने वाले मुद्दों को उन्होंने हमेशा विधानसभा में भी उठाया है और वह ऐसा करना जारी रखेंगे। 64 वर्षीय नागेंद्रन 234 सदस्यीय तमिलनाडु विधानसभा में दक्षिणी तिरुनेलवेली विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। सदन में उनकी मृदुभाषी वक्ता की छवि और साथ ही इस बारे में पूछे जाने पर कि अपनी पार्टी के एजेंडे को वह कैसे आगे बढ़ाएंगे, खासकर जब उनके पूर्ववर्ती अन्नामलाई अपनी मुखर शैली के लिए लोकप्रिय रहे हैं, नागेंद्रन ने कहा कि वह विधानसभा में भाजपा की नीतियों को स्पष्ट करने में कभी विफल नहीं हुए हैं। उन्होंने साथ ही कहा कि पार्टी के लक्ष्यों को जोर-शोर से उठाते समय उनकी 'नरम छवि'' कभी कोई मुद्दा नहीं रही। उन्होंने यह भी कहा कि अन्नामलाई ने राज्य में पार्टी को अच्छी तरह से विकसित किया है और उनकी अनूठी कार्यशैली सराहनीय है।

यह पूछे जाने पर कि क्या 'ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कषगम' (अन्नाद्रमुक) द्वारा उनकी पार्टी को आवंटित सीट में से दिनाकरन (टीटीवी) के नेतृत्व वाली एएमएमके और पनीरसेल्वम को सीट आवंटित करने के लिए भाजपा आगे आएगी, नागेंद्रन ने पीटीआई-भाषा' से कहा, अभी (अन्नाद्रमुक के साथ) तो सिर्फ गठबंधन बना है। उन्होंने कहा, सीट बंटवारे पर फैसला हमारा संसदीय बोर्ड और आलाकमान करेगा। अन्नाद्रमुक भी इस संबंध में एक समिति गठित कर सकती है और हमारा संसदीय बोर्ड इस पर विचार-विमर्श करेगा।

एडप्पाडी के. पलानीस्वामी के नेतृत्व वाली अन्नाद्रमुक 11 अप्रैल को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) में वापस आ गई, जिन्होंने घोषणा की थी कि गठबंधन पलानीस्वामी के नेतृत्व में 2026 का राज्य विधानसभा चुनाव लड़ेगा। नागेंद्रन के पूर्ववर्ती के. अन्नामलाई ने अन्नाद्रमुक के राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) में फिर से शामिल होने से कुछ समय पहले कहा था कि दिनाकरन जैसे सहयोगियों को ''निराश'' नहीं किया जा सकता जो पार्टी के पीछे मजबूती से खड़े हैं।

स्वागत

चेन्नई में मंगलवारको सीएम प्रधान कार्यालय में तौहीद जमात ऑफ इंडिया के अध्यक्ष ए मुहम्मद सिद्दीकी, उपाध्यक्ष आई मुहम्मद मुनीर, महासचिव ए मुहम्मद शिबली, उप महासचिव तकवा एम बोइटिन कोषाध्यक्ष राय बर्डव्स ने मुख्यमंत्री एमके स्टालिन से मुलाकात की। और उन्हें केंद्र सरकार के वक्फ संशोधन विधेयक को पूरी तरह से वापस लेने का आग्रह किया और तमिलनाडु विधानमंडल में एक अलग प्रस्ताव पारित करने के लिए सरकार को धन्यवाद दिया। इस मौके पर हिंदू धार्मिक बंदोबस्ती मंत्री शेखरबाबू भी उपस्थित थे।

चेन्नई में 15 अप्रैल को तमिलनाडु विधान सभा में नियम संख्या 110 के तहत मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने घोषणा की कि राज्यों के उचित अधिकारों की रक्षा और केंद्र और राज्य सरकारों के बीच संबंधों को बेहतर बनाने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है।

मुख्यमंत्री स्टालिन ने राज्य की स्वायत्तता पर उच्च स्तरीय समिति की घोषणा की

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

चेन्नई। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन ने मंगलवार को राज्य की स्वायत्तता पर उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक समिति गठित करने की घोषणा के साथ ही आरोप लगाया कि केंद्र द्वारा राज्यों के अधिकारों को धीरे-धीरे छीना जा रहा है। ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कषगम (अन्नाद्रमुक) ने इस घोषणा को लेकर मुख्यमंत्री की आलोचना की और पूछा कि उनकी द्रविड़ मुनेत्र कषगम (द्रमुक) इतने सालों तक क्या कर रही थी। अन्नाद्रमुक ने आरोप लगाया कि इस कदम का उद्देश्य राज्य सरकार की विफलताओं से जनता का ध्यान भटकाना है।

केंद्र में भाजपा के नेतृत्व वाली राजग सरकार पर हमला करते हुए स्टालिन ने कहा कि उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश कुरियन जोसेफ की अध्यक्षता वाली उच्च स्तरीय समिति राज्य की स्वायत्तता सुनिश्चित करने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों के बीच संबंधों की विस्तार से जांच करेगी। यह समिति जनवरी 2026 में अपनी अंतरिम रिपोर्ट पेश करेगी। सिफारिशों के साथ अंतिम रिपोर्ट दो साल में पेश की जाएगी। समिति में पूर्व नौकरशाह अशोक वर्धन शेट्टी और राज्य योजना आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष एम नागनाथन सदस्य होंगे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि यह समिति कानून के अनुसार, उन विषयों को स्थानांतरित करने के लिए अध्ययन करेगी जो पहले राज्य सूची में थे लेकिन समवर्ती सूची में शामिल कर दिए गए थे। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (नीट) राज्यों के अधिकार क्षेत्र से बाहर है।

स्टालिन ने तमिलनाडु विधानसभा में कहा, हम केवल तमिलनाडु के कल्याण को ध्यान में रखते हुए सत्ता और धन के हस्तांतरण पर जोर नहीं दे रहे हैं, बल्कि गुजरात से लेकर पूर्वोत्तर भागों और कश्मीर से लेकर केरल तक फैले देश के विशाल क्षेत्र के लोगों के हितों को ध्यान में रख रहे हैं।

बैठक

दक्षिण भारत राष्ट्रमत

झारखंड के मुख्यमंत्री और नवनिर्वाचित झामुमो अध्यक्ष हेमंत सोरेन, झामुमो संस्थापक शिबू सोरेन, उपाध्यक्ष रूपी सोरेन और विधायक कल्पना मुर्मू सोरेन के साथ मंगलवार को रांची के खेलगांव में मेगा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के ताना भगत इंडोर स्टेडियम में 13वीं कार्यकारी समिति की बैठक में भाग लेते हुए।

तिरुमला बोर्ड के सदस्य ने गायों की मौत के मामले में पूर्व अध्यक्ष के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

चेन्नई/तिरुपति। तिरुमला तिरुपति देवस्थानम (टीटीडी) बोर्ड के सदस्य जी भानु प्रकाश रेड्डी ने गायों की मौत के संबंध में अपने आरोपों से मंदिर प्रबंधन को कथित रूप से ''बदनाम'' करने के लिए पूर्व अध्यक्ष बी करुणाकर रेड्डी के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। हालांकि, करुणाकर ने गायों की मौत की गहन जांच की मांग करते हुए कहा कि वह अपने बयान पर कायम हैं, क्योंकि उन्होंने कुछ भी ''गलत नहीं'' किया। करुणाकर ने 11 अप्रैल को संवाददाता सम्मेलन में आरोप लगाया कि टीटीडी गोशाला में बड़ी संख्या में गायें मर रही हैं। उन्होंने दावा किया कि पिछले तीन महीनों में ''लापरवाही'' के कारण 100 गायों की मौत हुई है।

भानु प्रकाश ने शिकायत में कहा, काल्पनिक आधार पर लगाए गए बेबुनियाद आरोप निश्चित रूप से मानहानि के बराबर हैं और वे आम जनता की नजर में मंदिर और उसके प्रशासन की प्रतिष्ठा को कम करते हैं। शिकायत को मंगलवार को 'पीटीआई-भाषा' के साथ साझा किया गया। शिकायत में करुणाकर के दावों का खंडन किया गया है।

भानु प्रकाश ने कहा कि ये आरोप समाचारपत्रों और सोशल मीडिया पर सामने आए हैं, जिससे श्रद्धालुओं की भावनाएं आहत हुई हैं और उनकी आस्था को चोट पहुंची है। इसके मद्देनजर, भानु प्रकाश ने पुलिस अधीक्षक (एसपी) से पूर्व टीटीडी अध्यक्ष और ऐसे दावे करने वाले अन्य लोगों के खिलाफ उचित कार्रवाई करने का अनुरोध किया है। इस बीच, करुणाकर ने गायों की मौतों की गहन जांच की मांग दोहराते हुए कहा है कि वह अपने बयान पर कायम हैं।

Printed& Published by Devendra Sharma on behalf of owners M/s. New Media Company, 6/4 , Ist floor, Cantonment station road, Bengaluru-51 and printed at Dinasudar Printing Division, 116, Queens Road, Bengaluru-560052. **Editor-Shreekant Parashar**,
(*Responsible for selection of news under PRB Act.) Reproduction of any matter from this newspaper in whole or in part or any such manner without prior written permission from the publisher is strictly prohibited and punishable by law.
HEAD OFFICE : DAKSHIN BHARAT RASHTRAMAT, New Media Company, 6/4, Cantonment Station Road, Bangalore 560051. Editorial : 080-25363030 / 9945488003. For Advertisement : 9945488002 - email : news@dakshinbharat.com